• आदर्श ग्राम : फिक्रमंद नहीं सांसद • क्या पटरी पर लौटेगी अर्थव्यवस्था...?

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

कमजोर न हों जड़ें

वर्ष 18, अंक-8 | 16 से 31 जनवरी 2020 | मूल्य 25 रूपये

अबकी बार जुगाड़ू महापौर

R.N.I NO.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/ 2015-17

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

पाक्षिक अक्स

www.akshnews.com

लॉगऑन करें

www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल
फोन:0755-4017788,2575777

D-17008

इस अंक में

प्रशासनिक

9 | क्या लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली...?

मप्र की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इस समय यह सवाल चर्चा में बना हुआ है कि क्या प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश में पहली बार लखनऊ व गौतमबुद्धनगर...

राजपथ

10-11 | फिक्रमंद नहीं सांसद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के कुछ महीनों के भीतर ही सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान किया था। इसके तहत करीब 2500 गांवों की कायापलट करने का लक्ष्य रखा गया था। योजना के तहत 2014 से 2019...

मंथन

14 | कमजोर न हों जड़ें

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जोर अब शाखाओं को बढ़ाने पर रहेगा। युवा, महिलाओं, छात्रों को जोड़ने के साथ वनवासी परिवार में संघ का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, केरल, पश्चिम बंगाल और...

खेती किसानी

15 | राहत पर भेदभाव

सीजन 2019 में देश के कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से खेती के साथ ही जानमाल की हुए भारी नुकसान की भरपाई में भी केंद्र सरकार मप्र से भेदभाव कर रही है। प्रदेश में 55 लाख किसानों की 60 लाख हेक्टेयर खरीफ की फसल खराब हुई थी।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र में वक्त है बदलाव के नारे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस ने अपने एक साल के कार्यकाल में कई बदलाव किए हैं। लेकिन सबसे अधिक विवाद नगरीय निकायों में महापौर या अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने को लेकर हुआ है। मामला राज्यपाल से लेकर हाईकोर्ट तक सुर्खियों में बना रहा। अंततः सरकार के पक्ष में निर्णय हुआ है कि नगरीय निकायों में अब महापौर या अध्यक्ष को जनता नहीं बल्कि पार्षद चुनेंगे।

30-31

38

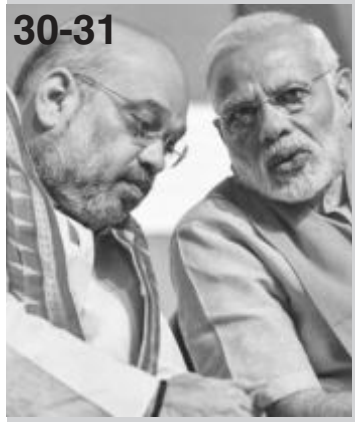

40

44

सियासत

32-33 | विवादों में इलेक्टोरल बॉन्ड

देश के राजनीतिक गलियारों में इलेक्टोरल (चुनावी) बॉन्ड का नाम साल 2017 से खूब चर्चा में है। मोदी सरकार ने राजनीतिक चंदे की स्वच्छता व पारदर्शिता के लिए साल 2017 के बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड लागू किया था। इसके बाद जनवरी 2018 में पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए।

दिल्ली दरबार

34 | दिल्ली का दांव

दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 8 फरवरी को यहां वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। पिछले दो विधानसभा चुनाव यहां आम आदमी पार्टी के पक्ष में एकतरफा या उसके और बीजेपी के बीच आमने-सामने के रहे हैं। इस बार कांग्रेस मुकाबले को त्रिकोणीय...

राजस्थान

37 | मौत का अस्पताल

राजस्थान का कोटा शहर कभी औद्योगिक नगरी के नाम से मशहूर था। उद्योगों के बंद होने के बाद यह शहर देश में कोचिंग संस्थानों का सबसे बड़ा हब बन गया। मगर पढ़ाई के तनाव में यहां बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों के लगातार आत्महत्या करने की घटनाओं...

6-7 अंदर की बात
41 विदेश
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 फिल्म
45 खेल
46 व्यंग्य

अपनी बात

अपनी–अपनी भारतीयता बनाने–बचाने की लड़ाई

बृज नारायण चकबस्त का शेर है-

मजा है अहद-ए-जवानी में सर पटकने का
लहू में फिर ये रवानी रहे न रहे

सर सिर पटकने का कोई वाजिब सबब तो हो। मप्र सहित देशभर में इन दिनों बिना सबब के ही राजनीतिक पार्टियां अपना सिर पटक रही हैं। इससे देश में जैसे आंदोलनों, जलसों और जुलूसों का मौसम आ गया है। उत्तर भारत की कड़कड़ाती ठंड को चुनौती देते हुए दिल्ली से अहमदाबाद-हैदराबाद-भोपाल तक अलग-अलग शहरों और विश्वविद्यालयों के युवा और छात्र कहीं नागरिकता संशोधन कानून, कहीं राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, कहीं छात्रों की पिटाई और कहीं फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर हैं। बेशक दिल्ली में होने और अपने शानदार एकैडमिक इतिहास के चलते जेएनयू इन आंदोलनों की नब्ज बना हुआ है। अचानक हम पा रहे हैं कि सारे मुद्दों के बीच जेएनयू का समर्थन या विरोध सबसे अहम मुद्दा बनता जा रहा है। दीपिका पादुकोण जेएनयू जाकर छात्रों के साथ खड़ी भर होती हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया उनके समर्थन और विरोध में बंट जाती है। कुछ लोग उनकी फिल्म **'छपाक'** इसलिए देखना चाहते हैं कि उन्होंने जेएनयू के छात्रों के समर्थन में खड़े होकर अपने लोकतांत्रिक विवेक का परिचय दिया है और एक तरह से सरकार के साथ खड़े जेएनयू प्रशासन का विरोध किया है जबकि कुछ लोग उनकी फिल्म के बहिष्कार पर आमादा हैं क्योंकि उन्होंने जेएनयू जाकर 'राष्ट्रवाद पर तेजाब फेंका' है। यहां तक कि केंद्र सरकार की कुछ प्रमोशनल योजनाओं से दीपिका पादुकोण को अलग किया जा रहा है। इन सबके बीच मप्र सरकार ने छपाक को टैक्स फ्री कर दिया है। सरकार के इस कदम से भाजपा को इस कदर मिर्ची लगी कि उसने कमलनाथ सरकार पर कई आरोप तो गढ़े ही, साथ ही फिल्म तान्हाजी को टैक्स फ्री करने की मांग करने लगे। यही नहीं भाजपा ने तो फिल्म तान्हाजी के टिकट मुफ्त में बांटने शुरू कर दिए, तो युवा कांग्रेस कई जगह छपाक के फ्री टिकट बांट रही है, वहीं उत्तरप्रदेश के कई सिनेमाघरों को सपा ने बुक करा लिया है। दरअसल, राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी भारतीयता बचाने की जुगत में लगी हुई हैं। और इसके लिए फिल्मों को हथियार बनाया जा रहा है। मप्र ही नहीं बल्कि भाजपा ने तो दीपिका की फिल्म छपाक का पूरे देश में विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस, सपा सहित कई विपक्षी दल समर्थन कर रहे हैं। समर्थन और विरोध की परस्पर टकराती इस राजनीति के बीच आंदोलन के जो मूल मुद्दे हैं- वे या तो खो गए हैं या फिर लगभग अप्रासंगिक हो चले हैं। हद तो यह है कि देश आर्थिक बदहाली के मुहाने पर खड़ा है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, युवा पीढ़ी अपने कर्त्तव्य से भटकती जा रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इसकी चिंता नहीं है। सब अपने आपको सबसे बड़ा भारतीय दिखाने में लगे हुए हैं। आलम यह है कि देश में शिक्षा, साहित्य, धर्म और सिनेमा को भी अलग-अलग विचारधाराओं में बांट दिया गया है। आज स्थिति यह है कि देश की आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई पर बोलने की बजाय राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही हैं। एक पार्टी को जो राष्ट्रवाद नजर आता है, वही दूसरी पार्टी को राष्ट्रविरोधी। इससे देश में बैर का भाव पनप रहा है। इसका प्रभाव युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है और इसी कारण देश के शिक्षण संस्थान आंदोलन का केंद्र बन गए हैं। युवाओं की आक्रामकता को भुनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ ही अलग-अलग विचारधाराओं के लोग भी सीमाएं पार कर रहे हैं।
इससे देश में अनैतिकता बढ़ती जा रही है, जो देश के लिए घातक है।

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 18, अंक 8, 16 से 31 जनवरी, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2015-17

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-
फोन : 011 25495021, 011 25494676
मुंबई : बी-1, 41 शिव पावर्ती चेम्बर प्लाट नंबर 106-110 सेक्टर-21
नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411
कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता
फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई,
मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर
मोबाइल - 094251 25096

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

हम सबसे स्वच्छ

स्वच्छता में देशभर में एक बार फिर इंदौर ने टॉप पर आ गया है। इंदौर के टॉप पर आने में नगर निगम के साथ-साथ इंदौरवासियों का भी योगदान है। देश के अन्य राज्यों के शहरों को भी इंदौर से सीखना चाहिए और अपने शहरों को स्वच्छ बनाना चाहिए।

● **सूरज वर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

बाघों की सुरक्षा पर सोचें

प्रदेश में बाघों की मौतें चिंता का विषय है। आए दिन बाघों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। प्रदेश सरकार को इस ओर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। वनों की सुरक्षा में सरकार को और अधिक ध्यान देना होगा। तभी कहीं जाकर प्रदेश में बाघों की मौतों पर अंकुश लगाया जा सकता है।

● **शिखा साहू,** भोपाल (म.प्र.)

देशवासी गुमराह है

सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने देशवासियों को गुमराह किया है। इस कानून से देश के किसी भी अल्पसंख्यक को कोई नुकसान नहीं होगा। लोगों को ध्यान देना होगा कि वे किसी के बहकावे में न आएं। इससे देश की संपत्ति को नुकसान होता है।

● **राहुल देशमुख,** जबलपुर (म.प्र.)

कैसे खरीदे प्याज?

प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपनी महा-अयुष्मान योजना में उच्च और मध्यमवर्गीय 48 लाख परिवार भी शामिल किए हैं जिनके बाद प्रदेश में महा-आयुष्मान योजना में 1.88 करोड़ लोग शामिल हो जाएंगे। इस प्रकार की योजनाएं प्रदेश के लोगों के लिए जरूरी हैं ताकि इस महंगाई के जमाने में स्वास्थ्य पर आने वाले भारी खर्च को कम किया जा सके और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का अधिकार संवैधानिक तरीके से मिल सके। मध्य प्रदेश की जनता को प्रदेश की कमलनाथ सरकार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महा-आयुष्मान योजना के रूप में राइट टू हेल्थ योजना लागू करके तोहफा देना चाहती है। उम्मीद है कि सरकार का ये कदम प्रदेश की जनता के लिए लाभदायक होगा।

● **दिनेश पुरोहित,** सीवा (म.प्र.)

छिड़ चुके हैं बगावत के सुर

महाराष्ट्र की तीन पहिए की सरकार में बगावत के सुर छिड़ना शुरू हो गए हैं। पहले इनकी सरकार के एक राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की हवा उड़ी, और अब कांग्रेस के कांग्रेस विधायक कैलाश गौरांतयाल ने भी मंत्री पद न दिए जाने को लेकर इस्तीफा देने की बात की है। आगे-आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल सरकार को महाराष्ट्र के विकास के लिए अच्छे कदम उठाने चाहिए। हम सभी को उम्मीद है कि गठबंधन की ये सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरेगी।

● **प्रणब कुमार,** पुणे (महाराष्ट्र)

ताकि किसान न हो परेशान

इस समय प्रदेश के किसानों की हालत बहुत खराब है। इस पर मिट्टी की बिगड़ी सेहत ने उनको और परेशानी में डाल दिया है। प्रदेश की कमलनाथ सरकार को कुछ ऐसा उपाय खोजना होगा कि जिससे किसान को परेशान न होना पड़े। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अब प्रदेश सरकार को ध्यान देना होगा। प्रदेश में यूरिया के संकट से निपटने के लिए भी कमलनाथ सरकार को ध्यान देना होगा।

● **बलवीर सिंह,** ग्वालियर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

दूसरे के विभाग की चिंता

पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार के मंत्रियों के कामकाज को लेकर कमाल का गोलमाल हो रहा है। भारत सरकार के जिस मंत्री को जो काम करना है उसे छोड़कर वह बाकी दूसरे काम कर रहा है। मंत्री अपने-अपने विभाग के कामकाज से नदारद हैं और दूसरे मंत्रालयों के कामकाज पर विशेषज्ञ टिप्पणी कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट से पहले उद्योगपतियों से चर्चा की और फिर उन्होंने देश के जाने-माने अर्थशास्त्रियों के साथ नीति आयोग में बैठक की। नीति आयोग की बैठक में देश के गृहमंत्री अमित शाह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दोनों शामिल हुए और पूरे मनोयोग से सारी बातें सुनीं। पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक से नदारद रहीं। इसी तरह जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू में छात्रों के साथ मारपीट का विवाद हुआ और पूरे देश में हंगामा मचा तो पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। ऐसे ही जेएनयू में नकाबपोश गुंडों के हमले में घायल हुई लड़कियों का हालचाल जानने में महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कोई रूचि नहीं दिखाई, लेकिन लगातार दो दिन उन्होंने इस बात पर बयान दिया कि दीपिका पादुकोण जेएनयू में क्यों गई थीं। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्री अपने विभाग पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे?

कांग्रेस का नया सेक्युलर चेहरा

कांग्रेस पार्टी में थोड़े समय पहले तक जो भूमिका मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह निभाते थे वह सक्रिय भूमिका अब लग रहा है कि शशि थरूर निभाने लगे हैं। यानि कांग्रेस का नया सेक्युलर चेहरा बनकर थरूर सामने आए हैं। संभवत: शशि थरूर इकलौते बड़े नेता हैं, जो नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अपने राज्य केरल में हुए विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। फिर वे दिल्ली के जामिया इलाके के शाहीन बाग में लगातार चल रहे आंदोलन में हिस्सा लेने गए और वहां उन्होंने भाषण भी दिया। वे कांग्रेस के इकलौते नेता हैं, जो जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गए और नकाबपोश गुंडों के हमले में घायल जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष से मुलाकात की। वैसे प्रियंका गांधी 5 जनवरी की रात हमले के तुरंत बाद एम्स गई थीं पर वे भी जेएनयू नहीं गईं। पहली बार करीब तीन साल पहले जब जेएनयू में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई हुई थी तब राहुल गांधी वहां गए थे पर इस बार वे भी वहां नहीं गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बनाई चार सदस्यीय जांच टीम के सदस्यों ने जरूर जेएनयू के छात्रों से मुलाकात की।

सियासी पैंतरे

बिहार की सियासत में फिर उथल-पुथल दिखने लगी है। सियासी हलकों में नीतीश के भावी पैतरों को लेकर अटकलें तेज हैं। वे दबाव बनाने की राजनीति में निपुण माने जाते हैं। तेजस्वी यादव भले उन्हें पलटू चाचा कहते हों पर उनके नेतृत्व में फिर विधानसभा चुनाव लड़ने की परिस्थिति बने तो चाचा-भतीजा फिर एक हो सकते हैं। बिहार में सीएए का जैसा जबर्दस्त विरोध हुआ, उसने नीतीश को चौकस किया है। तभी तो उन्हें ऐलान करना पड़ा कि वे अपने सूबे में एनआरसी लागू नहीं करेंगे। पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा की जमीन खिसकने और फिर झारखंड के चुनावी नतीजों ने नीतीश की बेचैनी तो बढ़ाई ही है। इस बीच कांग्रेस ने तो कह भी दिया है कि नीतीश साथ आना चाहें तो उनका स्वागत है। साफ है कि नीतीश एक तरफ तो अपने लिए नए गठबंधन का विकल्प खुला रखे हैं, दूसरी तरफ हालात का फायदा उठाते हुए भाजपा की बांह मरोड़ने के फेर में हैं। नहीं तो नीकु की सहमति और स्वीकृति के बिना पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर इतनी जुर्रत कैसे कर सकते हैं कि नीतीश के उपमुख्यमंत्री पर ही कटाक्ष कर बैठे। फिर प्रशांत किशोर ने भाजपा को आगाह किया कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वह जद (एकी) से बराबर की सीटों की उम्मीद न पाले।

गहलोत का जोश

सीएए पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आक्रामक तेवरों ने भाजपा खेमे में खलबली मचाई है। कानून के विरोध में निकली रैली का जयपुर में गहलोत ने खुद नेतृत्व किया। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। जबकि इसी सूबे के सीमाई इलाकों में सबसे ज्यादा शरणार्थी रह रहे हैं। कानून को अव्यवहारिक बता गहलोत ने लागू करने से साफ इनकार किया है। भाजपा खेमे में भी गुटबाजी है। वसुंधरा राजे ने समर्थन में जोश नहीं दिखाया। गहलोत जैसे तेवर भाजपा के सूबेदार सतीश पूनिया से लेकर केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल व कद्दावर नेता गुलाब चंद्र कटारिया कोई नेता नहीं दिखा पाया। नतीजतन आलाकमान को मोर्चा संभालना पड़ा है। जोधपुर में रैली की। गहलोत के आक्रामक तेवरों ने उनकी पार्टी में उत्साह का संचार किया है। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजों के बरक्स वे डंके की चोट पर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भाजपा का बिस्तर अब सारे देश से ही गोल होने वाला है।

तनातनी क्यों?

मोदी सरकार और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के बीच इन दिनों जबरदस्त तनातनी चल रही है। इस तनातनी के पीछे केंद्र सरकार का मंत्रालय की सभी सेवाओं को एक कॉडर में लाने का निर्णय है। दरअसल, सरकार ने रेल विभाग को चुस्त-दुरुस्त बनाने की नीयत से एक बड़ा निर्णय रेल मंत्रालय के अलग-अलग कॉडर को समाप्त कर केवल एक ही कॉडर रखने का फैसला लिया है। रेलवे के अफसरों में सरकार के इस निर्णय से भारी अफरा-तफरी मच गई है। वर्तमान में रेल मंत्रालय के भीतर आठ अलग-अलग संवर्ग हैं जिन्हें मिलाकर सरकार इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस नाम से एक कॉडर करने का निर्णय ले चुकी है। सरकार के इस फैसले का विरोध बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। सभी सेवाओं के अफसरों ने प्रतिदिन हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री को ऐसा न करने की सलाह और अनुरोध करने वाले पोस्टकार्ड भेजने का फैसला लिया है। खबर है कि रेल मंत्री के भरसक प्रयास के बाद भी रेलवे के अफसर कुछ सुनने को राजी नहीं हैं।

कौन हैं चतुर्वेदी जी...?

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक चतुर्वेदी जी की चर्चा जोरों पर है। मंत्रालय से लेकर पुलिस मुख्यालय तक चतुर्वेदी जी के नाम की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ ही लोगों ने चतुर्वेदी जी को देखा है। आलम यह है कि चतुर्वेदी जी के कारनामों की चर्चा करने वाले कई अफसर भी ऐसे हैं, जिन्होंने चतुर्वेदी जी को देखा नहीं है। प्रशासनिक वीथिका में नामदार हो रहे चतुर्वेदी जी की जब पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि वाकई में ये काफी रसूखदार हैं। चतुर्वेदी जी का रसूख इस कदर है कि वह कई रेंज के आईजी को चला रहे हैं। यानी चतुर्वेदी जी जो चाहते हैं कई आईजी, डीआईजी और एसपी वही करते हैं। बताया जाता है कि अपने रसूख का फायदा उठाकर चतुर्वेदी जी लक्ष्मी की कृपा भी खूब पा रहे हैं। यही नहीं कुछ लोग तो यह भी कहने से नहीं चूक रहे हैं कि चतुर्वेदी जी के कारण कई आईजी, डीआईजी और एसपी के घर भी इन दिनों लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। प्रशासनिक वीथिका में कुछ अफसर तो दबी जुबान से यह कहने से नहीं चूकते हैं कि काश हमें भी कोई चतुर्वेदी मिल जाए। वहीं कुछ अफसर चेताते हुए कहते हैं कि जिस दिन चतुर्वेदी जी भंडाफोड़ होगा उस दिन प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में किसी काले अध्याय का खुलासा हो सकता है। अब देखना यह है कि चतुर्वेदी जी की चतुराई कब तक कायम रहती है।

कैसे चलेगा खर्चा-पानी?

15 साल बाद सत्ता में वापसी के बाद जिन विधायकों को मंत्री पद मिला उनमें से अधिकांश ने अपने विभाग की योजनाओं-परियोजनाओं की आड़ में खर्चा-पानी का जुगाड़ कर लिया। हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा की तर्ज पर मंत्रियों के यहां खर्चा-पानी के लिए रकम पहुंच रही है। लेकिन हर मंत्री उतना भाग्यवान नहीं है। प्रदेश में एक मंत्री को इन दिनों खर्चा-पानी की चिंता सता रही है। दरअसल, मंत्रीजी के विभाग की जिस योजना से उनके यहां खर्चा-पानी की रकम पहुंचती थी, उसकी नीति में बदलाव कर दिया गया है। दरअसल, यह बदलाव इसलिए किया गया है कि उक्त योजना बच्चों के पोषण के लिए शुरू की गई है, लेकिन उसमें जबरदस्त घपलेबाजी चल रही थी, इसको देखते हुए नीति में बदलाव क्या हुआ कि मंत्रीजी के यहां पहुंचने वाला खर्चा-पानी भी बंद हो गया। अब उक्त मंत्री को यह चिंता खाए जा रही है कि उनका तथा उनके कार्यकर्ताओं का खर्चा कैसे चलेगा। यहां बता दें कि मंत्रीजी का विभाग ऐसा है जो हमेशा अपने घपले-घोटालों के लिए सुर्खियों में बना रहता है।

तबादले के लिए तीन ओएसडी

अगर यह कहा जाए कि प्रदेश के एक सबसे प्रमुख विभाग के मंत्री केवल शोभा की वस्तु बने हुए हैं तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो मंत्रीजी की विभाग में चल नहीं पा रही है, उस पर उन पर पहरा बिठा दिया गया है। ऐसे में मंत्रीजी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनको लक्ष्मी प्राप्त हो सके। जानकारी के अनुसार कहने को तो मंत्री जी के पास दो ओएसडी हैं। वे विभागीय कार्यों के साथ ही अन्य कार्यों में मंत्रीजी की सहायता करते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि मंत्रीजी के विभाग में छोटे स्तर पर होने वाले तबादले के लिए जब भी बैठक होती है उसमें एक तीसरे ओएसडी भी शामिल रहते हैं। बताया जाता है कि इनकी उपस्थिति के कारण मंत्रीजी के दोनों ओएसडी तबादलों में कुछ खास नहीं कर पाते हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई कि तीसरे ओएसडी की जमावट खुद सरकार के मुखिया ने की है। गौरतलब है कि यहां जिस विभाग की बात की जा रही है वह विभाग कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालता है। कहा जाता है कि इस विभाग में होने वाले तबादलों में बड़े स्तर पर लेनदेन होती है। मलाइदार पद और स्थान पाने के लिए अदना सा अफसर भी लाखों इधर-उधर कर देता है। शायद यही वजह है कि विभाग की बैठक में तीसरे ओएसडी आ धमकते हैं। इन महाशय पर सरकार को भी भरपूर ऐतबार है।

तू डाल-डाल, मैं पात-पात

यह कहावत इन दिनों प्रदेश के सबसे कमाऊ विभागों में से एक विभाग में चरितार्थ हो रही है। दरअसल, विभाग दो धुर्व में बंट गया है। एक तरफ विभाग के सारे अधिकारी हैं तो दूसरी तरफ विभागीय मंत्री। अफसर अपनी खिचड़ी पकाने के लिए चाल पर चाल चल रहे हैं तो मंत्री ने भी उनकी चाल भांप ली है और वे अपनी चाल चलने लगे हैं। जानकारी के अनुसार गत दिवस हुई विभागीय बैठक में निर्णय लिया गया कि विभाग में अन्य विभागों से फ्लाइंग स्कॉट की भर्ती की जाए। इसको लेकर अफसरों ने पूरी फाइल तैयार कर मंत्रीजी के पास अनुमति के लिए भेज दी। बताया जाता है कि फाइल का अवलोकन करने के बाद मंत्री जी को अहसास हुआ कि किस तरह अफसर उन्हें अंधेरे में रखकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। फिर क्या था मंत्रीजी ने भी अपने हिसाब से उसमें काला-पीला कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनके पास लक्ष्मी का हिसाब बराबर नहीं पहुंच रहा है। मंत्री जी ने कई अन्य फाइलों को भी लटका रखा है, क्योंकि उन्हें डर है कि अफसर उनसे किसी ऐसी-वैसी फाइल पर दस्तखत न करा लें।

साख पर आंच

प्रदेश सरकार का अब तक का कार्यकाल निर्विवाद रहा है। लेकिन अपने ही नेताओं और कुछ अधिकारियों के कारण सरकार की साख पर आंच आ रही है। दरअसल, गत दिनों हुए एमपीपीएससी की परीक्षा में भील आदिवासियों को अपराधी बताए जाने संबंधित सवाल पूछा गया था। इस सवाल पर बवाल मचना तय था, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री के विधायक भाई ने इस मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ मुख्यमंत्री से सदन में माफी मांगने की बात कहकर सारा दोष सरकार पर मढ़ दिया। इससे सरकार की साख पर आंच आ गई। यही नहीं एक जिम्मेदार संस्था द्वारा इस तरह की गलती होना भी सरकार के लिए चिंता का विषय है। वहीं एक जिले के कलेक्टर की कथनी से सरकार की साख पर बन आई है। यह महोदय एक फिल्म को लेकर हो रहे विवाद में बेवजह कूद पड़े हैं। ऐसा कर उन्होंने अपने सर्विस रूल का उल्लंघन किया है। अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर पिल पड़ा है। आलम यह है कि केंद्र में शिकायत की नौबत आ गई है।

राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) भारत को बांटने की एक भयावह और शरारतपूर्ण योजना है। इसके तहत भारत में रहने वाले हर नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। यह लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों के खिलाफ है।

● **पी चिदंबरम**

टेस्ट क्रिकेट का प्रशंसक होने के नाते मुझे नहीं लगता कि इससे छेड़छाड़ की जानी चाहिए। इस प्रारूप को उसी तरह खेला जाना चाहिए जिस तरह यह वर्षों से खेला जाता रहा है। टेस्ट क्रिकेट को चार दिन का कर देने पर बल्लेबाज यह सोचना शुरू कर देंगे कि यह सीमित ओवरों के क्रिकेट का लंबा प्रारूप है। इससे खेल को लेकर सोच बदल जाएगी।

● **सचिन तेंदुलकर**

ऑफिस में काम करने के लिए हफ्ते में चार दिन तय होने चाहिए। मेरा मानना है कि लोग अपने परिवार, प्रियजनों, जीवन और संस्कृति के अन्य पहलुओं के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। कामकाजी जीवन में यह हमारे लिए अगला कदम हो सकता है। केवल फिनलैंड ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के देशों को यह तय करना चाहिए।

● **सना मारिन**

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नकाबपोशों द्वारा की गई हिंसा के दृश्य देखकर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले की याद आ गई। शीघ्र ही जांच करके इन नकाबपोश हमलावरों को पकड़ा जाना चाहिए। आज देशभर में छात्र खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

● **उद्धव ठाकरे**

अपने देश में हर कोई यही चाहता है कि लड़की गोरी होनी चाहिए। किसी भी लड़की को उसके रंग से नहीं जज करना चाहिए। भले ही मेरा रंग दुनिया कि नजर में सांवला है फिर भी मुझे अपने पर नाज है। हमें कभी भगवान से इस प्रकार की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसा क्यों बनाया। कभी नहीं! हमें हमेशा खुद से प्यार करना चाहिए भले ही लोग हमें किसी भी तरह जज करें। ऐसे में लोगों को भी लड़कियों को उनके कलर, उनके शरीर की बनावट, उनका चलना, बैठना, उनका पहनावा हर किसी को जज करने का कोई हक नहीं है।

● **पौलमी दास**

वाक्युद्ध

अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए मोदी सरकार ऐसे कानून देश पर थोप रही है, जिससे लोगों का ध्यान उसकी कमजोरियों पर न जाए। देश में शांति थी, लेकिन केंद्र ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर को अपने पिटारे से निकालकर लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया है। अब दोष विपक्ष को दे रहे हैं।

● **राहुल गांधी**

केंद्र सरकार ने ऐसा कोई भी कानून का प्रावधान नहीं किया है, जिससे ऐसे आंदोलन की जरूरत थी। लेकिन विपक्ष ने जनता को कानूनों की गलत व्याख्या कर उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित किया है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल देश में हो रहे आंदोलनों के लिए जिम्मेदार हैं और उनके कारण ही कानून व्यवस्था बिगड़ रही है।

● **अमित शाह**

क्या लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली...?

मप्र की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इस समय यह सवाल चर्चा में बना हुआ है कि क्या प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश में पहली बार लखनऊ व गौतमबुद्धनगर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा) में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा कर दी गई है। मप्र में पिछले साल 15 अगस्त को सीएम कमलनाथ कमिश्नर सिस्टम लागू करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने ऐलान नहीं किया। अब संभावना जताई जा रही है कि 26 जनवरी को सीएम ऐलान कर सकते हैं। इस बारे में आईपीएस एसोसिएशन और डीजीपी की मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है।

पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के लिए गृहमंत्री बाला बच्चन का कहना है जो मध्यप्रदेश के हित में होगा, जनता जो चाहेगी और कानून की दृष्टि से जो बेहतर होगा, वही निर्णय सीएम कमलनाथ लेंगे। भाजपा सरकार में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के लिए बड़ी लंबी-चौड़ी कवायद की गई थी। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। सीएम कमलनाथ पहले ही कमिश्नर सिस्टम लागू करने के संकेत दे चुके हैं। लेकिन आईएएस लॉबी की वजह से इस पर हर बार संकट आ जाता है। ऐन वक्त पर फैसले बदल जाते हैं।

प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि राजधानी सहित प्रदेशभर में बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए यह जरूरी है। लेकिन प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच इससे सहमत नहीं हैं। वह कहती हैं कि सिस्टम बदलने से अपराधों में कमी नहीं आएगी। पुलिस के वर्तमान ढांचे में एडीजी स्तर के अफसरों की भरमार है, जबकि मैदानी अमले की कमी है। थाने से लेकर जिला और संभाग मुख्यालय में पदस्थ अफसर व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाएं, इस पर जोर होना चाहिए।

वह कहती हैं कि अपराधों पर अंकुश पुलिस की सतर्कता और सक्रियता से लगेगा, न कि पावर बढ़ने से। पुलिस पर प्रयोग बंद होना चाहिए। एसएसपी, फिर डीआईजी और अब पुलिस कमिश्नर सिस्टम। इसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसा होता तो बेंगलुरू और दिल्ली में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद अपराधों में कमी आती। दोनों शहरों में महिला अपराध बढ़े हैं।

उधर, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं, इसलिए अपराधों पर अंकुश लगाने में पुलिस अक्षम साबित हो रही है। पूर्व पुलिस महानिदेशक अरुण गुर्टू कहते हैं कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली एक ऐसा सिस्टम है जो पुलिस अधिकारियों को जवाबदेह बनाएगा। दूसरे राज्य इसे लागू कर चुके हैं, वहां अच्छे परिणाम मिले हैं। फिर मप्र में इससे क्यों परहेज हो रहा है। जब तक अच्छा सिस्टम नहीं बनेगा, अच्छे से अच्छा अधिकारी परिणाम नहीं दे पाएगा।

प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की वकालत करने वाले आईपीएस अधिकारियों का कहना है कि इस प्रणाली की जरूरत इसलिए है कि जिलाबदर के प्रस्ताव महीनों तक कलेक्टर कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं। कई आदतन अपराधियों को भी एसडीएम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। पुलिस जिस अपराधी का प्रोफाइल जानती है, उसे सीधे जेल भेजेगी। कानून व्यवस्था से जुड़े विषयों पर पुलिस खुद निर्णय ले सकेगी। साथ ही इस प्रणाली के लागू होने से पुलिस के अधिकार भी बढ़ेंगे। प्रतिबंधात्मक धाराओं में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत पुलिस की कोर्ट से होगी। जिलाबदर भी पुलिस अफसर ही तय करेंगे। सीमित क्षेत्र में धारा 144 लागू करने के अधिकार होंगे। लाठीचार्ज की अनुमति कलेक्टर से नहीं लेनी होगी। धरना-प्रदर्शन, रैलियों की अनुमति पुलिस देगी।

वर्तमान समय में देश के 71 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। दिल्ली, बेंगलुरू और मुंबई के अपराधों पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि यह प्रणाली भी अपराध रोकने में उतनी कारगर नहीं है। अगर मप्र के संदर्भ में देखें तो यह महिला अपराधों में पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए सरकार ने कई प्रयोग किए लेकिन कोई कारगर नहीं हो सका। वर्ष 2009 में एसएसपी सिस्टम इंदौर और भोपाल में लागू किया गया लेकिन इससे भी कोई बदलाव नहीं दिखा। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2012 में 28 फरवरी को विधानसभा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। लेकिन इस पर बात नहीं बनी। सरकार ने 18 दिसंबर 2012 को दो महानगरों में एसएसपी सिस्टम समाप्त कर डीआईजी सिस्टम लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। लेकिन इसका भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। यही नहीं राजधानी पुलिस ने लॉ एंड आर्डर और इन्वेस्टिगेशन विंग अलग-अलग बनाने का प्रयोग भी किया। यह प्रयोग सबसे पहले हबीबगंज थाने में किया गया। हालांकि वक्त के साथ-साथ यह भी फाइलों में बंद होकर रह गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वर्तमान सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली जैसा प्रयोग करेगी?

● **अरविंद नारद**

ऐसा होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम

एमपी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के पिरामिड में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी स्तर के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। उसके नीचे दो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, जो आईजी स्तर के होंगे। पिरामिड में एडिशनल पुलिस कमिश्नर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी डीआईजी स्तर अफसरों को मिलेगी। इसी तरह डिप्टी पुलिस कमिश्नर एसपी स्तर के होंगे। जूनियर आईपीएस या वरिष्ठ एसपीएस अधिकारियों को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकेगा। सबसे पहले पुलिस कमिश्नर सिस्टम इंदौर और भोपाल में लागू किया जा सकता है। यानि मध्यप्रदेश की कुल आबादी में से केवल 5.6 फीसदी पर ही कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। प्रदेश की सात करोड़ 26 लाख आबादी में से भोपाल की 18.86 लाख और इंदौर की 21.93 लाख आबादी है। भोपाल की आबादी प्रदेश की कुल आबादी का 2.59 प्रतिशत है और इंदौर की आबादी 3.01 प्रतिशत है।

फिक्रमंद नहीं सांसद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस उद्देश्य के साथ सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी, वह अपने उद्देश्य से भटक गई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। इसका उद्देश्य एक आदर्श भारतीय गांव के बारे में महात्मा गांधी की व्यापक कल्पना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए एक यथार्थ रूप देना था। योजना के अंतर्गत, प्रत्येक सांसद एक ग्राम पंचायत को गोद लेता है और सामाजिक विकास को महत्व देते हुए इसकी समग्र प्रगति की राह दिखाता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर हो। सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया जाता है और सांसदों को सांसद निधि के कोष से ही इसका विकास करना होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के कुछ महीनों के भीतर ही सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान किया था। इसके तहत करीब 2500 गांवों की कायापलट करने का लक्ष्य रखा गया था। योजना के तहत 2014 से 2019 के बीच चरणबद्ध तरीके से सांसदों को तीन गांव गोद लेने थे और 2019 से 2024 के बीच पांच गांव गोद लेने की बात कही गई है। सांसदों ने इस पर किस तरह रुचि ली। सांसद कितने फ्रिकमंद हैं। यह सामने आया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से। आंकड़े बता रहे हैं कि पहले चरण में सांसदों ने अच्छी रूचि दिखाई इसके बाद चौथे चरण तक आते-आते हालात इस तरह दिख रहे हैं जिससे साबित होता है कि सांसदों को अपने गांवों की चिंता नहीं है।

मप्र में लोकसभा के 29 और राज्यसभा के 11 सांसद हैं। इनमें से लोकसभा के 28 और राज्यसभा के 8 सांसद भाजपा के हैं। यानी 40 में से 36 सांसद भाजपा के हैं, लेकिन इनमें से मात्र 7 सांसदों ने ही **आदर्श ग्राम योजना** के चौथे चरण में गांवों को गोद लिया है। इस कारण मप्र बड़े राज्यों में फिसड्डी साबित हुआ है। मप्र के सांसदों ने चार चरणों में कुल 80 गांवों को गोद लिया है। इनमें सबसे कम चौथे चरण में अब तक मात्र 7 गांवों को गोद लिया है। जबकि चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के 52, तमिलनाडु के 36, महाराष्ट्र के 32, गुजरात के 28, राजस्थान के 20, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के सांसदों ने 9-9 गांवों को गोद लिया है।

केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सांसद आदर्श ग्राम योजना के पहले चरण में लोकसभा के 543 सांसदों में से 500 सांसदों ने अपने चुनाव क्षेत्र में एक गांव को गोद लिया। वहीं राज्य सभा के कुल 254 सदस्यों में से 203 सदस्यों ने योजना के मुताबिक अपने लिए एक-एक गांव का चयन किया है। लोकसभा और राज्य सभा मिलाकर जहां देश में कुल 796 सांसद थे, वहीं 93 सांसदों ने अपने लिए गांव का चयन नहीं किया। यानी पहले चरण में देशभर में महज 703 गांवों को विकास के टॉप गेयर पर डालने के लिए चयन किया गया। जिसमें मप्र के 40 सांसदों में से 37 सांसदों द्वारा गोद लिए गांव भी थे।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना के दूसरे चरण में स्थिति और भी खराब है। लोकसभा के 545 सांसदों में महज 364 सांसदों ने अपने लिए एक गांव का चयन किया। वहीं 259 सांसदों ने गांव का चयन नहीं किया। वहीं राज्यसभा के 243 सांसदों में से महज 133 सांसदों ने गोद लेने वाले गांवों का चयन किया। 110 सांसद गांव गोद नहीं ले सके। लिहाजा,

सात माह में महज सात ने चुना गांव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजनाओं में शामिल सांसद आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के सांसदों की रुचि नहीं दिखाई दे रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तक अभी सात सांसदों का प्रस्ताव पहुंचा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने जबलपुर के ग्राम घाना को आदर्श ग्राम बनाने के लिए चुना है। इनके अलावा सागर के सांसद राज बहादुर सिंह ने नरयावली विधानसभा क्षेत्र व सागर जनपद के तहत आने वाली पंचायत बदौना को, इंदौर सांसद शंकर लालवानी में तिल्लौर खुर्द, राज्यसभा सांसद व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीहोर जिले के बुदनी विकासखंड के ग्राम पंचायत डोबी का चयन किया है। वहीं राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने सिंगरौली के पोड़ी नौगाई गांव को गोद लिया है।

आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण के लिए कुल 788 सांसदों में महज 497 सांसदों ने अपने लिए एक गांव का चयन किया। वहीं 291 सांसदों ने योजना के इस चरण में गांव का चयन नहीं किया। दूसरे चरण में मप्र के महज 20 सांसदों में ही गांव गोद लिए।

आदर्श ग्राम योजना का तीसरा चरण पूरे आदर्श ग्राम योजना पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा के 545 सांसदों में महज 239 सांसदों ने इस चरण में अपने लिए एक गांव को गोद लिया। वहीं राज्यसभा के 243 सांसदों में महज 62 सांसदों ने जरूरी प्रक्रिया को पूरा किया। लिहाजा, आंकड़ों के मुताबिक कुल 788 सांसदों में से 487 सांसदों ने तीसरे चरण के लिए एक भी गांव का चयन नहीं किया। मप्र के 15 सांसदों ने इस चरण में रुचि दिखाई और गांव गोद लिए। चौथा चरण की हालत बहुत खराब रही। सांसद आधे रह गए। केवल 252 सांसदों ने रुचि दिखाई और गांव गोद लिए इनमें 208 लोकसभा से और 44 राज्यसभा से हैं। मप्र के सांसदों की रुचि भी कम होती गई। गोद लेने वाले सांसदों का आंकड़ा 7 पर अटक गया है।

इस योजना में 2016 तक प्रत्येक सांसद को एक-एक गांव को गोद लेकर उसे विकसित करना था। 2019 तक दो और गांवों और 2024 तक आठ गांवों का विकास किया जाना था। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से भी अपील की थी कि वे विधायकों को इस योजना के लिए प्रोत्साहित करें, तो हर निर्वाचन क्षेत्र में 5 से 6 और गांव विकसित हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सांसदों और कैबिनेट मंत्रियों के इस योजना से मुंह मोड़ने की वजह योजना के लिए बजट में किसी प्रकार के फंडिंग के इंतजामों को न होना माना गया। सांसदों को बताया गया था कि देश में चल रही मौजूदा योजनाओं- इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, बैकवर्ड रीजंस ग्रांट फंड, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सांसद निधि, ग्राम पंचायत की कमाई, केंद्र और राज्य वित्त आयोग निधि और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी के ही पैसे का इस्तेमाल किया जाए।

सिर्फ 1,753 गांव चयनित

साल 2014 में लॉन्च सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अब तक सिर्फ 1,753 ग्राम पंचायत ही आदर्श ग्राम के लिए चयनित हुए हैं। 2019 के बाद अब सभी सांसदों को 5 गांवों को गोद लेकर उन्हें आदर्श ग्राम बनाना है। सांसद ग्राम योजना भारत की पहली ऐसी योजना है जिसमें सांसदों को एक साल के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र के किसी एक गांव को गोद लेकर वहां की बुनियादी सुविधाओं समेत खेती, रोजगार, पशुपालन आदि क्षेत्रों के विकास कार्य में जोर देना है। साल 2014 से 2019 के बीच चार पड़ावों में सांसदों द्वारा अपने लोकसभा क्षेत्र में किसी भी एक गांव को गोद लेने की संख्या तेजी से घटी है। आदर्श ग्राम योजना के तहत साल 2016 तक सभी सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र के किसी एक गांव पर विकास कार्य कर उसे आदर्श गांव का मॉडल बनाना था। साल 2016 के बाद सांसदों को किसी दो गांव को गोद लेकर उसे आदर्श गांव के रूप में तब्दील करना था। वहीं 2019 के बाद यानी वर्तमान में अब से पांच गांव सांसदों के झोली में हैं, जिन्हें उन्हें आदर्श ग्राम बनाना है। आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत विकास कार्य पूरा करने के लिए कई तरह से फंड मिलते हैं। इनमें इंदिरा आवास, पीएमजीएसवाय और मनरेगा शामिल है। इसके अलावा सांसदों को मिलने वाला विकास फंड भी कार्यक्रम पूरा करने में मददगार है।

केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यह योजना काफी सफल रही है। नवंबर 2017 को केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 19,732 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं और 7,204 पर काम चल रहा है। वैसे, सरकार चाहे जो भी दावे करे, देश की अन्य योजनाओं की तरह पीएम मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना भी धरातल तक नहीं पहुंच सकी। इसके पर्याप्त कारण भी हैं। इस योजना को जिस तरह से प्रचारित किया गया, उसके स्तर पर इसकी फंडिंग के इंतजाम नहीं किए गए। इसके लिए कोई नया फंड निर्धारित नहीं हुआ। सांसदों को बताया गया था कि देश में चल रही मौजूदा योजनाओं- इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, बैकवर्ड रीजंस ग्रांट फंड, सांसद निधि, ग्राम पंचायत की कमाई, केंद्र और राज्य वित्त **आयोग निधि और कॉरपोरेट** सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी के ही पैसे का इस्तेमाल किया जाए। इस योजना के तीन चरण थे। पहले चरण के तहत 2014 से 2016 के बीच एक गांव को गोद लेकर उसे विकसित करना था। इस दौरान 543 लोकसभा सांसदों में से 500 सांसदों ने और 245 राज्यसभा सांसदों में से 203 सांसदों ने गांवों को गोद लिया। दूसरे चरण यानी 2016 से 2018 के बीच केवल 340 लोकसभा सांसदों और 126 राज्यसभा सांसदों ने गांवों को गोद लिया। तीसरे चरण यानी 2017 से 2019 के बीच गांवों को गोद लेने वाले सांसद और कम हो गए। अब तक केवल 141 लोकसभा सांसदों और 32 राज्यसभा सांसदों ने ही गांवों को गोद लिया है।

सांसदों के गोद लिए कई गांवों को आदर्श गांव घोषित तो कर दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन गांवों की हालत पहले जैसी हो गई। इन गांवों में सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कई काम कराए गए थे, जिनकी गुणवत्ता कुछ महीनों बाद ही सामने आने लगी। इन गांवों में से अधिकांश में सड़क, सफाई, बिजली, पानी, रोजगार और स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। हाल ही में शहरी विकास पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि फंडिंग और उचित कार्ययोजना के अभाव में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं कागजों में ही सफल होंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी मोदी सरकार की छह शीर्ष योजनाओं में केवल 21 फीसदी फंड का ही इस्तेमाल हो सका। ये हाल स्मार्ट सिटी समेत उन योजनाओं का है जिनके लिए अतिरिक्त फंड की घोषणा की गई थी। आदर्श ग्राम योजना के लिए तो सरकार की ओर से किसी अतिरिक्त फंड का इंतजाम नहीं है। ऐसे में आदर्श गांव बनाने का पीएम का सपना सच होता नहीं दिख रहा है।

● **अरूण दीक्षित**

जौरा में अग्निपरीक्षा

मप्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे शह-मात के खेल में एक बार फिर दोनों पार्टियों और उनके दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अग्निपरीक्षा होगी। इसके लिए जौरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चौसर बिछनी शुरु हो गई है।

प्रदेश में जौरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आने लगी है। कांग्रेस विधायक बनवारी लाल के निधन के बाद जौरा सीट खाली हुई है। इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। उधर टिकट के दावेदार चुनावी मैदान में सक्रिय हो गए हैं। गौरतलब है कि झाबुआ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। वह अपनी जौरा सीट हाथ से निकलने नहीं देगी। वहीं भाजपा इस सीट को जीतकर झाबुआ का बदला लेने की कोशिश करेगी।

झाबुआ उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के पास सदन में 115 विधायकों और एक निर्दलीय विधायक के मंत्री होने से 116 की मजबूत स्थिति आ गई थी। हालांकि, कांग्रेस के लिए अभी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सदन में अब 229 विधायक बचे हैं। इसमें से कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 114 विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा के विधायकों का समर्थन है। वहीं, बीजेपी के पास फिलहाल सदन में 108 विधायकों का संख्या बल है। बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद अब सीट खाली हो गई है, जौरा में उपचुनाव होगा।

जौरा में होने वाले उपचुनाव में सिंधिया के साथ केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसका कारण यह है कि तोमर मुरैना संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं जबकि सिंधिया अंचल के सर्वमान्य कांग्रेस नेता हैं। टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति बनाने में इन दोनों नेताओं की प्रमुख भूमिका रहेगी। जौरा विधानसभा में उपचुनाव अगले 6 माह के अंदर होना है। ऐसे में सिंधिया के कंधो पर भार आने वाला है। वैसे विधानसभा चुनाव के समय भी सिंधिया ने अंचल का भार अपने कंधो पर लिया था और 28 विधानसभा सीटें जीतकर कांग्रेस को दी थी जिसके कारण ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकी थी।

भाजपा के अंदर केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर संगठन क्षमता के हिसाब से काफी आगे है, क्योंकि युवा मोर्चा से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्होने अपनी संगठन क्षमता कई बार दिखाई है। यही कारण है कि इस बार जौरा उपचुनाव की जिताने की जिम्मेदारी तोमर के ऊपर काफी रहेगी, लेकिन सामने सिंधिया के होने के कारण मामला बराबरी पर अटकता है। सिंधिया युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय होने के साथ ही अंचल की जनता के बीच सर्वमान्य नेता माने जाते है। अब कांग्रेस के अंदर उनके ऊपर कितना विश्वास किया जाता है यह समय के हिसाब से ही देखने को मिलेगा।

जौरा विधानसभा क्षेत्र रिक्त होने के बाद से ही कांग्रेस की तरफ से कई दावेदार सक्रिय हो गए है। अब दावेदार तो कई है, लेकिन कौन मैदान में आएगा इसका फैसला सिंधिया के हाथ में रहेगा। वैसे जिसको भी मौका मिलेगा उसके लिए उपचुनाव की राह आसान हो सकती है, क्योंकि सरकार के लिए एक-एक विधायक काफी महत्वपूर्ण है जिसके कारण जहां सरकार पूरा जोर लगाएंगी वहीं सिंधिया भी अपने दावेदार को जिताने के लिए मैदान में जोर लगाने से नहीं चूकेंगे।

इधर कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद एक बार फिर प्रदेश की विधानसभा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रदेश की विधानसभा पिछले 16 साल में 31 उपचुनाव देख चुकी है। 32वां उपचुनाव भी आने वाले समय में जौरा विधानसभा सीट पर होगा। ये स्थिति बहुत कम समय के लिए बनी है जब विधानसभा में पूरे 230 सदस्य मौजूद रहे हों। उपचुनाव का सिलसिला 2003 से शुरू हुआ जो अब तक जारी है। हाल ही में प्रदेश दो विधानसभा उपचुनाव से गुजर चुका है जिसमें छिंदवाड़ा और झाबुआ शामिल हैं। इन उपचुनाव के पीछे जो वजह हैं उनमें विधायकों का निधन, विधानसभा सीट छोड़कर लोकसभा चले जाना या फिर पार्टी बदलने के बाद अपनी सीट से इस्तीफा देना और फिर दूसरी पार्टी की टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ना। 2013 में चुनाव के वक्त तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी का निधन हो गया था।

नई विधानसभा के वास्तु पर गाहे-बगाहे सवाल खड़े होते रहे हैं। वास्तुशास्त्री इसे भवन निर्माण का दोष बताते हैं लेकिन कई लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी ने इस भवन में कुछ बदलाव जरूर करवाए थे। इसके अलावा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज का कार्यक्रम विधानसभा भवन में कराया था। इतना ही नहीं उनको सदन में भी ले जाया गया था। इन सभी बातों को वास्तु से जोड़कर देखा गया था। अभी तक जिन विधानसभा सीट पर उपुचनाव हुए हैं उनमें नोहटा, बालाघाट, बुदनी, बड़ा मलहरा, पंधाना, उदयपुरा, शिवपुरी, लांजी, सांवेर, गोहद, तेंदूखेड़ा, सोनकच्छ, कुक्षी, जबेरा, महेश्वर, विदिशा, बहोरीबंद, विजयराधौगढ़, आगर, गरोठ, देवास, मैहर, घोड़ाडोंगरी, नेपानगर, बांधवगढ़, अटेर, चित्रकूट, मुंगावली, कोलारस, छिंदवाड़ा और झाबुआ विधानसभा सीट शामिल हैं।

● **सुनील सिंह**

अंचल में कांग्रेस का रिकॉर्ड बेहतर

ग्वालियर अंचल में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का इतिहास रहा है। शिवपुरी विधानसभा का उप चुनाव हुआ था उस समय भाजपा की सरकार थी ओर सत्ता पक्ष के अधिकांश मंत्रियों ने वहां डेरा डाला था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अकेले सिंधिया ने लड़ाई लड़ी ओर कांग्रेस प्रत्याशी को फतह दिलवाई थी। इसी तरह कोलारस के साथ ही अटेर का भी उपचुनाव कांग्रेस ने सिंधिया की दम पर जीता था। जौरा विधानसभा में बसपा का भी काफी बोलबाला रहा है और वहां से उसके दो बार विधायक भी रहे है इसलिए कांग्रेस को बसपा के साथ समझौता करने में लाभ हो सकता है, लेकिन उपचुनाव के समय क्या गणित बैठता है उसके बाद ही यह तय हो सकेगा कि कांग्रेस के लिए राह कितनी आसान है।

फॉरेंसिक जांच पर आंच

सागर की लैब के भरोसे

डीएनए रिपोर्ट की जांच के लिए सागर जिले में प्रदेश की इकलौती फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है। यहां प्रदेशभर से हर महीने 200 से ज्यादा सैंपल आते हैं। लैब में रेप-मर्डर जैसे गंभीर अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन सैंपल ज्यादा आने की वजह से रिपोर्ट में देरी होती है। कई बार सैंपल ज्यादा होने से इन्हें जांच के लिए हैदराबाद की लैब में भेजना पड़ता है। डीएनए जांच के लिए सागर एफएसएल में 9 साइंटिस्ट हैं। अभी भी लैब में करीब 1200 जांच रिपोर्ट लंबित हैं। इनमें गंभीर अपराधों की जांच रिपोर्ट भी शामिल है। एनसीआरबी के आंकड़ों में रेप के मामले में प्रदेश के लगातार कई वर्षों तक 'नंबर-वन' रहने पर पूर्व की बीजेपी सरकार ने दो साल पहले इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिए थे। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए कई उपाय किए, साथ ही प्रदेश के 5 जिलों में 100 करोड़ रुपए की लागत से डीएनए लैब खोलने का प्रस्ताव भेजा। मगर सरकार ने प्रस्ताव पर ध्यान ही नहीं दिया।

हाल ही में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी वर्ष 2018 के अपराधों के आंकड़ों में मध्य प्रदेश में फिर दुष्कर्म की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आईं हैं। यहां हर रोज लगभग 15 बच्चियों या **महिलाओं को वहशी** लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। यह चिंता का विषय है। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि दुष्कर्म के मामलों की जांच भी समय पर और ठीक से नहीं हो पा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां फॉरेंसिक जांच पर आंच आई है।

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश वर्ष 2018 में भी 5450 दुष्कर्म की घटनाओं के कारण देश में पहले नंबर रहा है। चिंता की बात रही कि इन घटनाओं में 54 ऐसी भी हैं जो छह साल या इससे कम उम्र की बच्चियों के साथ घटीं। वहशीपन की हद यह भी रही कि 60 साल से अधिक उम्र की 11 वृद्ध महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं से मप्र शर्मसार हुआ है। लेकिन कितने मामलों में दोषियों को सजा हो पाई है? इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि कई मामलों में फॉरेंसिक जांच अभी भी अटकी हुई है। यही नहीं मध्यप्रदेश पुलिस फॉरेंसिक मामलों की जांच के मामले में लगातार फेल साबित हो रही है। भोपाल की मनुआभान टेकरी में पिछले साल आठवीं की छात्रा के साथ हुए रेप और हत्या की सनसनीखेज वारदात में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की चालान डायरी में आरोपी बनाए गए जस्टिन राज और अविनाश साहू की डीएनए रिपोर्ट निगेटिव आई है। सागर फॉरेंसिक लैब से दो बार आई डीएनए रिपोर्ट में ये दोनों आरोपी बे-गुनाह साबित हुए हैं। इनके ब्लड और सीमन का छात्रा के शरीर से लिए गए सैंपल से मिलान नहीं हुआ है। छात्रा के शरीर में आरोपियों के बजाय किसी दूसरे के सीमन पाए गए। डीएनए रिपोर्ट पुलिस के लिए गले की फांस बन गई है।

भोपाल पुलिस अब इस रिपोर्ट को अन्य फॉरेंसिक लैब में भेजकर नई रिपोर्ट के इंतजार में है। ऐसे में अहम सवाल यह उठ रहा है कि अगर आरोपियों की डीएनए रिपोर्ट निगेटिव है तो छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या किसने की थी। ऐसी ही कई अन्य रेप और हत्या की घटनाएं हैं, जो फॉरेंसिक जांच के कारण अटकी हुई हैं। ऐसे में या तो निर्दोष जेल की सजा काट रहे हैं, या फिर दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। सागर की फॉरेंसिक लैब वर्ष 2018 से मई 2019 के बीच हुए रेप केस में डीएनए रिपोर्ट के **आधार पर 29 गुनाहगारों को फांसी की सजा दिलवा चुकी है। लेकिन भोपाल की मनुआभान टेकरी की घटना** से संबंधित रिपोर्ट के बाद पुलिस की कार्रवाई ने सागर फॉरेंसिक लैब पर प्रश्न-चिन्ह लगा दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस ने हैदराबाद से जो **रिपोर्ट** मंगाई है वह क्या कहानी बयां करती है।

सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि पिछले कई सालों से बलात्कार के मामले में नंबर-1 रहने के बावजूद भी सरकार ने डीएनए जांच की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है। पुलिस को सागर की एकमात्र लैब के भरोसे रहना पड़ रहा है। अगर सागर लैब की किसी जांच से पुलिस संतुष्ट नहीं हो पाती है तो उसे दूसरे प्रदेशों की लैब का सहारा लेना पड़ता है। दरअसल प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाओं पर **सियासत** होती रही है। सरकारें भले बदल गई हों, विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सदन से सड़क तक हंगामा करती रही है, लेकिन रेप की घटना के बाद सबसे महत्वपूर्ण सबूत माने जाने वाले डीएनए रिपोर्ट तैयार करने वाली प्रयोगशाला यानी लैब बनाने की ओर सरकारों का ध्यान नहीं गया। दो साल पहले पुलिस मुख्यालय ने शासन को इस बाबत प्रस्ताव भेजा था, लेकिन आज भी ये प्रस्ताव फाइलों में धूल खा रहा है। महिला अपराधों को सियासी मुद्दा तो बनाया जाता है, लेकिन डीएनए लैब के प्रस्ताव को हरी झंडी दी जाए, इस दिशा में काम नहीं होता। पुलिस मुख्यालय ने कई बार इस बाबत शासन को याद भी दिलाया है, फिर भी शासन मौन है।

पीएचक्यू के प्रस्ताव के अनुसार इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को अपडेट कर डीएनए लैब बनाने की बात कही गई है। वहीं उज्जैन और रीवा में नई लैब खोले जाने का प्रस्ताव है। डीएनए लैब के साथ ही पुलिस राज्य के सभी 9 जोन में एक रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी खोलने पर भी विचार कर रही है। इस काम पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पुलिस के मुताबिक रेप के आरोपियों को उनके अपराध की सजा दिलाने के लिए डीएनए की जांच अहम होती है। पिछले साल नाबालिग से रेप के 21 मामलों में फांसी सुनाई गई। इनमें से 19 मामलों में डीएनए रिपोर्ट अहम सबूत साबित हुई थी। जब बीजेपी की सरकार थी, तो कांग्रेस ने रेप की घटनाओं को लेकर हंगामा किया था। लेकिन अब सरकार कांग्रेस की है और बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती रही है। मनुआभान की टेकरी पर हुए गैंगरेप की डीएनए रिपोर्ट नहीं होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री **शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे थे।** सरकार से डीएनए लैब खोलने की मांग भी की थी। लेकिन 15 साल तक प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया।

● **राजेश बोरकर**

कमजोर न हों जड़ें

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जोर अब शाखाओं को बढ़ाने पर रहेगा। युवा, महिलाओं, छात्रों को जोड़ने के साथ वनवासी परिवार में संघ का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, केरल, पश्चिम बंगाल और असम में संघ का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा। यह निर्णय एक निजी गार्डन में संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में चल रही संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार की राष्ट्रवादी नीतियों और कार्यों की प्रशंसा की गई और संघ व उससे जुड़े वैचारिक संगठनों का कार्यक्षेत्र ग्रामीण अंचल तक फैलाने का फैसला हुआ। एक अहम निर्णय सहकार्यवाह की संख्या बढ़ाने और भाजपा सहित अन्य अनुषंगी संगठनों में और प्रचारकों को भेजने का रहा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रस्ट के गठन और उसमें संघ व विहिप की भूमिका पर भी बात हुई।

पहले दिन संघ प्रमुख भागवत और सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने प्रांतों के पदाधिकारियों से चर्चा की। परेशानियां पूछीं और समाधान भी मांगा। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ संघ प्रमुख की अलग से चर्चा हुई। इस दौरान तीन बिंदुओं पर फोकस रहा। पहला, संबंधित राज्य में संघ को आ रही परेशानियों को जानना और समाधान, दूसरा संघ के विस्तार के लिए सालभर काम और तीसरा समाज में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए। असम, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के दौरे होंगे। शाखा संचालन और विस्तार के लिए लगातार काम होगा।

संघ सिर्फ बाढ़, भूकंप, सूखा या बड़े हादसे के दौरान ही सेवा कार्यों को सीमित नहीं रखेगा। समाज की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के निराकरण में भी संघ अहम भूमिका निभाएगा। देशभर में शाखाओं का ज्यादा विस्तार होगा। आदिवासी अंचल में नई शाखाएं शुरू होंगी। हर वर्ग को जोड़ा जाएगा। कार्य का विस्तार करेंगे। आम आदमी से सीधे जुड़ाव के लिए संघ परंपरा में बदलाव करने की सोच रहा है। ये बदलाव बड़े स्तर पर होंगे। संघ की अखिल भारतीय बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी सहित प्रमुख पदाधिकारियों ने देशभर के अलग-अलग राज्यों से आए प्रतिनिधियों से वन-टू-वन चर्चा की। इस दौरान हर प्रांत के लिए अलग रणनीति तय की गई और वर्षभर के आयोजनों पर मुहर भी लगी।

अब बेंगलुरु में होगी संघ की प्रतिनिधि सभा

इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंथन बैठक में तय हुए विषयों के प्रस्तावों पर अब प्रतिनिधि सभा में मुहर लगेगी, जो मार्च में बेंगलुरु में होगी। उस बैठक में राम मंदिर निर्माण, नागरिकता कानून, सामाजिक समरसता, पर्यावरण सहित अन्य मुद्दों पर व्यापक स्तर पर चर्चा होगी। अलग-अलग प्रांतों से प्रतिनिधि सभा में डेढ़ हजार से ज्यादा पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मंथन बैठक में नागरिकता कानून को लेकर जनजागरण करने की योजना तैयार की गई और उस पर तत्काल अमल करने को कहा गया। इसे देखते हुए मालवा प्रांत में **तीन स्थानों** पर नागरिकता कानून के समर्थन में तिरंगा मार्च भी निकाले गए। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी तैयारियों को लेकर भी संघ के प्रमुख पदाधिकारी अनुषांगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। संघ की बैठक में तय हुआ कि देश में हाल ही में जो भी निर्णय हुए हैं, उन्हें लेकर नकारात्मक माहौल न बने। ऐसा होने पर संघ सोशल इंजीनियरिंग के जरिए निर्णयों पर जनसमर्थन जुटाए। सामाजिक समरसता को लेकर भी संघ और सहयोगी संगठन विभिन्न आयोजन करेंगे।

बैठक में दूसरे दिन भाजपा की ओर से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। यह बात सामने आई है कि संघ प्रमुख भागवत और जोशी ने कुछ विषयों पर संतोष से अलग से चर्चा की। इस दौरान राम मंदिर, सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) और धारा 370 जैसे अहम मुद्दों पर सरकार के फैसलों की प्रशंसा की गई और कुछ सुझाव भी दिए गए। सूत्रों के मुताबिक, सीएए को लेकर संघ अब पूरी रणनीति और कार्ययोजना अपने हाथ में रखना चाहता है। वह इसे राष्ट्रवाद से जुड़ा मानकर देश के बड़े तबके को एकजुट करना चाहता है। यही वजह है कि भाजपा और केंद्र सरकार सीएए पर **जागरूकता** को लेकर जो काम कर रहे हैं, वह चलते रहेंगे, लेकिन संघ भी अपने स्तर पर स्वयंसेवकों के जरिए लोगों तक बात पहुंचाएगा।

भाजपा में बड़े बदलाव के संकेत भी मिले है। संघ की इंदौर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संघ नेताओं ने देश भर में भाजपा **राज्य प्रभारियों** की भूमिका पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के एक साल बाद भाजपा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के प्रभारियों को बदला जाएगा। इनमें मध्यप्रदेश भी शामिल है। इसके अलावा दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी बैठक में चर्चा की गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत के सात दिनी प्रवास और बैठकों के दौर के बाद एक बात बिलकुल स्पष्ट हो गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नए साल का पहला एजेंडा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) ही होगा। बैठकों में यूं तो प्रांतवार प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र के बारे में बात की गई, पर संघ ने पूरा ध्यान इस बिंदु पर केंद्रित किया, जिसे वह दशकों से अपना कोर मुद्दा मानता आया है। राम मंदिर, धारा 370 के बाद नागरिकता संशोधन कानून पर संगठन ने व्यापक जनसमर्थन जुटाने की योजना बनाई है। इसके तहत अब एक व्यक्ति के बजाय पूरे परिवार को जोड़कर यह बताया जाएगा कि सीएए देश के लिए क्यों जरूरी है। बीते 15 दिन से शाखाओं में भी चर्चा का यह बड़ा मुद्दा है।

● **विकास दुबे**

राहत पर भेदभाव

सीजन 2019 में देश के कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से खेती के साथ ही जानमाल की हुए भारी नुकसान की भरपाई में भी केंद्र सरकार मप्र से भेदभाव कर रही है। प्रदेश में 55 लाख किसानों की 60 लाख हेक्टेयर खरीफ की फसल खराब हुई थी। अतिवृष्टि की भरपाई के लिए मप्र सरकार ने केंद्र को 6621.28 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम भेजा था। लेकिन केंद्र ने अभी तक मप्र को दो किस्तों में 2,749 करोड़ रुपए ही दिया है।

गत दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से सात राज्यों के लिए 5908.56 करोड़ के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी। इस राशि में असम के लिए 616.13 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी, जबकि हिमाचल प्रदेश के लिए 284.93 करोड़ रुपए, कर्नाटक के लिए 1,869.85 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश के लिए 1,749.73 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र के लिए 956.93 करोड़ रुपए और त्रिपुरा के लिए 63.32 करोड़ रुपए तथा उत्तर प्रदेश के लिए 367.17 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश समेत चार राज्यों को 3200 करोड़ रुपए की अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की थी। इसमें महाराष्ट्र को 600 करोड़ और मध्यप्रदेश को 1000 करोड़ रुपए जारी किए थे।

बेमौसम बारिश और बाढ़ से मानसूनी सीजन में देश के कई राज्यों में खरीफ फसलों के साथ-साथ जानमाल को भारी नुकसान हुआ था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बाढ़ से खरीफ फसलों **खासकर** के सोयाबीन, कपास, मक्का के साथ ही बागवानी फसलों अंगूर और अनार आदि के साथ ही प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ था जिस कारण प्रभावित किसानों को आर्थिक कठिनाईयों का सामाना करना पड़ रहा है। मध्यप्रदेश में **अतिवृष्टि** की वजह से खरीफ फसलें प्रभावित हुई हैं। इससे प्रदेश में 55 लाख किसानों की 60 लाख हेक्टेयर में फसलें बर्बाद हुई हैं। फसलों की क्षतिपूर्ति, जान-माल और अधोसंरचना के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 6621.28 करोड़ रुपए की राहत राशि मांगी थी। इसके एवज में केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 को सिर्फ एक हजार करोड़ रुपए की राहत राशि ही भेजी थी। इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के किसानों की दुर्दशा व नुकसान का हवाला देकर कहा कि केंद्र से मदद की जरूरत है। केंद्र सरकार उदारता दिखाएं। उसके बाद गत दिनों फिर 1,749.73 करोड़ रुपए दिए।

मध्यप्रदेश में मानसून सामान्य से 46 फीसदी अधिक बारिश हुई है जिस वजह से धान को छोड़कर हर फसल पर अतिवर्षा का असर हुआ है। मध्यप्रदेश में अतिवर्षा और इस वजह से होने वाले जलजमाव और बाढ़ ने किसानों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। आधी से अधिक खरीफ की फसल चौपट होने के बाद प्रदेश के किसान अब बीमा कंपनी और सरकार की तरफ से मिलने वाले मुआवजे की राह देख रहे हैं। अगस्त महीने में खेतों में जल जमाव के बाद सोयाबीन और मक्के की फसल खराब होने की सूचना आने लगी थी, जिसके बाद मध्यप्रदेश सरकार ने फसलों के सर्वे के आदेश दिए थे। मध्यप्रदेश सरकार के आधिकारिक आंकड़ों की माने तो प्रदेश में खरीफ की 149.35 लाख हेक्टेयर फसल में से 60.52 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है। इससे लगभग 55.36 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। हरदा के किसान सेठी पटेल कहते हैं कि उनकी सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर और मक्के की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। धान की फसल से कुछ उम्मीद है। पटेल ने बताया कि सोयाबीन की फसल काटने के बाद उससे आमदनी होती थी जिससे वे गेंहू और चने की फसल लगाते थे, लेकिन इस बार खराब सोयाबीन की फसल हटाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। कई किसानों के पास पैसे न होने की वजह से सोयाबीन की खराब फसल खेतों में अभी भी लगी हुई है और कुछ किसान खेत साफ करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। मंडियों में इस समय सोयाबीन की आवक हो जाती थी और ट्रक के ट्रक सोयाबीन मंडियों में खड़े रहते थे, लेकिन इस साल स्थिति बदली हुई है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

फसल बीमा का 2301 करोड़ का भुगतान रोका

खरीफ वर्ष-2019 के लिए फसल बीमा का राज्यांश अग्रिम राशि 509.60 करोड़ रुपए का भुगतान बीमा कंपनियों को कर दिया है लेकिन केंद्र सरकार ने इस मद में भी राज्यांश की राशि 231 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक नहीं किया है। कृषि मंत्री ने कहा पिछली भाजपा सरकार ने बीमा कंपनियों को रबी सीजन 2017-18 में 165 करोड़, खरीफ-2018 में 1772 करोड़ तथा रबी सीजन 2018-19 में राशि 424 करोड़ रुपए यानी कुल 2301 करोड़ रुपए का राज्यांश राशि का भुगतान नहीं किया है। इसलिए इस साल हमें फसल बीमा का खरीफ-2019 का केंद्र का हिस्सा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। कृषि मंत्री ने बताया राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के समय का खरीफ 2018 के फ्लैट भावांतर योजना में मक्का फसल के लिए 2 लाख 60 हजार किसानों को 514 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। खरीफ 2017 के भावांतर के 576 करोड़, खरीफ 2018 के 321 करोड़ और अतिरिक्त 6 लाख मीट्रिक टन के 120 करोड़ अर्थात कुल 1017 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मप्र को अब तक नहीं दिए हैं।

राशन वितरण में अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि जनवरी 2020 से प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू की जा रही है। इस व्यवस्था में प्रदेश के उपभोक्ता देश के 11 राज्यों आन्ध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में भी अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, इन 11 राज्यों के उपभोक्ता मध्यप्रदेश में राशन ले सकेंगे। तोमर ने बताया कि इस योजना में उपभोक्ता राशन पूर्व निर्धारित मात्रा में पूर्व निर्धारित दर गेहूं 2 रुपए, चावल 3 रुपए और मोटा अनाज एक रुपए प्रति किलोग्राम पर प्राप्त कर सकेंगे।

मंत्री तोमर ने बताया कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अधिकाधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए अक्टूबर 2019 से प्रदेश में वन स्टेट-वन राशन योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस योजना को लागू करने पर अभी सिर्फ विचार कर रही है। तोमर ने बताया कि इस योजना में राशन उपभोक्ता एक शहर अथवा एक वार्ड से दूसरे शहर अथवा दूसरे वार्ड में भी राशन दुकान से निर्धारित मात्रानुसार निर्धारित दर पर राशन ले सकता है। इस योजना से आज प्रदेश के 117 लाख से अधिक परिवार के साढ़े पांच करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। मंत्री ने पिछले एक साल में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विकास के विशेष प्रयासों एवं नवाचारों की जानकारी देते हुए कहा कि राशन उपभोक्ताओं का हित संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है।

मंत्री ने बताया कि माह अक्टूबर, 2019 से प्रदेश में आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था लागू की गई है। इसमें पात्र परिवारों का सत्यापन बायोमेट्रिक के आधार पर किया जाकर राशन वितरण किया जा रहा है।

नर्मदा-कालीसिंध परियोजना से घर-घर पहुंचेगा पेयजल

लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास जिले में सोनकच्छ विकासखण्ड के ग्राम गंधर्वपुरी में आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम में बताया कि 4 हजार करोड़ लागत की नर्मदा-कालीसिंध लिंक परियोजना के जरिए गांव-गांव, घर-घर पाईप लाइन से पेयजल पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि नई सरकार ने क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए सबसे पहले यह परियोजना स्वीकृत की है। मंत्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में आम जनता के हित में काम कर रही है। यह सरकार लोगों के सुख-दुख में सदैव उनके साथ रहती है और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का गांव में ही निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई सरकार ने आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने के लिए हम कृत-संकल्पित हैं।

परिवहन माफिया के विरूद्ध की जाएगी कड़ी कार्यवाही

परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने परिवहन अधिकारियों से कहा है कि वह बिना किसी डर के परिवहन माफिया के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। राजपूत ने माफिया की चर्चा करते हुए कहा कि परिवहन विभाग में संगठित माफिया द्वारा अनेक अनियमितताएं किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं, जिनके द्वारा चेक-पोस्टों पर 500-500 अवैध गाड़ियों की निकासी कराने की जानकारी भी प्राप्त हो रही थी। यार्डों में खड़ी गाड़ियों पर करोड़ों का बकाया टैक्स भुगतान नहीं किए जाने की बात मेरे संज्ञान में आई है। राजपूत ने बड़ी संख्या में बहुत-सी वाल्वो एसी बस मालिक द्वारा विभिन्न त्योहारों पर यात्रियों से निर्धारित किराए से अधिक की राशि वसूल किए जाने तथा रेत और अन्य प्रकार की सामग्री की ओवर-लोडिंग पर भी रोक लगाना बहुत जरूरी है।

राजस्व वसूली में पीछे रहे अधिकारियों की जिलेवार समीक्षा करते हुए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि वर्ष 2019-20 में राजस्व वसूली का लक्ष्य 4 हजार करोड़ निर्धारित है। इसमें से अभी तक 2211 करोड़ राजस्व के रूप में प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले ढाई माह में अर्थात 31 मार्च तक 1689 करोड़ रुपए की बकाया वसूली की जाना सुनिश्चित करे। इसके लिए पूरा परिवहन अमला स्वयं नाकों पर उपस्थित रहें। उन्होंने राजस्व वसूली में श्योपुर एवं शिवपुरी जिले के परिवहन अमले की सराहना की जो प्रदेश में अभी तक राजस्व वसूली में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर है। मंत्री राजपूत ने कहा कि सबसे पहले चिन्हित वाहन मालिकों पर कार्यवाही करें, जिनसे बड़ी राशि की वसूली की जाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक विशेष दल गठित करें। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे, उन्हे 26 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही, काम के प्रति लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। राजपूत ने कहा कि राजस्व वसूली की रिपोर्ट के आधार पर गोपनीय चरित्रावली में मूल्यांकन दर्ज किया जाएगा।

रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार का मुख्य उद्देश्य

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने उज्जैन में डे-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों को हितलाभ वितरित किए। उन्होंने नगर निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं में चयनित 143 हितग्राहियों को 95 लाख 62 हजार रुपए के चेक वितरित किए। सिंह ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। मंत्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य शहर में स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि योजना में स्व-सहायता समूहों को 10 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सिंह ने कहा कि स्व-सहायता समूहों में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ें, जिससे वे आत्म-निर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि इंदौर की तरह उज्जैन में भी इच्छुक महिलाओं को ई-रिक्शा दिए जाएंगे।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों में सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नगरों में प्रतिदिन नल के माध्यम से पेयजल पहुंचाया जाएगा।

नदी, तालाब, कुओं के संरक्षण-संवर्धन की ठोस रणनीति बनाएं

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने जल भवन में जल जीवन मिशन क्रियान्वयन की कार्यशाला में कहा कि ग्रामीणों को घर तक नल से जल पहुंचाने की जिम्मेदारी को मिशन के रूप में निभाएं। उन्होंने कहा कि नदी, तालाब और कुओं के संरक्षण और संवर्धन की ठोस रणनीति बनाएं। पांसे ने कहा कि राज्य सरकार ने राईट टू वाटर एक्ट के जरिए सम्पूर्ण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की सार्थक पहल की है। इस मिशन का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों है।

पांसे ने अधिकारियों से कहा कि जल मिशन योजना के अन्तर्गत न सिर्फ लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो बल्कि योजनाओं से ग्रामीणों को दीर्घकालीन लाभ भी मिले। प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला ने कहा कि ग्रामीण परिवारों को गुणवत्तायुक्त पेयजल घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन बेहतर प्लानिंग से इसे सफल बनाया जा सकता है।

सांची में विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना होगी

भोपाल से कोलम्बो (श्रीलंका) सीधी विमान सेवा शुरू की जाएगी। सांची में विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना का काम जल्द शुरू किया जाएगा। प्रदेश के आध्यात्म मंत्री पीसी शर्मा की कोलम्बो में श्रीलंका सरकार के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धने के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिए गए। बैठक में महाबोधि सोसायटी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भिक्खु वानगल उपतिस्स नायक थेरो और मध्यप्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव उपस्थित थे। बैठक में श्रीलंका के विदेश मंत्री गुणवर्धने ने कहा कि भारत सरकार द्वारा भोपाल से कोलम्बो विमान सेवा शुरू करने की पहल स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका सरकार कोलम्बो से भोपाल के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा कि श्रीलंका से लाखों यात्री भोपाल और सांची जाते हैं। भोपाल-कोलम्बो के बीच डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी से लाखों लोगों को लाभ होगा। बैठक में आध्यात्म विभाग द्वारा सांची में विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान, भिच्छु प्रशिक्षण और बुद्धिस्ट चेन्टिंग सेंटर की स्थापना पर विस्तृत चर्चा हुई। विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान के प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया गया। बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान में बौद्ध दर्शन, बौद्ध विज्ञान, बौद्ध कला एवं संस्कृति और बौद्ध समारोह के साथ दुनिया के विभिन्न देशों में स्थित बौद्ध धर्म के तीर्थ, बौद्ध धर्म की परम्पराएं एवं बौद्ध धर्म को मानने वालों की जीवन और कला शैली को शामिल किया गया है। मंत्री शर्मा ने बताया है कि श्रीलंका के विदेश मंत्री गुणवर्धने ने प्रोजेक्ट को वित्तीय समर्थन देने की स्वीकृति प्रदान की है।

● अक्स टीम

300 करोड़ की टैक्स चोरी

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में कई विभागों की टीम ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) के नेतृत्व में गुटखा कंपनियों पर कार्रवाई की तो अधिकारी यह देखकर दंग रह गए कि वहां नियमों को ताक पर रखकर काम हो रहे थे। इनमें अनुमति से ज्यादा उत्पादन, टैक्स चोरी, मिलावट, बच्चों से काम कराना आदि पाए जाने पर केंद्र और राज्य सरकारों के सात विभागों को प्रकरण सौंपे गए हैं। इन कंपनियों द्वारा करीब 300 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करने का अनुमान लगाया जा रहा है। उधर, गोविंदपुरा में सील की गई एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना के बाद शक और बढ़ गया है।

गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू ने 10 जनवरी को अलसुबह भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में राजश्री, कमला पसंद और ब्लैक लेबल गुटखा के कारखाने पर कार्रवाई की। यहां करीब पांच करोड़ रुपए के गुटखे व पान मसाले की खेप रखी थी, जो देश के विभिन्न हिस्सों में जाने वाली थी। फैक्ट्रियों में मशीनों पर तेजी से उत्पादन हो रहा था। हर मशीन पर प्रति मिनट 1200 का उत्पादन किया जा रहा था, जबकि कंपनी को अनुमति केवल 450 रोटेशन प्रति मिनट की थी।

कंपनी इसके जरिए टैक्स की करोड़ों रुपए की चोरी कर रही थी। यहां करीब दर्जनभर बच्चे भी काम कर रहे थे। इसके साथ ही बिहार-जम्मू तथा अन्य क्षेत्रों के 500 कर्मचारी प्रदूषित वातावरण में काम करते हुए पाए गए। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड की कटौती में भी गड़बड़ी की आशंका जताई गई। फैक्ट्रियों में बिजली चोरी भी की जा रही थी। यही नहीं, गुटखे बनाने में इनके द्वारा तंबाकू की मिलावट भी की जा रही थी, जबकि तंबाकू पान मसाले में नहीं मिलाया जा सकता। इसके बाद ईओडब्ल्यू की इंदौर की टीम को वहां तीन कंपनियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए, मगर स्टाफ की कमी होने से केवल एक गुटखा कंपनी पर कार्रवाई हुई।

तमाम खामियां पाए जाने पर ईओडब्ल्यू ने स्वास्थ्य, खाद्य एवं औषधि, उद्योग, श्रम, वाणिज्यिक कर सहित जीएसटी-सीजीएसटी आदि को सूचना दी। गुटखा कंपनियों से तैयार माल व कच्चे माल में मिलावट तथा उनके गुणवत्ताहीन होने की आशंका के चलते नमूने एकत्रित किए, जिन्हें परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। ईओडब्ल्यू ने सभी विभागों से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है, जिससे अपराध पंजीबद्ध किया जा सके। प्रति मिनट उत्पादन में अनुमति से ढाई गुना से भी ज्यादा गुटखा बनाए जाने से सरकारों को करोड़ों की क्षति पहुंचाई जा रही थी।

ईओडब्ल्यू महानिदेशक सुशोभन बनर्जी का कहना है कि प्रदेश और जनहित के खिलाफ होने वाली गतिविधियों में संलग्न लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू द्वारा लगातार कार्रवाई की जाएगी। गुटखा कंपनियां न केवल सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचा रही थीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी कर रही थीं। यहां बच्चों से मजदूरी भी करवाई जा रही थी। ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई कर विभागों को मामला सौंप दिया है और उनकी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

राजश्री और कमला पसंद पान मसाला कंपनी के संचालक कमलकांत चौरसिया और शशिकांत चौरसिया की गोविंदपुरा स्थित फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई के बाद जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री में एक ही पान मसाले को राजश्री और कमला पसंद के पाउच में पैक किया जा रहा था। दोनों पान मसालों के दाम में भी काफी अंतर है। फैक्ट्री से फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने राजश्री और कमला पसंद पान मसाले के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। फूड सेफ्टी अमले के मुताबिक गुटखा फैक्ट्री में पान मसाले में मिलाने के लिए कुछ केमिकल्स रखे मिले हैं।

केमिकल्स का नाम पता करने राजश्री और कमला पसंद गुटखा के नमूने जांच के लिए फूड लेबोरेटरी भेजे गए हैं। जांच में सामने आया है कि कंपनी ने पिछले साल 500 करोड़ रुपए जीएसटी जमा किया था। आशंका है कि कंपनी द्वारा इतनी ही राशि की टैक्स चोरी की गई है। जांच में सामने आया है कि कंपनी ने टैक्स चोरी के लिए लंबे रास्ते की एक बिल्टी (बिल) पर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर की दो गाड़ियां चलाईं। इसमें एक गाड़ी का ही जीएसटी जमा करना पड़ा। वहीं, टैक्स चोरी के लिए एक रास्ता यह भी अपनाया गया था कि तीन से चार घंटे की दूरी तय करने में ट्रक को 48 घंटा का समय लगना बताया जाता था। इस अवधि में ट्रक एक ही बिल्टी पर पास की दूरी के चार से पांच चक्कर लगा लेता था। अब सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर गड़बड़ियों की जांच कर रहे हैं।

● **बृजेश साहू**

5 करोड़ की मिलावटी गुटखा सामग्री बरामद

राजधानी के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गुटखा कंपनियों के कारखानों में 5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का मिलावटी सामग्री और गुटखा बनाने की मशीनें बरामद की गई हैं। ईओडब्ल्यू एसपी अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि छापे में कंपनियों में लगभग 5 करोड़ रुपए कीमत का मिलावटी गुटखा पाया गया, जिसे देश के अलग-अलग स्थानों पर भेजने की तैयारी थी। एसपी ने यह भी बताया कि तीनों कंपनी में लगी मशीन में छेड़छाड़ कर तय सीमा से अधिक उत्पादन कर कंपनियों द्वारा टैक्स चोरी भी की जा रही थी। वहीं बिजली की चोरी करने का मामला भी सामने आया है। बिजली चोरी कर गुटखा कारखानों में दिन रात उत्पादन किए जाने की बात सामने आई है। बिजली चोरी कितनी हुई है, इसका पता लगाया जा रहा है। सरकार को शुद्ध के लिए युद्ध के तहत यह कोशिश करनी चाहिए कि वह पान-गुटखा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दे। क्योंकि इससे कैंसर होने की संभावना तो रहती ही है साथ ही गंदगी भी फैलती है। प्रदेश के कई शहर स्वच्छता में पान-गुटखा के कारण ही पिछड़ जाते हैं, क्योंकि लोग इन्हें खाकर गंदगी फैलाते हैं।

लैंड पूलिंग एक्ट की तैयारी

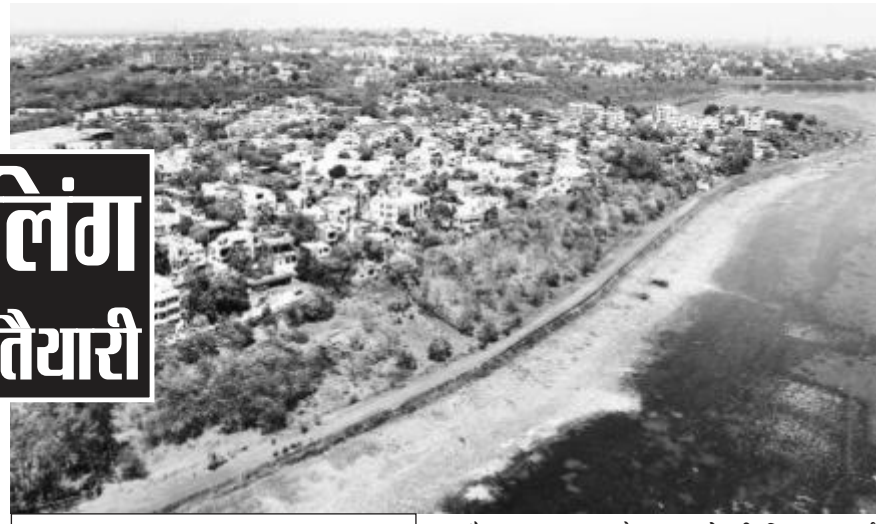

प्रदेश के प्राधिकरणों की कार्यशैली अब बदलेगी। सरकार ने प्रदेश के लिए लैंड पूलिंग एक्ट तैयार किया है। प्रदेश में तैयार हुआ लैंड पूलिंग का मॉडल अहमदाबाद की तर्ज पर तैयार हुआ है। शासन ने लैंड पूलिंग एक्ट तो बना दिया है। अब नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्रालय द्वारा उसके आधार पर नियम बनाए जा रहे हैं। भोपाल सहित सभी प्राधिकरणों के अधिकारियों से भी इस संबंध में सुझाव मांगे गए हैं।

कमलनाथ सरकार ने लैंड पूलिंग एक्ट लागू तो कर दिया है, मगर उसके नियम अभी नहीं बन सके है। इसके चलते एक्ट पर अमल किस तरह किया जाएगा, वह नियमों से ही तय होगा। लैंड पूलिंग एक्ट के चलते प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड योजनाएं घोषित करने के बाद 50 प्रतिशत जमीन मालिकों को वापस लौटा देगा और 30 प्रतिशत जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और 20 प्रतिशत जमीन प्राधिकरण के पास रहेगी, जिसे वह भूंखडों के रूप में बेच सकेगा। अलग-अलग योजनाओं में प्राधिकरण ने 20 से लेकर अधिकतम 33 प्रतिशत तक विकसित भूखंड दिए हैं।

वैसे तो भोपाल-इंदौर जैसे शहरों में लैंड पूलिंग एक्ट का फायदा किसानों या जमीन मालिकों को ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी प्राधिकरण जो विकसित भूखंड देता है वह अधिक फायदेमंद है, इसमें जमीन मालिकों को न तो कोई विकास कार्य करना पड़ता है और न कॉलोनाइजर लाइसेंस लेने से लेकर अन्य अनुमतियां लेना पड़ती है। मगर अब 50 प्रतिशत जमीन में अंदरूनी विकास जिसमें सड़क, ड्रैनेज, पानी या अन्य सुविधाएं जमीन मालिक को ही जुटानी पड़ेगी। भोपाल सहित प्रदेशभर के प्राधिकरणों की लगभग 86 योजनाएं लैंड पूलिंग एक्ट के दायरे में आ रही है। इनमें से 66 योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें 10 प्रतिशत से भी कम विकास कार्य हुए हैं।

इंदौर विकास प्राधिकरण का गठन मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिए हुआ था, लेकिन योजनाएं विकसित करने के साथ अफसरों ने प्लॉट विकसित करने और आवासीय व कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। ऐसे में योजनाएं लागू करने में परेशानी आने लगी। आईडीए जिस मास्टर प्लान रोड का निर्माण करने की तैयारी करता, उसके 150 से 300 मीटर के दायरे की जमीन को भी योजना में शामिल कर लेता था। कोर्ट केस के कारण कई बार आईडीए को भूमि अधिग्रहण में परेशानी भी आती थी। नए लैंड पूलिंग एक्ट में अहमदाबाद मॉडल की तरह योजनाएं घोषित करने के बाद आईडीए का जोर 18 से 30 मीटर चौड़ाई की सड़कों के निर्माण पर ज्यादा रहेगा। उस सड़क का लाभ जिसे मिलेगा, उससे तय प्रतिशत के तहत जमीन ली जाएगी। जमीन मालिकों को भी उसी स्कीम में जमीन दी जाएगी। ऐसा होने पर जमीन मालिक को भी प्राधिकरण से समझौता करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी और विकास के काम भी जल्दी हो जाएंगे। एक्ट लागू होने के बाद आईडीए की करीब आठ योजनाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वर्षों से उन योजनाओं में विकास कार्य नहीं हो पाए। अभी एक्ट का नोटिफिकेशन आना बाकी है। मास्टर प्लान के तहत जो भी विकास कार्य होने हैं, उन्हें पूरा करने पर हमारा फोकस रहेगा।

गुजरात में विकास कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए प्राधिकरणों को ज्यादा शक्तियां दे रखी हैं। शहर के जिस हिस्से में सड़क निर्माण करना हो, वहां प्राधिकरण को जमीन लेने में ज्यादा परेशानी नहीं आती है। सरकार हर स्कीम के लिए एक प्लानर नियुक्त करती है। वह सुनवाई करता है, उसके बाद सरकार भी सुनवाई करती है। जिस हिस्से में सड़क, उद्यान आदि का निर्माण करना हो, उसे काले रंग से नक्शे में दर्शाया जाता है और जो हिस्सा जमीन मालिकों को दिया जाना होता है, उसका रंग लाल होता है। ऐसे में जमीन मालिकों को भी बार-बार कार्यालयों के ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं।

शासन द्वारा लाए जा रहे लैंड पूलिंग एक्ट पर जल्द ही अमल होगा। विधानसभा से मंजूरी के बाद अब शासन इसका गजट नोटिफिकेशन करेगा, फिर नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय से नियम बनेंगे। तत्पश्चात प्राधिकरण की लगभग 10 योजनाएं छूटेंगी, लेकिन 6 माह तक किसी तरह के नक्शे मंजूर नहीं होंगे। तब तक प्राधिकरण नए एक्ट के मुताबिक योजनाओं का नोटिफिकेशन करा सकेगा। किसानों या जमीन मालिकों को हालांकि इस नए लैंड पूलिंग एक्ट से अधिक फायदा नहीं होगा। उल्टा प्राधिकरण की विकसित भूखंड की नीति अधिक कारगर है। अभी जिन दो योजनाओं में प्राधिकरण अनुबंध कर चुका है उनके संबंध में भी नए सिरे से जमीन मालिकों से चर्चा की जाएगी। अंदरूनी सड़कों के साथ-साथ अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जिनमें बिजली, पानी, ड्रेनेज या अन्य की व्यवस्थाएं खुद जमीन मालिकों को ही करना पड़ेंगी। इसके चलते उन्हें तमाम विभागों में चक्कर काटना होंगे, जबकि अभी प्राधिकरण पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद तैयार करके देता है, जिस पर सिर्फ नक्शा मंजूर कराकर काम शुरू कराना ही शेष रहता है।

● **नवीन रघुवंशी**

योजना में ये होंगे प्रावधान

जानकारी के मुताबिक लैंड पूलिंग एक्ट में 50 प्रतिशत जमीन इसके मूल मालिक को लौटाई जाएगी और शेष 50 प्रतिशत में से 20 प्रतिशत जमीनों का उपयोग मास्टर प्लान या अन्य प्रमुख सड़कों के निर्माण पर होगा और 10 प्रतिशत जमीन हरियाली के लिए रहेगी। बची 20 प्रतिशत जमीन प्राधिकरण बेचकर सड़क व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गई राशि निकालेगा। जो योजनाएं अभी लैंड पूलिंग एक्ट के चलते समाप्त होंगी, उनमें एक्ट के ही मुताबिक 6 माह तक किसी तरह के नक्शे मंजूर नहीं होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि प्राधिकरण से योजनाएं छूटते ही जमीन मालिक पहले नगर तथा ग्राम निवेश से अभिन्यास और फिर नगर निगम से भवन अनुज्ञा हासिल कर ले। 6 माह का समय प्राधिकरण को नए एक्ट के तहत योजनाएं घोषित करने का मिलेगा, जिसमें 3 अलग-अलग स्टेज पर योजना घोषित होगी। पहली स्टेज पर प्रारंभिक नोटिफिकेशन, दूसरी स्टेज पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन और तीसरी स्टेज पर शासन की मंजूरी के बाद फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा।

एससी-एसटी एक्ट के अमल में मप्र अग्रणी

विगत दिनों सांची के होटल गेटवे रिट्रीट में 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता' विषय पर दो दिवसीय पुलिस अधिकारियों की राज्य स्तरीय सेमीनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस अधिकारी मानवीय गुणों का परिचय देकर उनके मददगार बनें, जो उपेक्षित हैं और प्रगति के दौर में पिछड़ गए हैं। ऐसे लोगों की मदद किसी पुण्य से कम नहीं। डीजीपी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अमल में राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश के अग्रणी रहने पर खुशी जाहिर की और अतिरिक्त पुलिस

महानिदेशक अजाक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव एवं उनकी टीम को बधाई दी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अजाक शाखा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने कहा अजा एवं अजजा वर्ग से संबंधित प्रकरणों के विवेचक एवं पर्यवेक्षकों को व्यवहारिक रूप से दक्ष बनाने के लिए अजाक शाखा द्वारा साल में दो बार इस प्रकार की सेमीनार आयोजित की जातीं हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि उनके कार्य-व्यवहार में अजा एवं अजजा के प्रति संवेदनशीलता झलकना चाहिए।

समापन कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आपदा प्रबंधन डी सी सागर, उप पुलिस महा निरीक्षक अजाक आई पी अरजरिया व पुलिस अधीक्षक रायसेन मोनिका शर्मा भी मौजूद थीं। कार्यक्रम का संचालन सहायक पुलिस महानिरीक्षक अजाक विजय खत्री ने किया।

गांव पहुंच पुलिस ने किया जनता से सीधा संवाद

पुलिस और जनता के बीच सकारात्मक समझ विकसित करने के मकसद से गत दिनों पुलिस अधिकारियों ने रायसेन जिले के अनुसूचित-जाति बहुल ग्राम गुलगांव के निवासियों से सीधा संवाद स्थापित किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक **अजाक** प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री कमल नाथ की मंशानुसार कार्यक्रम को गुलगांव में किया गया है। मकसद यह है कि योजनाओं में मिलने वाले तमाम अधिकार संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचें और वे इसका लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि आमतौर पर घटना-दुर्घटना या कोई भी समस्या होने पर जन-सामान्य पुलिस को ही अवगत कराते हैं और पुलिस भी उनकी लगातार मदद करने का प्रयास करती है।

रायसेन जिला कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कहा कि गुलगांव एक आदर्श गांव है। सामाजिक समरसता का उदाहरण है। यहां हर फैसले आपसी सहमति से हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सभी वर्गों का उत्थान करना है। पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति, उनके आश्रितों, साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण-पोषण व्यय, परिवहन सुविधाएं सहित अनुसूचित जाति-जनजाति संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया। डीआईजी आईपी अरजरिया भी कार्यक्रम में मौजूद थे। सरपंच बाबूलाल अहिरवार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने महिला शक्ति पर कविता भी सुनाई। इस अवसर पर ग्रामवासियों के अलावा बड़ी संख्या में जिले के अधिकारी भी उपस्थित थे।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करें

डीजीपी विजय कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों से चर्चा करते हुए दिशा-निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार महिला अपराधों की तत्परता से विवेचना की जाए। महिलाओं से संबंधित अपराधों में एफआईआर दर्ज करने में कदापि देरी न हो, जो पुलिस अधिकारी व कर्मचारी एफआईआर कायम करने में देरी करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस मुख्यालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में एडीजी महिला अपराध अन्वेष मंगलम, एडीजी अपराध अनुसंधान विभाग राजीव टंडन सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

सिंह ने निर्देश दिए कि पुलिस मुख्यालय द्वारा महिला अपराधों के संबंध में जारी की गई एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का पालन कराएं। उन्होंने जोर देकर महिला संबंधी अपराधों में प्रोफेशनल पुलिसिंग के जरिए साक्ष्य जुटाएं, जिससे न्यायालय में अपराधी को सजा मिल सके। सिंह ने पीड़ित के साथ **संवेदनशील** एवं सहयोगात्मक व्यवहार करने पर भी विशेष बल दिया। साथ ही कहा कि पुलिस थानों को महिला फ्रेंडली बनाएँ अर्थात थानों में महिलाओं के लिए सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। पुलिस महानिदेशक ने महिला पुलिस बल का युक्ति-युक्तिकरण कर सभी पुलिस थानों में महिला पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की पदस्थापना सुनिश्चित की जाए, जिससे महिला अपराधों की विवेचना में देरी न हो।

कचरे से करोड़ों की कमाई

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में अव्वल रहकर लगातार चौथी बार देश के सबसे साफ-सुथरे शहर का खिताब हासिल करने के लिए जोर लगा रहे इंदौर में कचरा अब कीमती चीज बन गया है। नगरीय निकाय ने अलग-अलग तरीकों से कचरे के प्रसंस्करण का नवाचारी मॉडल तैयार किया है जिससे उसे हर साल तकरीबन चार करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। उन्होंने बताया कि कोई 35 लाख की आबादी वाले इंदौर में हर रोज तकरीबन 1,200 टन कचरे का अलग-अलग तरीकों से सुरक्षित निपटारा किया जाता है। इसमें 550 टन गीला कचरा और 650 टन सूखा कचरा शामिल है।

केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के लिए इंदौर नगर निगम के सलाहकार असद वारसी के मुताबिक पीपीपी मॉडल के आधार पर एक निजी कम्पनी ने शहर में 30 करोड़ रुपए के निवेश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त ऑटोमेटिक प्रसंस्करण संयंत्र लगाया है। देश में संभवत: अपनी तरह के इस पहले संयंत्र में हर दिन 300 टन **सूखे कचरे** का प्रसंस्करण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोई 35 लाख की आबादी वाले इंदौर में रोज तकरीबन 1,200 टन कचरे का निपटारा किया जाता है, इसमें 550 टन गीला कचरा और 650 टन सूखा कचरा शामिल है।

वारसी ने बताया कि रोबोटिक प्रणाली वाले इस संयंत्र की खासियत ये है कि इसका सेंसर सूखे कचरे को छांट कर अलग कर देता है। प्रसंस्करण के बाद सूखे कचरे में से कांच, प्लास्टिक, कागज, गत्ता, धातु आदि पदार्थ अलग-अलग बंडलों के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इस संयंत्र के लिए आईएमसी ने 4 एकड़ जमीन दी है। उन्होंने बताया कि इस जमीन पर संयंत्र लगाने के अलावा इंदौर में और कोई वित्तीय निवेश नहीं किया है, हालांकि एग्रीमेंट के मुताबिक, संयंत्र लगाने वाली निजी कम्पनी कचरे के प्रसंस्करण से होने वाली आय में से आईएमसी को हर साल 1.51 करोड़ रुपए का प्रीमियम देगी।

इंदौर नगर निगम के सलाहकार असद वारसी ने बताया कि आईएमसी गीले कचरे के प्रसंस्करण से कम्पोस्ट खाद और बायो सीएनजी ईंधन बना रहा है। इसके अलावा मलबे से ईंटें, इंटरलॉकिंग टाइल्स और अन्य निर्माण सामग्री बनाई जा रही है। इन सभी उत्पादों की बिक्री से शहरी निकाय को कुल 2.5 करोड़ रुपए की सालाना कमाई हो रही है। उन्होंने बताया कि 3 गैर सरकारी संगठनों को घर-घर से सूखा कचरा इकट्ठा करने का जिम्मा सौंपा गया है। पहले चरण में ये गैर सरकारी संगठन शहर के करीब 22,000 घरों से सूखा कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। घर के मालिकों को हर एक किलोग्राम सूखे कचरे के बदले एनजीओ की ओर से 2.5 रुपए का भुगतान किया जा रहा है।

कुछ माह पहले तक देवगुराड़िया क्षेत्र स्थित जिस ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास से गुजरने पर भी बदबू की वजह से निकलना दूभर हो जाता था वहां अब हरियाली लहलहा रही है। कचरे के विशालकाय पहाड़ों को वैज्ञानिक विधि से हटाने के बाद अब नगर निगम करीब 100 एकड़ क्षेत्र में पौधारोपण में जुटा है। अब तक हजारों पौधे रोपे जा चुके हैं। इसके अलावा लैंडफिल साइट को इतना आकर्षक बनाया गया है कि लोग आकर वहां आराम से घूम सकें। कुछ साल पहले तक ट्रेंचिंग ग्राउंड क्षेत्र के आसपास गांव और कालोनियों के रहवासी कचरे की बदबू से परेशान थे। बदबू के साथ ही आए दिन कचरे में लगने वाली आग से होने वाले प्रदूषण से पूरा इलाका दूषित था। यहां तक कि इलाके के बोरिंग में आने वाला पानी भी दूषित होने लगा था। स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरी बार नंबर वन की कवायद के दौरान नगर निगम की टीम ने ट्रेंचिंग ग्राउंड पर तीस चालीस वर्ष से जमे कचरे के निस्तारण की योजना तैयार की। इस प्रक्रिया में गीले और सूखे कचरे को वैज्ञानिक विधि से अलग किया गया। अंतिम स्तर तक मिट्टी की जांच की गई कि कहीं उसमें हानिकारक केमिकल या मैटल आदि को मिले नहीं है। जांच रिपोर्ट सकारात्मक मिलने के बाद ट्रेंचिंग ग्राउंड पर सिटी फारेस्ट बनाने की योजना को मंजूरी दी गई।

● **विशाल गर्ग**

100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सिटी फॉरेस्ट

ट्रेंचिंग ग्राउंड कुल 159 एकड़ में फैला है। कचरे के पहाड़ हटने के बाद खाली हुई 100 एकड़ जमीन पर सिटी फॉरेस्ट तैयार करने की योजना तैयार कर ली गई। बीते मानसून के पहले ही 11 हजार पौधे लगाने और इनकी संख्या बढ़ाकर 40 हजार करने का लक्ष्य रखा गया। बारिश के बाद भी पौधारोपण का कार्य लगातार जारी है। अब लक्ष्य पूरे ट्रेंचिंग ग्राउंड पर एक लाख पौधे लगाना है। निगम के उद्यान अधिकारी कैलाश जोशी के अनुसार ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बनाए गए सिटी फारेस्ट में बड़, पीपल, शीशम, कचनार, करंज और मोरसली जैसे पौधे लगाए गए हैं। दो साल तक इनकी विशेष देखभाल करना होगी इसके बाद ये खुद-ब-खुद बढ़ने लगेंगे। इसके अलावा सिटी फॉरेस्ट में बगीचे भी बनाए जा रहे हैं जहां लोग घूमने आ सकेंगे। निगम ने ट्रेंचिंग ग्राउंड पर ड्राय वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी शुरू किया है। निजी कंपनी ने 15 करोड रुपए खर्च कर इस प्लांट को लगाया है। कंपनी इस प्लांट के माध्यम से हर दिन 300 टन सूखा कचरा प्रोसेस हो सकता है। इससे निगम को भी हर साल डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा की आय होगी।

बढ़ रहा वनों का दायरा

हर 50 मीटर की दूरी पर एक पेड़ जरुरी

पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. प्रभात सोनी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार पर्यावरण संतुलन के लिए प्रति व्यक्ति 4 पेड़ होना आवश्यक है। एक स्वस्थ पेड़ से सात लोगों को प्राण वायु मिल पाती है। यदि हम इसके आसपास कचरा जलाते हैं तो इसकी ऑक्सीजन उत्सर्जित करने की क्षमता आधी हो जाती है। इस तरह हम तीन लोगों से उनकी जिंदगी छीन लेते हैं। इसके अलावा किसी भी स्थान पर 50 मीटर की दूरी पर एक पेड़ जरूर होना चाहिए। इससे वहां के रहवासियों को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध हवा मिलेगी और लोग स्वस्थ रहेंगे।

जंगलों से खुशखबरी आई है। देश में वन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। इसका खुलासा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार दो साल में पांच हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र फैल गया है। इसमें वन क्षेत्र और वन से इतर पेड़ों को भी हरित क्षेत्र में शुमार किया गया है। देश के कुल वन क्षेत्र का दायरा 21.67 फीसदी हो गया है। वर्ष 2014 से 2019 की पांच साल की अवधि में देश के वन क्षेत्र में 13 हजार वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। इस दौरान सघन वन क्षेत्र और विरल वन क्षेत्र समेत सामान्य वन क्षेत्र की श्रेणियों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है जो अकेले भारत में संभव हो सका है।

इस रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रदेश के 50 जिलों में से 25 में वनक्षेत्र दो साल में कम हुआ और 25 में बढ़ा है। बताने की जरूरत नहीं कि इन जिलों में **वन माफिया** और वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की गई है। वहीं मध्य प्रदेश के 25 जिले ऐसे भी हैं जहां वन क्षेत्र बढ़ा है। कहने की जरूरत नहीं कि यहां का जंगल वन विभाग के अच्छे अधिकारियों के हाथ में रहा।

सबसे ज्यादा जंगल सीहोर जिले में कटे हैं। जंगल कटने की सूची में वनमंत्री उमंग सिंघार का गृहजिला धार भी शामिल है। वहीं पन्ना में सबसे ज्यादा वनक्षेत्र बढ़ा है। उज्जैन ऐसा जिला है जहां कुल क्षेत्रफल का एक प्रतिशत भी जंगल नहीं है। यहां जंगल सिर्फ 0.59 प्रतिशत जमीन पर है। उज्जैन ऐसा जिला है जहां कुल क्षेत्रफल का एक प्रतिशत भी जंगल नहीं है। यहां जंगल सिर्फ 0.59 प्रतिशत जमीन पर है। 10 जिलों में वनक्षेत्र 10 प्रतिशत से कम है और 17 में 20 प्रतिशत से कम। सिर्फ 2 जिलों में 50 प्रतिशत से ज्यादा। ये दो जिले बालाघाट और श्योपुर हैं। 10 जिलों में वनक्षेत्र 10 प्रतिशत से कम है और 17 में 20 प्रतिशत से कम। सिर्फ 2 जिलों में 50 प्रतिशत से ज्यादा। ये दो जिले बालाघाट और श्योपुर हैं। 10 प्रतिशत से कम वन वाले जिलों में झाबुआ भी शामिल है। 35 प्रतिशत से ज्यादा जंगल वाले जिले मात्र 10 हैं। इसरो के सेटेलाइट से मिले आंकड़ों से ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसके पहले साल 2017 में रिपोर्ट आई थी। दो सालों में प्रदेश में 68.49 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़े हैं। प्रदेश में 25.14 प्रतिशत जंगल है। 2017 में ये 25.11 प्रतिशत थे। 17 जिलों में वेरी डेंस फॉरेस्ट (अधिक घनत्व वाले जंगल) नहीं है। आलीराजपुर और झाबुआ भी इस श्रेणी में रखे गए हैं।

इसरो के सेटेलाइट से मिले आंकड़ों से ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसके पहले साल 2017 में रिपोर्ट आई थी। दो सालों में प्रदेश में 68.49 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़े हैं। प्रदेश में 25.14 प्रतिशत जंगल है। 2017 में ये 25.11 प्रतिशत थे। 17 जिलों में वेरी डेंस फॉरेस्ट (अधिक घनत्व वाले जंगल) नहीं है। आलीराजपुर और झाबुआ भी इस श्रेणी में रखे गए हैं। दमोह जिले में हर साल लाखों की संख्या में पौधरोपण किया जा रहा है, इसके बावजूद भी वन क्षेत्र बढ़ने की बजाय घट रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में दमोह जिले में 2606 वर्ग किलोमीटर के जंगल थे, जो वर्ष 2017 में 2594 वर्ग किलोमीटर के बचे हैं। वर्ष 2019 में 2587 वर्ग किलोमीटर का जंगल बचा हुआ है। दो साल में 7 वर्ग किमी जंगल कम हो गया है। दमोह जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 730600.00 हेक्टेयर है, जिनमें कुल 248981.81 हेक्टेयर क्षेत्र में अर्थात 35.41 प्रतिशत वनक्षेत्र है। वन विभाग के पास एक बड़ा मैदानी अमला भी पदस्थ है, जिस पर जंगलों को बचाने की पूर्ण **जिम्मेदारी** है, इसके बावजूद भी जिले में वन क्षेत्र घटना चिंता का विषय है। हैरानी की बात है कि वन विभाग द्वारा हर साल जिलेभर में 10 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जाता है, लेकिन यदि इतनी अधिक संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं तो फिर वन क्षेत्र में कमी क्यों आ रही है। जबकि पड़ोसी जिले पन्ना एवं छतरपुर में वन क्षेत्र में इजाफा हुआ है।

एक समय था जब प्रदेश की हर सड़क किनारे बड़े-बड़े पेड़ हुआ करते थे, जिससे बाहर से आने वाले लोग पेड़ों की छांव में खड़े होकर तेज धूप से राहत महसूस करते थे, लेकिन सड़कों के चौड़ीकरण एवं शहरीकरण के विस्तार के चलते अधिकांश पेड़ गायब हो गए हैं। स्थिति यह है कि अब अधिकांश सड़क पर पेड़ नहीं बचे हैं। हालांकि मिशन ग्रीन एवं वन विभाग की ओर से पौधे लगाए गए हैं, लेकिन अभी वह विकसित हो रहे हैं।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

विकास का रोडमैप

कहावत है बूंद-बूंद से घड़ा भरता है। अगर देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र में बुंदेलखंड में बूंद-बूंद की मानिंद विकास हुआ होता तो आज यह क्षेत्र इतना बदहाल नहीं होता। हालांकि क्षेत्र के विकास के लिए मप्र और उप्र की सरकारें कुछ खास सक्रिय नजर आ रही हैं। वहीं केंद्र सरकार को भी ध्यान इस क्षेत्र के विकास पर केंद्रित हो रहा है। इसके लिए रोडमैप बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने मध्यप्रदेश के सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग को आपस में जोड़कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग एएसआई का सर्किल कार्यालय सागर में बनाने के संकेत दिए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव तैयार कराकर संस्कृति सचिव के पास भिजवाया है। यदि सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो प्रदेश में भोपाल के बाद सागर ऐसा संभाग होगा, जिसमें सर्किल कार्यालय होगा और यहां से 4 संभागों के 21 जिलों के पुरातात्विक स्थलों की मॉनीटरिंग की जाएगी।

बता दें कि सागर में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का सब सर्किल कार्यालय है। यहां के सारे काम भोपाल से होते हैं। प्रदेश के जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल संभाग में सर्किल कार्यालय नहीं हैं। जिससे प्राचीन स्थलों की देखरेख और उनके संरक्षण को लेकर गंभीरता से काम नहीं हो पाता है। अनदेखी के चलते कई स्थल जमींदोज हो रहे हैं और भारी नुकसान होने के बाद भी उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। इन स्थलों को संरक्षित करने और उनकी नए सिरे से कार्ययोजना बनाने के लिए अमले की कमी पड़ रही है, इन समस्याओं को देखते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सर्किल कार्यालय स्थापित करने को लेकर निर्णय लिया है।

सागर के सब सर्किल कार्यालय में पदस्थ संरक्षण सहायक राहुल तिवारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इसका प्रस्ताव मांगा है और इसकी जानकारी भी संस्कृति सचिव के पास भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि सर्किल कार्यालय बनने पर जो काम अभी तक भोपाल में होते हैं, वे सागर में होने लगेंगे। प्राचीन स्थलों की देखरेख, उनके सुधार कार्य और संरक्षण को लेकर जल्द काम किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि मंजूरी मिलने पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) का सर्किल कार्यालय सागर में बनेगा और यहां से एएसआई 21 जिलों पर नजर रखेगा। इसके लिए जमीन चिह्नित की जा रही है और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से इसका नक्शा तैयार कराया जा रहा है। मुख्यालय से अप्रूवल मिलते ही कार्यालय निर्माण का काम शुरू हो जाएगा।

मंजूरी मिलने पर प्रदेश में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का यह दूसरा सर्किल सागर होगा। पहला भोपाल में सर्किल है। अभी सब सर्किल सागर है, जहां पर केवल संरक्षण सहायक (सिविल इंजीनियर) स्तर के अधिकारी ही बैठते थे, लेकिन सर्किल बनने के बाद यह क्षेत्र सुपरिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट और अधीक्षण पुरातत्वविद् की मॉनीटरिंग में आ गया है। सर्किल कार्यालय बनने के बाद सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल तक करीब 21 जिलों के पुरातात्विक स्थलों की मॉनीटरिंग सागर के सर्किल कार्यालय से होगी। इस तरह बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल आपस में जुड़कर एक सर्किल में आ जाएंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि सारे प्राचीन स्थल सागर सर्किल से जुड़ते हैं। इस रूट को देखते हुए कार्ययोजना बनाई जा रही है। अभी सागर सब सर्किल कार्यालय है। प्रस्ताव तैयार किया गया है। सभी मंत्रालयों से स्वीकृति मिलने के बाद इस पर निर्णय होगा।

मोदी सरकार ने देश को 2 डिफेंस कॉरिडोर दिए। इसमें से एक की सौगात बुन्देलखंड की झोली में डाली गई। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार ने 430.31 करोड़ के बजट में सर्वाधिक 328 करोड़ रुपए झांसी जनपद के लिए स्वीकृत किए, जबकि चित्रकूट को 50 करोड़ व अलीगढ़ को 52.31 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। यह परियोजना जब पूरी तरह से आकार लेगी, तो युवाओं के लिए रोजगार के ढेरों अवसर खुलेंगे।

● **सिद्धार्थ पांडे**

देश के विकास का मॉडल बनेगा बुंदेलखंड

अपनी तमाम विशेषताओं के बावजूद सूखा, गरीबी, पलायन और पिछड़ेपन के लिए चर्चित बुंदेलखंड अब नकारात्मक धारणा से बाहर निकल रहा है। सिर्फ जलसंरक्षण का जखनी मॉडल ही नहीं बल्कि अन्य अभियानों की गूंज भी केंद्र सरकार तक पहुंच चुकी है। ग्राम्य विकास मंत्रालय बुंदेलखंड मॉडल के आधार पर देशभर में विकास कराने की योजना बना रहा है। इसी सिलसिले में आईआईएम रांची के प्रोफेसर डॉ. नितिन को इन योजनाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। बीते दो दशक में लगातार सूखे की मार और राजनीति ने बुंदेलखंड के असल स्वरूप को कहीं पीछे छोड़ दिया है। देश में इस इलाके की पहचान गरीबी और पिछड़ेपन के रूप में हो रही है। बुंदेलखंड के माथे से इस दाग को मिटाने के लिए जिलाधिकारी हीरालाल ने पहल शुरू की। एक-दो नहीं बल्कि पांच ऐसे अभियान छेड़े जो राष्ट्रीय फलक पर चमक उठे। केंद्र सरकार ने इस सकारात्मक पहल का स्वागत किया। बकौल प्रो. नितिन वास्तव में बुंदेलखंड में अब सामाजिक बदलाव दिखने लगा है। जल संरक्षण के प्रति लोगों की अवधारणा बदल रही है। खेती-किसानी के प्रति भी लोगों में अब दिलचस्पी बढ़ी और और मजदूरों का पलायन कम हो रहा है।

मप्र में करीब 20 साल बाद निकायों के महापौर और अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। यानि पार्षद महापौर और अध्यक्ष चुनेंगे। साथ ही इस बार पार्षदों का चुनाव पार्टियों के चुनाव चिन्ह के बिना होगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि महापौर और अध्यक्ष के लिए धनबल, बाहुबल का सहारा लिया जाएगा। यानि अबकी बार जुगाड़ू पार्षद ही महापौर बन पाएगा।

● राजेंद्र आगाल

मप्र में वक्त है बदलाव के नारे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस ने अपने एक साल के कार्यकाल में कई बदलाव किए हैं। लेकिन सबसे अधिक विवाद नगरीय निकायों में महापौर या अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने को लेकर हुआ है। मामला राज्यपाल से लेकर हाईकोर्ट तक सुर्खियों में बना रहा। अंततः सरकार के पक्ष में निर्णय हुआ है कि नगरीय निकायों में अब महापौर या अध्यक्ष को जनता नहीं बल्कि पार्षद चुनेंगे। यानी कि जनता को वोटिंग के माध्यम से महापौर चुनने का जो हक था, वो अब नहीं होगा। ऐसे में भाजपा द्वारा महापौर चुने जाने के बीच कई संभावनाएं व आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष में है, ताकि वह धनबल, बाहुबल और सरकार के दबाव के दम पर नगर निगमों में अपने महापौर बैठा सके। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसीलिए कानून में परिवर्तन किया है, ताकि वे पार्षदों की खरीद-फरोख्त करके अपना महापौर बना सके।

20 साल पुराने नियम में बदलाव

वर्ष 2000 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने मध्यप्रदेश में महापौर एवं नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराने का फैसला लिया था। तब से लेकर अब तक प्रदेश में महापौर एवं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता आ रहा था। इस दौरान किसी भी चुनाव में किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिर सरकार ने उस प्रावधान को बदलने का निर्णय क्यों लिया, जिसे उनकी ही पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने आज से 20 साल पहले लागू किया था। इस संदर्भ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि कांग्रेस इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष में है, ताकि वह धनबल और बाहुबल के दम पर नगर निगमों में अपने महापौर बैठा सके।

वहीं भाजपा के एक प्रदेश प्रवक्ता कहते हैं कि इतिहास रहा है जब कभी भी अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हुआ है, खरीद-फरोख्त बढ़ी है। इस प्रणाली से महापौर-अध्यक्षों का चुनाव कराने से मर्यादाओं का स्थान पैसा लेगा। यह प्रजातंत्र की हत्या करने जैसा है। वे सवाल उठाते हैं कि अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव की व्यवस्था विवादित नहीं रहती तो वर्ष 2000 में दिग्विजय सिंह इस व्यवस्था में बदलाव क्यों करते? वे कहते हैं कि कांग्रेस सरकार जनता के अधिकार का हनन कर किसी भी तरह निकायों के महापौर और अध्यक्ष के पद पर अपने नेताओं को काबिज कराना चाहती है।

पार्टी और बड़े नेता सुकून में

नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए पार्षदी के दावेदार गली-मोहल्लों में नजर आने लगे हैं। वर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षद समीकरण बिठाने में जुट गए हैं। प्रदेश सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव बगैर पार्टी चुनाव-चिन्ह के होंगे। कोई बिना किसी से टिकट मांगे अपना नामांकन दाखिल कर चुनाव लड़ सकता है। हालांकि हाइकोर्ट के निर्णय के बाद ही चुनाव प्रक्रिया की अंतिम तस्वीर साफ होगी। बिना चुनाव चिन्ह के निर्वाचन कराने के सरकार के फैसले का प्रमुख विपक्षी दल विरोध कर रहा है। महापौर का चुनाव भी सीधे जनता से कराने के लिए भाजपा संघर्ष कर रही है। चुनाव में टिकट का झंझट फिलहाल समाप्त हो जाने से राजनीतिक दलों के बड़े नेता सुकून महसूस कर रहे हैं। क्योंकि झंडे-डंडे उठाकर साथ चलने वाले समर्थक अब पार्टी के टिकट के लिए उनका कुर्ता नहीं पकड़ पा रहे हैं। हालांकि अपने खास समर्थकों के लिए नेताओं ने गली-मोहल्लों की राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दी है। भोपाल व दिल्ली के बंगलों पर सुकून महसूस किया जा रहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने औपचारिक चर्चा में कहा कि निकाय चुनाव में बहुत झंझट होते थे। एक वार्ड से टिकट एक को ही मिलना होता था और दावेदार कई होते हैं। एक टिकट मिलने से 4 नाराज हो जाते थे। आस्तीनें तानकर विधानसभा व लोकसभा चुनाव का इंतजार करते थे। सरकार के इस फैसले से हम बुराई लेने से बच गए।

निकायों से और हटेंगे अध्यक्ष हाईपॉवर कमेटी करेगी कंट्रोल

प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के पहले सरकार और अध्यक्षों को हटाएगी। आधा दर्जन अध्यक्षों पर जांचें चल रही हैं। इसके चलते इनका कार्यकाल पूरा होने के पहले गाज गिर सकती है। जबकि, सियासी नफे-नुकसान के आकलन के बीच सरकार हाईपॉवर कमेटी गठित करके निकायों का कंट्रोल दे सकती है। इसके लिए विधि विभाग ने भी मंजूरी दे दी है। निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह गंभीर है। ऐसे में निकाय चुनाव के लिए हर स्तर पर बिसात बिछना शुरू हो गई है। मार्च के बाद निकाय चुनाव होना हैं, लेकिन इसमें और देरी हो सकती है। सरकार ने पिछले हफ्ते चार नगरीय निकाय के अध्यक्षों को हटा दिया, जिससे वे आगामी निकाय चुनाव में शिरकत करने से बाहर हो गए हैं। वजह ये कि जब तक उन पर जांच चल रही है। नियमों के हिसाब से निकायों का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही चुनाव करना अनिवार्य है, लेकिन यदि चुनाव नहीं होते हैं तो आगे क्या करना है, इस पर कानून में कुछ नहीं लिखा। नियम सिर्फ यह कहता है कि चुनाव न होने पर वह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जो विधि के असंगत न हो। इसके चलते निकायों में प्रशासक बैठाने की प्रक्रिया चल रही है। इस पर जब सियासी सवाल उठने लगे, तो सरकार ने अब हाईपॉवर कमेटी बनाकर संचालन कराने रास्ता निकालने की तैयारी कर ली है। विधि विभाग ने लिखा है कि हाईपॉवर कमेटी बनाकर निकायों का संचालन कराया जा सकता है।

सही नहीं है निर्णय

गौरतलब है कि 16 नगर निगम के महापौर समेत अधिकांश नगर पालिका और नगर परिषद पर भाजपा के अध्यक्ष हैं, लेकिन चर्चा है कि प्रदेश में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस इन निकायों पर अपना कब्जा चाहती है। इसी मकसद से अधिनियम में संशोधन किया गया है। भाजपा पार्षदों द्वारा महापौर और अध्यक्ष चुनने की प्रणाली को सही नहीं मानती है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री **शिवराज सिंह चौहान** कहते हैं कि निकाय चुनाव में बदलाव कर कांग्रेस ने यह तो साफ कर दिया है कि उसे जनता पर विश्वास नहीं है। इसलिए उसने जनता के हाथ से महापौर चुनने का अधिकार छीन लिया है। यही नहीं कांग्रेस सरकार कई निकाय अध्यक्षों को हटा रही है, ताकि वे चुनाव में भाग न ले सकें। यह निर्णय बहुत गलत है, अभी तक **जनता महापौर** को चुनती थी, जिससे चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष रहता था। लेकिन अब पार्षद चुनेंगे तो खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। भ्रष्टाचार अधिक रहेगा और महापौर निष्पक्ष कार्य करने के बजाय दबाव में कार्य करेंगे।

वर्ष 2000 में मप्र की दिग्विजय सरकार ने नगर पालिक निगम विधि संशोधन अध्यादेश लाकर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को बदलकर प्रत्यक्ष प्रणाली लागू की थी। तब भोपाल में पहली बार प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत हुए चुनाव में कांग्रेस की विभा पटेल मेयर चुनी गई थीं। अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत भोपाल के आखिरी महापौर भाजपा के उमाशंकर गुप्ता थे। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर कांग्रेस सरकार ने जनता के हाथ से उनका अधिकार क्यों छीना है। वह कहते हैं कि अपने एक साल के कार्यकाल में सरकार जनता का भरोसा जीत नहीं पाई है। इसलिए ऐसे तिकड़म का सहारा ले रही है। वहीं राकेश सिंह का कहना है कि मप्र की कमलनाथ सरकार नगरीय निकाय चुनावों में जनता का सामना करने से डर रही है। सरकार को हार का डर सता रहा है, इसलिए निर्धारित समय पर निकाय चुनाव नहीं कराए गए। अब सरकार निकायों में प्रशासक नियुक्त कर रही है। ताकि, वह चिन्हित अधिकारियों के माध्यम से अपने हिसाब से नगरीय निकायों का संचालन कर मनमाने निर्णय ले सके।

पार्षदों का भी मान बढ़ेगा

उधर, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राज्य शासन के निर्णय से परिषद को मजबूती मिलेगी और पार्षदों का भी मान बढ़ेगा। महापौर का कद अब पहले से अधिक बड़ा होगा और परिषद में लिए गए निर्णय को अधिकारी तवज्जो देंगे। परिषद की गरिमा पहले से काफी बढ़ जाएगी, शहर विकास के कार्यों को बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। राज्य शासन के निर्णय से महापौर को अधिक शक्ति मिलेगी और वह पहले से बेहतर तरीके से कार्य कर सकेंगे। पार्षदों की बातों को अधिकारी अभी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। परिषद की महत्ता भी बढ़ेगी। शहर विकास से जुड़े निर्णय लिए जा सकेंगे।

नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने संशोधनों को लेकर स्पष्ट किया है कि मौजूदा व्यवस्था में नगरीय निकायों के अध्यक्ष तथा महापौर का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष व्यवस्था के माध्यम से करती है। इस व्यवस्था के कारण कई बार अध्यक्ष और चुने गए पार्षदों के बीच समन्वय में कमी रह जाती थी। इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय अटके रहते थे और नगरों का विकास प्रभावित होता था। इसको देखते हुए संशोधन किया गया है।

धनबल-बाहुबल का प्रयोग

विधायक एवं इंदौर नगर निगम की महापौर मालिनी गौड़ कहती हैं कि महापौर के लिए अभी अच्छे लोग आते थे, इसके बाद ऐसे लोग महापौर बनने के लिए कूद पड़ेंगे जो धनबल और बाहुबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। महापौर के चुनाव में अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं होती थी, लेकिन अब खरीद-फरोख्त शुरू हो जाएगी, जो शहर के विकास के लिए सही नहीं होगा।

उधर, सरकार का मानना है कि मप्र नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश-2019 के लागू होने से महापौर के चुनाव में करीब 30-35 करोड़ रुपए बचेंगे। भोपाल में ही करीब 3 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च होने का अनुमान रहता है। उधर, राजनीतिक दलों के खर्चों को भी जोड़ा जाए तो अप्रत्यक्ष तौर पर महापौर के चुनाव में खर्च होने वाली राशि शासकीय खर्च का 5 से 6 गुना होती है। वहीं ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल के संगठन मंत्री उमाशंकर गुप्ता का कहना है कि पार्षदों द्वारा महापौर चुनने से खरीद-फरोख्त की संभावना है।

गौरतलब है कि भोपाल-इंदौर जैसे बड़े निगमों में मेयर के चुनाव खर्च की सीमा अभी तक 35 लाख रुपए है, लेकिन चुनाव में 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च होता है। छोटे निगमों में मेयर चुनाव की खर्च राशि 15 लाख रुपए है, जबकि इन पर 1 करोड़ रुपए तक खर्च होता था। चुनाव खर्च की यह सीमा 2011 की जनसंख्या के हिसाब से तय की गई थी। भाजपा की आशंका है कि इस बार महापौर का **चुनाव अप्रत्यक्ष रूप** से होने के कारण पार्षदों की खरीद-फरोख्त होगी। इसके लिए धनबल और बाहुबल का प्रयोग होगा।

दल-बदल बढ़ेगा

भाजपा ने सरकार के इस फैसले का इसलिए विरोध किया है कि उसे यह आशंका है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और अध्यक्षों के चुनाव हुए तो उसको नुकसान हो सकता है। जबकि कांग्रेस अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाकर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में अपने समर्थकों को महापौर और अध्यक्ष बनाना चाहती है। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों का गणित देखा जाए तो दोनों ही प्रमुख पार्टियों के 40-40 प्रतिशत पार्षद जीतते हैं। वहीं, निर्दलीय और अन्य दलों के पार्षद 20 प्रतिशत पर ही सिमट जाते हैं। कमलनाथ सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस समर्थित पार्षदों के अलावा निर्दलीय और अन्य दल के पार्षद भी सत्ताधारी दल के साथ आना चाहेंगे। जिसके चलते प्रदेश के ज्यादातर नगरीय निकायों में कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधियों की जीत होगी।

हाल ही में छत्तीसगढ़ में भी अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं। कई जगह यह देखने को मिला है कि बराबरी की स्थिति होने के बाद भी **कांग्रेस** का महापौर बना है। इसी आशंका को देखते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव कहते हैं कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में बदलाव को लेकर सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर राज्यपाल का फैसला सर्वमान्य है, लेकिन इससे पार्षदों की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए सरकार को नगरीय निकायों में दल-बदल रोकने का कानून लागू करना चाहिए। वह कहते हैं कि भारत में शायद मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है, जहां पर जनता से सीधे अध्यक्ष और महापौर चुनने की व्यवस्था है। साथ ही अगर चुना हुआ जनप्रतिनिधि भ्रष्ट, निकम्मा और अलोकप्रिय हो तो उसे वापस बुलाने का अधिकार (राइट टू रिकॉल) भी मध्यप्रदेश में सिर्फ भाजपा शासन में लागू हुआ। इस अध्यादेश से जनप्रतिनिधियों में निरंकुशता बढ़ेगी और चुने गए जनप्रतिनिधि मनमानी करेंगे।

निकाय चुनाव पर तकरार

मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में तकरार का दौर जारी है। वार्ड आरक्षण की तारीख बढ़ाने और अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराए जाने को लेकर भाजपा ने प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और हमला बोला है। वहीं कांग्रेस नियमानुसार कदम उठाने का हवाला दे रही है। राज्य में नगर निकाय वार्डों का आरक्षण 30 दिसंबर तक किया जाना था, मगर इसे अब बढ़ाकर 30 जनवरी, 2020 कर दिया गया है। इसके चलते नगर निकाय के चुनाव फरवरी से पहले होना संभव नहीं है। इतना ही नहीं भोपाल को दो नगर निगमों में बांटने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास लंबित है। नगर निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण के लिए नगर विकास विभाग ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर कहा कि नियम-प्रक्रिया के तहत ही वार्ड परिसीमन किया जाए। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली है। इससे राज्य की कांग्रेस इकाई उत्साहित है, वहीं भाजपा को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं छत्तीसगढ़ जैसे ही नतीजे मध्य प्रदेश में न आ जाएं। वर्तमान में राज्य के नगर निकायों पर भाजपा का कब्जा है। नगरीय निकाय चुनाव मे महापौर पद के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संयोजक डॉ. पीजी नाजपांडे के द्वारा दायर इसी तरह की याचिका को हाईकोर्ट ने पूर्व में भी खारिज कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हे व्यक्तिगत आधार पर याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी थी जिसके चलते उन्होंने यह याचिका दायर की थी और एक बार फिर अदालत को बताया था कि नगरीय चुनाव में महापौर और नगर पालिका और जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने के नियम में राज्य सरकार ने गलत ढंग से संशोधन किया है। हाईकोर्ट ने इस पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने नियम का पालन करते हुए संशोधन किया है और अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव कराने का निर्णय लिया है जो कि पूरी तरह से सही है।

महापौर का नहीं हो पाएगा रिकॉल

नगर पालिका अधिनियम में संशोधन से यह स्पष्ट हो गया है कि महापौर का चुनाव अब जनता के बजाय चुने हुए पार्षद ही करेंगे और वे ही सभापति भी चुनेंगे। ये दोनों निर्वाचन एक ही दिन होंगे। यह भी अहम है कि महापौर व सभापति निर्वाचित पार्षदों में से ही चुने जाएंगे। नए नियमों के तहत इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभागायुक्त या कलेक्टर से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। सरकार ने महापौर, नगर पालिका अध्यक्षों को वापस बुलाने (रिकॉल) के अधिकार को खत्म कर दिया है। इसके लिए धारा 23 विलोपित की है। पहले किसी महापौर या अध्यक्ष से चुने हुए दो तिहाई पार्षद या इससे अधिक संतुष्ट नहीं होते थे तो खाली-भरी कुर्सी के नाम से दोबारा चुनाव की मांग करते थे। इसके जरिए प्रदेश में कुछ अध्यक्षों की कुर्सी भी गई। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर अभय राजनगांवकर के मुताबिक, रिकॉल पद्धति **स्विट्जरलैंड** से ली गई थी। इसमें शहर की जनता और उसके चुने हुए दो तिहाई जनप्रतिनिधि चाहें तो अध्यक्ष या महापौर को हटा सकते हैं। खरगोन जिले के करही में ऐसा हुआ, जहां अध्यक्ष भाजपा की थीं। उनके खिलाफ असंतोष के बाद चुनाव दोबारा हुए।

अब बदलेंगे चुनावी समीकरण

राज्य सरकार के फैसले के बाद शहर में निगम चुनाव के समीकरण बदलेंगे। महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव होने से पार्टी वरिष्ठ नेता को ही मैदान में उतारती थी। दूसरी-तीसरी लाइन में नेता पार्षद चुनाव लड़ते थे, पर अब बड़े नेताओं को भी जोर-आजमाइश करनी होगी। उधर, शहर के वार्डों का आरक्षण हो चुका है। लेकिन अब अगर परिसीमन की प्रक्रिया होती है फिर से वार्ड आरक्षण होगा, इस स्थिति में भी बहुत जगह बदलाव देखने को मिलेंगे। नगर निगम महापौर का चुनाव पार्षदों द्वारा तय कराने की शासन की घोषणा के बाद विधायक-मंत्री स्तर के शहर के कई बड़े नेता पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कई बार पार्षद का चुनाव जीत चुके वरिष्ठ पार्षद भी महापौर बनने की उम्मीद में खुद को दावेदार मान रहे हैं। दिसंबर- जनवरी में नगर निगम चुनाव की तारीखें घोषित होने के साथ ही शहर के कई पूर्व सांसद-विधायक, पार्टियों के जिलाध्यक्ष समेत पूर्व मंत्री तक पार्षद के चुनाव की टिकिट की लाइन में खड़े नजर आ सकते हैं। कारण स्पष्ट है, महापौर वही बनेगा जो पार्षद का चुनाव जीतेगा। अभी नगर निगम भोपाल में 85 वार्ड हैं। मौजूदा परिषद के 85 पार्षदों में महापौर को छोड़ दें तो नौ पार्षद दो बार से अधिक यानि बीते दस साल से पार्षद पद पर बने हुए हैं। इनमें से कुछ इससे भी अधिक समय से पार्षद हैं। अब जब पार्षद को महापौर बनने का मौका मिल रहा है तो ये दावेदारी करते हुए बड़े नेताओं की राह में दिक्कत खड़ी कर सकते हैं।

नगरीय निकायों में जीत की तैयारी में जुटी भाजपा

प्रदेश की सत्ता से बाहर होने के बाद अब भाजपा ने पूरा फोकस नगरीय निकायों व पंचायतों में एक बार फिर जीत हासिल करने तैयारियां शुरू कर दी है। अगले कुछ माह के दौरान यह दोनों चुनाव होना है। दरअसल भाजपा को लग रहा है कि अब प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता होने की वजह से उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर विपरीत असर पड़ सकता है, जबकि सरकार की वजह से मुख्य प्रतिद्वंदी दल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। ऐसे हालात में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव प्रभावित न हों, इसे लेकर पार्टी जल्द ही रणनीति बनाकर काम शुरू करने की तैयारी कर रही है। योजना के तहत संगठन अपने बड़े नेताओं को संभागों की जिम्मेदारी देने जा रही है, ताकि वे चुनाव से पहले निकाय स्तर पर जाकर तैयारी कर सकें। फिलहाल पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए गठित समिति की बागडोर पूर्व संगठन महामंत्री कृष्णमुरारी मोघे को सौंप दी है। फिलहाल प्रदेश की अधिकतर नगर निगमों पर भाजपा का कब्जा है पर कांग्रेस सरकार बनने के बाद नगरीय निकाय चुनाव में इस बार कड़ी टक्कर होने की संभावना है। ऐसे हालात में पार्टी की तैयारी है कि हर नगर निगम में पार्षद से महापौर तक के टिकट के लिए चेहरे चिन्हित करने और सर्वे कराने आदि का काम प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रारंभ कर दिया जाए। पार्टी इन चुनावों में नए चेहरों को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक भाजपा विधानसभा चुनाव 2018 की गलती न दोहराकर नगरीय निकाय चुनाव में नई पीढ़ी को सामने लाना चाहती है। पार्टी नेताओं की मानें तो राजनीति के पायदान पर ये छोटे चुनाव बेहद अहम होते हैं। यहां से एंट्री के बाद ही नए चेहरे विधानसभा और लोकसभा तक जाते हैं। संगठन चुनाव के बाद ही पार्टी नए चेहरों की तलाश शुरू कर देगी। पिछले चुनाव में भाजपा सभी 16 नगर निगम में काबिज हो गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ इस बार पुराने परिणामों को दोहराना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। इसी हिसाब से पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी।

महापौर पर अतिरिक्त दबाव

अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव कराने से नगरीय निकायों में पार्षद मजबूत होंगे। इस प्रणाली के तहत चुने महापौर या अध्यक्ष पर दबाव और अविश्वास प्रस्ताव आने की आशंकाएं लोग जताने लगे हैं। कुछ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षों से चर्चा के दौरान यह बात सामने आई है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से पार्षद मजबूत हो जाएंगे और अध्यक्ष पर दबाव भी बना रहेगा। कुर्सी से हटाने के लिए **सौदेबाजी** भी हावी रहेगी और भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। पूर्व महापौरों व पूर्व अध्यक्षों से जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली में से बेहतर प्रणाली के बारे में जाना तो अधिकांश प्रत्यक्ष प्रणाली के पक्ष में रहे। उनका मानना है कि प्रत्यक्ष प्रणाली में अध्यक्ष को पूरा शहर चुनता है और जनता की भागीदारी रहती है। इससे उसकी जबावदेही भी पूरे शहर के प्रति रहती है। अप्रत्यक्ष प्रणाली में दोनों तरह के पार्षद शामिल रहेंगे, अध्यक्ष को बनाने वाले और हराने वाले। ऐसे में अध्यक्ष और पार्षदों के बीच आपसी द्वंद्व भी बढ़ सकते हैं। इससे शहर के विकास पर प्रभाव पड़ सकता है।

खंडवा के महापौर सुभाष कोठारी का कहना है कि महापौर को जब पार्षद चुनेंगे तो वहां अतिरिक्त दबाव होगा। उन्हें संतुष्ट करना मुश्किल होगा। जबकि जनता की भागीदारी खत्म हो जाएगी। महापौर भी जनता से ज्यादा पार्षदों के प्रति खुद को जवाबदेह मानेगा। विकास में बाधाएं आएंगी। वहीं खंडवा नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अहमद पटेल कहते हैं कि लगातार अविश्वास प्रस्ताव को देखते हुए दिग्विजय सिंह शासनकाल में ही बदलाव किया था। मुख्यमंत्री कमलनाथ से हम सभी नेता प्रतिपक्षों ने मांग की थी कि पार्षद ही महापौर चुने। ध्रुवीकरण नहीं होगा तो कांग्रेस को लाभ मिलेगा। ये अच्छा निर्णय है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि कांग्रेस इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष में है, ताकि वह धनबल, बाहुबल और सरकार के दबाव के दम पर नगर निगमों में अपने महापौर बैठा सके। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसीलिए कानून में परिवर्तन किया

है, ताकि वे पार्षदों की खरीद-फरोख्त करके अपना महापौर बना सके। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हफीज अब्बास का कहना है, कांग्रेस हमेशा संविधान का सम्मान करती है और नियमों के मुताबिक ही फैसले लेती है। भाजपा अपनी सुविधा के अनुसार कानून की व्याख्या करती है। जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते हैं तो कोई बात नहीं और अगर कांग्रेस शासित राज्यों में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है तो सवाल उठाते हैं। भाजपा पार्षदों की निष्ठा पर सवाल उठाकर और खरीद-फरोख्त की बात करके आम मतदाता का अनादर कर रही है।

शुरू हो जाएगा कुर्सी का खेल

जानकारों का कहना है की पार्षदों द्वारा महापौर या अध्यक्ष चुने जाने के बाद **कुर्सी का खेल** शुरू हो जाएगा। आए दिन अविश्वास प्रस्ताव और कुर्सी बचाने का खेल होगा। महापौरों और अध्यक्षों का ध्यान पार्षदों को खुश करने में लगा रहेगा। इससे विकास भी प्रभावित होगा। गुना नपा के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रकाश तिवारी कहते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव महंगा होगा। विकास की गति थम जाएगी। पार्षद सौदबाजी करेंगे। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अध्यक्ष काम के बजाय, अपनी कुर्सी बचाने में लगा रहेगा। जनहित के लिए अध्यक्ष को सीधे चुना जाना चाहिए। इससे उनकी जबावदेही भी जनता के लिए प्रति रहेगी। वह कहते हैं कि गुना नपा में ही एक बार अध्यक्ष को बीच में अपना पद छोड़ना पड़ा था। कांग्रेस की गुटबाजी के चलते उनको पद छोड़ना पड़ा। उस समय कांग्रेस से रतन सोनी अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन पार्टी का अंदरूनी विवाद इतना बढ़ा कि उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद नेमीचंद जैन एडवोकेट को अध्यक्ष बनाया गया था। गुना नपा अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रणाली में जनता नेता चुनती है। जबकि अप्रत्यक्ष में पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे। इस प्रणाली से अध्यक्ष को हटाने के अविश्वास प्रस्तावों की बाढ़ सी आ जाएगी। इससे काम नहीं होगा। भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जिला पंचायत के चुनाव भी डायरेक्ट होना चाहिए।

नगरीय निकाय चुनाव में इस बार कांग्रेस सरकार बड़ा बदलाव करने की चर्चा इस समय राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ती दिख रही है। इसके पीछे की वजह ज्यादा से ज्यादा नगरीय निकायों में कांग्रेस के कब्जा करने की मंशा को बताया जाता है। इस संबंध में कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर के अनुसार मुख्य कारण ये है कि सभी जगहों का पूर्ण विकास हो, क्योंकि जब महापौर आदि विधायक बन जाते हैं तो वे केवल अपने क्षेत्र का ही विकास करते हैं। जबकि अन्य क्षेत्र विकास की दौड़ में ऐसा करने से पिछड़ जाते हैं।

प्रशासकों के हवाले निकाय

दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक 287 नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा होगा। यहां कार्यकाल पूरा होने के पहले चुनाव नहीं हो पाए हैं और अगले दो-तीन महीने उसकी संभावना भी नहीं है। इस माह के अंत तक 288 निकायों की बागडोर प्रशासकों के हाथ में पहुंच जाएगी। समय से निकाय चुनाव नहीं होने से सरकार को यहां प्रशासक नियुक्त करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश के 16 में से 14 नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 7 निगमों में प्रशासक नियुक्त किए जा चुके हैं। इस माह में बुरहानपुर, ग्वालियर व खंडवा और फरवरी में भोपाल, इंदौर, जबलपुर व छिंदवाड़ा ननि का कार्यकाल पूरा हो रहा है। यहां भी प्रशासक या प्रशासनिक समिति नियुक्त होगी। उज्जैन नगर निगम का कार्यकाल 3 सितंबर व मुरैना का 8 सितंबर को खत्म होगा, यहां प्रशासक की जरूरत नहीं पड़ेगी। राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस नगरीय निकाय चुनावों से डरी हुई है जो चुनावों को टालते हुए नगरीय निकायों में अपने चयनित अफसरों को प्रशासक बना रही है। राकेश सिंह ने प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर किसी भी नगरीय निकाय के प्रशासक ने गड़बड़ी भरे निर्णय लिए तो भाजपा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी।

भोपाल शहर का बंटवारा तय

मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में दो नगर निगम का बनना अब तय हो गया है। भाजपा के तमाम विरोधों के बाद भी राज्य सरकार ने भोपाल में दो नगर निगम बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेज दिया है। राज्यपाल के मुहर लगाने के बाद राजधानी में दो नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी होगी। भोपाल शहर के बंटवारे को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने सड़क से लेकर राजभवन तक कई बार ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराया था। लेकिन कमलनाथ सरकार ने अब दो नगर निगमों का प्रस्ताव राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजकर अपने कदम से पीछे हटने से इनकार कर दिया है।

24 जिलों में नहीं हुई पदों के आरक्षण की कार्रवाई, लेट होंगे निकाय चुनाव

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में देरी हो सकती है। क्योंकि अब तक प्रदेश के 24 जिलों में नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों में महापौर और अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण की कार्रवाई पूरी नहीं की गई है। बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक सागर, जबलपुर, विदिशा, सीहोर, पन्ना, आगर मालवा, गुना, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, देवास, धार, नरसिंहपुर, बुरहानपुर, मुरैना, डिंडोरी, मंडला, रतलाम, शहडोल, श्योपुर, शाजापुर, हरदा, होशंगाबाद से निवाड़ी जिलों के कलेक्टरों ने जानकारी शासन को नहीं भेजी है। आयुक्त नगरीय प्रशासन पी. नरहरि ने इसके लिए कलेक्टरों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश देते हुए वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या की जानकारी जल्द भेजने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जानकारी निर्धारित प्रपत्र में ही भेजें। यह निर्देश उन जिलों को दिए गए हैं, जिन्होंने अभी तक यह जानकारी नहीं भेजी। दरअसल, नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों में महापौर अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर कार्रवाई करने के लिए मई, जुलाई और अक्टूबर में कलेक्टरों को निर्देश दिए थे लेकिन तीन बार स्मरण कराने के बाद भी 24 जिलों के कलेक्टरों ने इस संबंध में कार्यवाही नहीं की है। इसके कारण चुनाव प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है।

नहीं बदलेगी तस्वीर

इस साल राज्यसभा के दोवार्षिक चुनाव हैं। कुल 73 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। ज्यादातर सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं, जिनके लिए मार्च में चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की दस सीटों सहित कुछ सीटों पर साल के अंत में चुनाव होना है। इस साल खाली हो रही 73 सीटों में से सबसे ज्यादा 18 सीटें भाजपा की हैं और 17 सीटें कांग्रेस की हैं। फिलहाल राज्यसभा 83 सांसदों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस सांसदों की संख्या 50 से नीचे होकर 46 रह गई है। आमतौर पर यह धारणा बनी थी कि जल्दी ही भाजपा को राज्यसभा में बहुमत मिल जाएगा। भाजपा नहीं तो कम से कम एनडीए को जरूर बहुमत मिल जाएगा। पर इस साल के दो वार्षिक चुनाव के बाद भी संसद के उच्च सदन की तस्वीर में कोई खास बदलाव नहीं आना है।

असल में पिछले 12-13 महीने में हुए विधानसभा चुनावों ने भाजपा या एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिलने की संभावना को खत्म कर दिया है। भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले साल सत्ता से बाहर हो गई थी और इस साल महाराष्ट्र व झारखंड की सत्ता से बाहर हो गई है। इससे इन पांच राज्यों में राज्यसभा चुनाव का हिसाब बदल गया है। अब इन राज्यों में ज्यादातर सीटें गैर भाजपा दलों को जाएंगी। कुल मिलाकर भाजपा को लगभग उतनी ही सीटें मिलेंगी, जितनी उसकी खाली हो रही हैं।

इनमें में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा 15 साल से सत्ता में थी। इन दो राज्यों में पांच सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से तीन सांसद भाजपा के रिटायर हो रहे हैं। इसी तरह बिहार में भाजपा और जदयू पिछले करीब 15 साल से सत्ता में हैं। वहां रिटायर हो रहे पांचों सांसद उसके ही हैं, जबकि इस बार उसे सिर्फ तीन सीटें मिलेंगी। भाजपा को उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा होगा। वह खाली हो रही दस में आठ सीटें जीत जाएगी। पर उसे राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में कुछ सीटों का नुकसान होगा। सो, कुल मिलाकर उसके सांसदों की संख्या जस की तस रहेगी या अगर एक दो अतिरिक्त सीटें भाजपा ने किसी तरह से निकाली तो उसकी संख्या में मामूली इजाफा होगा।

जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो उसकी स्थिति में भी ज्यादा बदलाव नहीं होगा। उसके जितने सांसद रिटायर हो रहे हैं लगभग उतनी संख्या में ही सांसदों की वापसी हो सकती है। उसे कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, असम जैसे राज्यों में एक-एक सीट का नुकसान हो सकता है पर कम से कम छह राज्यों में उसे फायदा भी हो रहा है और महाराष्ट्र में वह अपनी एक सीट बचाने में कामयाब रहेगी। सो, संभव है कि उसकी सीटों की संख्या में एक-दो का इजाफा हो जाए। राज्यसभा के चुनाव से पहले कई उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस का माहौल है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव रिटायर हो रहे हैं। राज्य में विपक्ष को एक सीट मिलने की पक्की संभावना है और वह सीट सपा को ही मिलेगी। पर सवाल है कि क्या पार्टी फिर से रामगोपाल यादव को ही राज्यसभा में भेजेगी या कोई नया चेहरा ट्राई करेगी? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को भी राज्यसभा में भेजने की चर्चा है। हालांकि खुद अखिलेश लोकसभा सांसद हैं इसलिए कई लोग इस संभावना को खारिज कर रहे हैं।

दूसरी सस्पेंस वाली सीट झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस सीट पर अपने पिता शिबू सोरेन को भेजेंगे या छोटे भाई बसंत सोरेन को? ध्यान रहे जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन इस बार दुमका लोकसभा सीट से चुनाव हारे हुए हैं, जबकि बसंत सोरेन 2016 के राज्यसभा चुनाव में सहयोगी पार्टी के दो सांसदों की क्रॉस वोटिंग की वजह से हार गए थे। इस बार यह भी चर्चा है कि हेमंत सोरेन अपनी जीती दो में से एक विधानसभा सीट खाली करेंगे तो वहां से बसंत सोरेन लड़ सकते हैं। पर उस सीट से अचानक हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है।

हरियाणा में खाली हो रही एक सीट का भी सस्पेंस है। बताया जा रहा है कि सरकार बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला की पार्टी से तालमेल करते हुए भाजपा ने उनको राज्यसभा की एक सीट देने का वादा किया था। पर यह तय नहीं है कि इस बार सीट दी जाएगी या अगले चुनाव में। राज्य की एक सीट कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के रिटायर होने से खाली हो रही है। कांग्रेस कुमारी शैलजा को कहां से राज्यसभा भेजेगी यह भी सस्पेंस है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला एक बार फिर महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिहार में जदयू के तीन सांसद रिटायर हो रहे हैं पर इस बार उसे दो सीटें मिलेंगी। इनमें एक सीट हरिवंश की हो सकती है क्योंकि वे राज्यसभा के उप सभापति हैं।

● **विशाल गर्ग**

सबकी नजर मप्र पर

मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है और इस वजह से सबकी नजर वहां के चुनाव पर है। मध्य प्रदेश के चुनाव में दिलचस्पी के दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की सीटों की संख्या में ज्यादा का अंतर नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि राज्य में खाली हो रही तीन में से दो सीटें जीतने का प्रयास कांग्रेस भी करेगी और भाजपा भी करेगी। यानी भाजपा तीसरी सीट पर कांग्रेस को वाकओवर नहीं देने जा रही है। उसने अगर अपना उम्मीदवार उतार दिया तो फिर तीसरी सीट पर घमासान पक्का है। ध्यान रहे राज्य में एक सीट जीतने के लिए 58 वोट की जरूरत होगी। कांग्रेस के पास अपने 114 और भाजपा के 108 विधायक हैं। सो, एक-एक सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के पास 56 और भाजपा के पास 50 वोट बचेंगे। कांग्रेस को सपा, बसपा और निर्दलियों का भी समर्थन है। इसलिए उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर अगर भाजपा कुछ तोड़फोड़ करना चाहिए या क्रास वोटिंग कराने का प्रयास करे तो मामला उलझ सकता है। दिलचस्पी का दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस की ओर से दो दिग्गज दावेदार हैं। एक हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया।

उन्नीस बीस

> हाल ही में आए कुछ राज्यों के चुनाव परिणाम इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में कोई भी एक दल इतना सक्षम नहीं होगा कि वह अकेले अपने दम पर सरकार बना सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बड़े दलों को छोटे दलों के पीछे चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

हरियाणा और महाराष्ट्र ने जो संकेत दिए थे झारखंड ने उस पर मुहर लगा दी। भारत जैसे सांस्कृतिक और भौगोलिक बहुलता वाले देश में क्षेत्रीय क्षत्रपों ने अपनी अहमियत एक बार और साबित कर दी है। हालांकि इससे पहले हुए राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भी जनता ने स्थानीय मुद्दों पर ही अपनी सरकारें चुनी थीं। जनता लगातार यह संदेश दे रही है कि वह केंद्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को अलग कर देखना जानती है। इसके साथ ही कांग्रेस ने महाराष्ट्र से लेकर झारखंड में जिस तरह से **क्षेत्रीय दलों** के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश शुरू की है उसका भी राजनीतिक संदेश है। एक समय था जब भाजपा ने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाया था। लेकिन अब कांग्रेस वाला **अहंकार** भाजपा में दिखना शुरू हो गया है। इस पर एक बार फिर तवज्जो इसलिए कि दोनों दल इतिहास से कोई सबक लेने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। शायद इसलिए क्षेत्रीय क्षत्रपों की समय-समाप्ति का ऐलान भी बहुत जल्दी इतिहास बन गया। पिछले कई विधानसभा चुनावों में देखा गया कि देश की जनता केंद्रीय और स्थानीय मुद्दों में फर्क करती आ रही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक में जनता ने संदेश दिया कि उसके लिए केंद्र का मुद्दा अलग है तो वह अपने राज्य में स्थानीय मुद्दों की ही बात करना चाहती है। पिछले साल के अंत और इस साल के शुरू में हुए विधानसभा चुनावों में खेती-किसानी और बेरोजगारी ही अहम मुद्दा रहा। मजबूत राजनीतिक **फैसलों** का उसकी जिंदगी पर असर नहीं पड़ा तो वह बहुत दूर से आए भाषण को क्यों सुने। जब उसे अपनी रोज की रोटी जुटाने में मुश्किल हो रही है तो वह इस बात पर खुश हो भी तो कैसे कि अब कश्मीर में जमीन-जायदाद खरीद सकता है।

आम जनता तो केंद्र और राज्य का फर्क करना जानती है लेकिन अफसोस कि भाजपा के रणनीतिकार यह फर्क करना नहीं सीख पा रहे हैं। कश्मीर और झारखंड की समस्या एक नहीं है। देश की औद्योगिक राजधानी महाराष्ट्र और एक खनिज संसाधनों से भरपूर लेकिन आर्थिक विकास में बहुत पिछड़े समाज की जरूरतें अलग हैं। झारखंड भूख से मौत के लिए कुख्यात हुआ, आरोप लगा कि संतोषी नाम की बच्ची भात-भात कहते हुए मर गई। यहां तो आधार कार्ड भी आरोपी हुआ कि इसका नंबर नहीं होने के कारण गरीब को उसके हिस्से का राशन नहीं मिला।

केंद्र और राज्य की राजनीति अलग-अलग

क्षेत्रीय क्षत्रपों की वापसी ने केंद्र और राज्य की राजनीति को अलग-अलग तरीके से लेने का संदेश दे दिया है। दिल्ली के चुनावी मैदान में तो इस संदेश का सकारात्मक असर दिखने भी लगा है। केंद्र सरकार के पास अभी पर्याप्त समय है कि वह जनता की उन जरूरतों पर संवाद करे जिसका संदेश उसने दिया है। हमने 2019 का जो चुनावी पाठ शुरू किया था, झारखंड ने क्षेत्रीयता का झंडा बुलंद कर उसका उपसंहार भी रच दिया है। सत्ता और जनता के बीच के रिश्ते को समझने का, कभी जनता के आगे जाने और सत्ता के पीछे होने का यह क्रम अगले साल भी चलता रहेगा।

कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष की एकता लंबे समय तक देखी गई। यह एकता राज्यों से होते हुए केंद्र तक बनी रही जिसका परिणाम हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनावों में आधुनिक भारत के इतिहास में अहम पार्टी रही कांग्रेस को ऐतिहासिक हार मिली। लेकिन 2014 के चुनावों में खासकर उत्तर प्रदेश से मिले प्रचंड बहुमत के बाद भाजपा ने इस विपक्षी एकता की बेकद्री की, क्योंकि वह ऐतिहासिक रूप से अपने बूते पक्ष में थी। लेकिन दुखद है कि इसके बाद भाजपा ने अपने खिलाफ उठे हर सुर को 'भ्रष्ट' बोलना शुरू कर दिया। खासकर आईबी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के सीमित इस्तेमाल का बुरा असर दिखने लगा और अपना अस्तित्व बचाने के लिए विपक्ष ने गोलबंदी शुरू की। कानून बनाकर चुनावी फंडिंग पर सत्ता पक्ष का एकाधिकार जैसे हालात ने भी विपक्ष को एकजुट होने के लिए मजबूर कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने जद (एकी) की जितनी मांगें मांगकर झुकना पसंद किया और कांग्रेस ने अकड़ना पसंद किया तो उसका नतीजा भी दिखा था। अब जबकि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के पास चुनावी चंदों का भी सहारा नहीं बचा तो उनके पास एक-दूसरे को सहारा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भारत जैसे देश में जब चुनावी प्रचार को बहुत महंगा बना दिया गया है तो चुनावी चंदा किसी भी पार्टी के वजूद के लिए अहम हो जाता है। अब विपक्ष के पास अपने-अपने अहंकार को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड में जिस तरह कांग्रेस ने झुक कर क्षेत्रीय क्षत्रपों के छाते के नीचे चलना मंजूर किया, उसे राजनीतिक इतिहास में एक सबक के तौर पर ही देखा जाएगा।

इन सारे बिंदुओं के साथ सबसे अहम है अर्थव्यवस्था यानी आम लोगों की रोजी-रोटी की बात। **नोटबंदी और जीएसटी** का असर लंबे समय बाद जनजीवन पर साफ-साफ दिखने लगा है। यह छह-सात महीने जैसे छोटे समय की बात होती तो जनता इसमें भी अच्छे दिन देख लेती। लेकिन जिस तरह से हालात लंबे समय से बिगड़ रहे हैं उसके बाद प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। जनता को अर्थव्यवस्था पर तसल्ली भी मिल

जाती तो बात आगे बढ़ सकती थी। लेकिन यहां तो 'हम लहसुन, प्याज नहीं खाते' से लेकर 'कहां है मंदी, कहां है मंदी' जैसे संवाद गूंजने लगे। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र व झारखंड तक में सत्ता पक्ष ने उस कमजोर वर्ग को कोई उम्मीद नहीं दिखाई जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था।

वहीं महाराष्ट्र व झारखंड दोनों ही प्रदेशों की सरकार में कांग्रेस पार्टी जूनियर पार्टनर की भूमिका में है। इन दो प्रदेशों की सरकार में शामिल होकर कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार व कर्नाटक में **बड़ी बेअदबी** से सत्ता से बेदखली के गम को भी भुलाने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, जिसमें वहां की जनता ने इनके गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया था। लेकिन चुनाव के बाद भाजपा शिवसेना गठबंधन में खटपट होने से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस ने मिलकर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवा दिया। वहां मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण को तो मंत्री बनाया गया है। मगर शरद पवार के विरोध के चलते पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को मंत्री पद से महरूम रहना पड़ा।

महाराष्ट्र व झारखंड की जीत में कांग्रेस अपनी कर्नाटक की हार को छुपाने का असफल प्रयास कर रही है। कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा की सरकार बनने से रोकने के लिए कांग्रेस ने अपने धुर विरोधी जनता दल सेक्युलर से समझौता कर कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। कुमार स्वामी सरकार में कांग्रेस जूनियर पार्टनर के रूप में शामिल हुई थी। लेकिन एक साल के अंदर ही कुमार स्वामी सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी के बीएस येदियुरप्पा फिर से मुख्यमंत्री बन गए। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए गए

कांग्रेस पार्टी जूनियर पार्टनर की भूमिका में

कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता इन दिनों खुशी से बम-बम हो रहे हैं। पहले महाराष्ट्र फिर झारखंड में भाजपा की हार से कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे खुशी मना रहे हैं मानो कांग्रेस पार्टी ने बरसों से खोया अपना जनाधार फिर से हासिल कर लिया हो। कांग्रेसजनों के चेहरे पर इन दिनों किसी जंग को जीतने वाली मुस्कान देखने को मिल रही है। हालांकि महाराष्ट्र व झारखंड दोनों ही प्रदेशों की सरकार में कांग्रेस पार्टी जूनियर पार्टनर की भूमिका में है। इन दो प्रदेशों की सरकार में शामिल होकर कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार व कर्नाटक में बड़ी बेअदबी से सत्ता से बेदखली के गम को भी भुलाने का प्रयास कर रही है।

कांग्रेस के 15 विधायकों के क्षेत्रों में सम्पन्न हुए उपचुनाव में भाजपा को 12 व कांग्रेस को दो सीट ही मिल पाई। एक सीट पर भाजपा का बागी चुनाव जीत गया। कर्नाटक जैसा बड़ा प्रदेश हाथ से फिसलने के उपरांत भी कांग्रेस पार्टी द्वारा खुशी मनाना लोगों की समझ से परे है।

2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सहित सभी बड़े नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा देशव्यापी अभियान चलाया था। विरोधी दलों के बहुत सारे नेताओं ने भी कांग्रेस के **उस अभियान को** अपना समर्थन दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दूसरी बार भरोसा करते हुये भाजपा को 303 लोकसभा सीटों पर जिताकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार केंद्र में सरकार बनवाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र 52 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। यहां तक कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी खुद अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव में केरल, पंजाब और तमिलनाडु ने जरूर कांग्रेस की लाज रख ली। कांग्रेस केरल में 15, पंजाब में 8 और तमिलनाडु में 8 सीटें जीतने में सफल रही। इसके अलावा तेलंगाना में तीन, पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़ में दो-दो, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, अंडमान निकोबार दीप समूह, पांडिचेरी में कांग्रेस का एक-एक सांसद ही जीत पाया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, चंडीगढ़ सहित 14 प्रदेशों में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को देशभर में 19.49 प्रतिशत मत मिले थे जबकि लोकसभा में उनके सांसदों का प्रतिनिधित्व मात्र 9.58 प्रतिशत है। राज्यसभा में भी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या घटकर मात्र 46 रह गई है।

2014 में कांग्रेस पार्टी की जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, झारखण्ड, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम सहित कुल 16 प्रदेशों में सरकार थी। वहीं 2019 में कांग्रेस पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी में अकेले अपने बल पर व महाराष्ट्र तथा झारखंड में क्षेत्रीय दलों के छोटे पार्टनर के रूप में सत्तारूढ़ है। महाराष्ट्र में तो जोड़-तोड़ कर कांग्रेस, शिवसेना व एनसीपी के साथ मिलकर सरकार में शामिल हो गई। लेकिन हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस लगातार दूसरी बार सरकार बनाने से रह गई। हरियाणा में 40 सीटें जीतकर भाजपा ने वहां दुष्यंत चौटाला व निर्दलियों के साथ मिलाकर सरकार बना ली।

कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। पार्टी में जमीन से जुड़े लोगों को आगे लाना चाहिए। राज्यसभा के रास्ते वर्षों से सत्ता का सुख भोगने वाले बड़बोलों से पार्टी को पीछा छुड़ाना चाहिए। साफ छवि के नेताओं को नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में भागीदारी देनी चाहिए जिससे कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत होकर अपना पुराना जनाधार हासिल कर सके। यदि आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के सहारे गठबंधन की राजनीति में ही उलझी रहेगी तो उसका रहा सहा जनाधार भी खिसक जाएगा। फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना सपना बनकर ही रह जायेगा।

● **दिल्ली से रेणु आगाल**

चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने की एक नई व्यवस्था के रूप में हमारे सामने आया है। सरकार का दावा है कि चुनावी बॉन्ड व्यवस्था से राजनीतिक दलों को गलत तरीके से की जाने वाली फंडिंग के प्रचलन पर रोक लगेगी और उन दलों को ही चंदा दिया जा सकेगा जो इसके योग्य हों। लेकिन सरकार की इस पहल पर कई सवालिया निशान लगने से इसकी सकारात्मकता और पारदर्शिता फिर सवालों के घेरे में है। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने चंदा देने वालों के नाम को गोपनीय रखने के संशोधन पर आपत्ति जताई थी। जाहिर है, आयोग को इस बात का डर है कि नाम गुप्त रखने से प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं आएगी।

विवादों में इलेक्टोरल बॉन्ड

देश के राजनीतिक गलियारों में इलेक्टोरल (चुनावी) बॉन्ड का नाम साल 2017 से खूब चर्चा में है। मोदी सरकार ने राजनीतिक चंदे की स्वच्छता व पारदर्शिता के लिए साल 2017 के बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड लागू किया था। इसके बाद जनवरी 2018 में पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए। अभी तक के हासिल आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2018 से अक्टूबर 2019 तक कुल 12,313 इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं जिनके द्वारा राजनीतिक दलों को 6,128 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। लेकिन यह चंदा किस-किस ने दिया है इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाई है। यही नहीं जिस तरह प्रधानमंत्री कार्यालय ने वित्त मंत्रालय को निर्देश देकर अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन किया और इलेक्टोरल बॉन्ड की अवैध बिक्री का दरवाजा खोल दिया उससे इलेक्टोरल बांड गड़बड़ियों और घोटालों का हिमालय बन गया है।

चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए त्योहार सरीखे होते हैं। इसमें बेहतर कल के लिए आम आदमी की आकांक्षाएं और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। लेकिन इसी चुनावी प्रक्रिया में कुछ ऐसी चिंताएं भी जुड़ी हैं जो **बीते सात दशकों** से लोकतंत्र के इस पर्व का स्वाद कड़वा कर देती है। पॉलिटिकल फंडिग और खर्च का सवाल भी चिंताओं की फेहरिस्त का हिस्सा है। यूं तो चुनाव में चंदा देना आम बात है। लेकिन ये चंदा कौन दे रहा है? कितना दे रहा है, किसे दे रहा है और क्यों दे रहा है? ये सवाल हर चुनाव में उठते रहे हैं। लेकिन इस बार देश में इलेक्टोरल बॉन्ड पर विवाद चरम पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी अपारदर्शिता और भाजपा को मिलने वाले चंदे में रिकार्ड बढ़ोत्तरी।

हालांकि इस व्यवस्था का निर्माण होने के समय ही सरकार की ओर से यह कहा गया था कि यह पूरी तौर पर पारदर्शी नहीं, लेकिन अब उसे लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद का कारण विपक्ष का यह आरोप है कि इस व्यवस्था का लाभ सत्ताधारी दल यानी भाजपा को मिल रहा है। इस आरोप के साथ रिजर्व बैंक की उस आपत्ति का भी जिक्र किया जा रहा है जो उसकी ओर से चुनावी बांड को लेकर जताई गई थी।

चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की है। सरकार ने इस दावे के साथ इस बॉन्ड की शुरुआत की थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ-सुथरा धन आएगा, काले धन पर रोक लगेगी। हालांकि, इस बॉन्ड ने पारदर्शिता लाने की जगह जोखिम और बढ़ा दिया है, यही नहीं विदेशी स्त्रोतों से भी चंदा आने की गुंजाइश हो गई है। चुनाव आयोग ने भी अपनी टिप्पणियों में इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी अज्ञात बैंकिंग व्यवस्था के जरिए राजनीतिक फंडिंग को लेकर संदेह जाहिर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 12 मार्च को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार को नसीहत भी दी थी कि इस बारे में केंद्र सरकार गंभीरता से कदम उठाए। इसके बाद से ही इलेक्टोरल बॉन्ड लगातार सवालों के घेरे में है। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का सोर्स पता न होने के चलते कॉर्पोरेट चंदे को बढ़ावा मिला। साथ ही विदेश से मिलने वाला धन भी वैध हो गया। इस बॉन्ड के स्त्रोत का खुलासा करना जरूरी नहीं है।

इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत करते समय इसे सही ठहराते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में लिखा था, इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था में साफ-सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 में बदलाव के द्वारा लाए गए थे। वास्तव में इनसे पारदर्शिता पर जोखिम और बढ़ा है। खुद चुनाव आयोग ने इन बदलावों पर गहरी आपत्ति करते हुए कानून मंत्रालय को इनमें बदलाव के लिए लेटर लिखा है। सरकार का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में योगदान किसी बैंक के अकाउंट पेई चेक या बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। सरकार का यह भी तर्क है कि इन बॉन्ड को एक रैंडम सीरियल नंबर दिए गए हैं जो सामान्य तौर पर

राजनीतिक चंदा हमेशा विवादों में

दरअसल, भारतीय राजनीति में चुनावी चंदे का मामला हमेशा ही विवादों में रहा है। कभी इसे राजनीति में कालेधन के उपयोग से जोड़ा जाता है, तो कभी राजनीति के अपराधीकरण के लिए भी इसे दोषी माना जाता है। लेकिन विडंबना है कि आजादी के 70 साल बाद जिस चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की गई उसमें भी पारदर्शिता अपने वजूद की तलाश कर रही है। दरअसल, कई दशकों से सियासी दल चंदा देने वालों के नाम को छुपाने का जो खेल, खेल रहे थे, उसका खात्मा इस चुनावी बॉन्ड के चलते भी नहीं हो सका है। ऐसे में पारदर्शिता के सभी सरकारी दावे महज दावे ही मालूम पड़ते हैं। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि हर बार पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए चंदा देने वालों के नाम उजागर करने की मांग की जाती है लेकिन सियासी दल हर कानून में अपना रास्ता खोज निकालते हैं। 20 हजार रुपए से कम चंदा देने वालों के नाम और चुनावी बॉन्ड में दान दाताओं की पहचान गोपनीय रखने की व्यवस्था इसी का एक पहलू है।

आंखों से नहीं दिखते। बॉन्ड जारी करने वाला एसबीआई इस सीरियल नंबर के बारे में किसी को नहीं बताता। लेकिन उक्त सारे प्रावधानों से भी समस्याएं दूर नहीं होतीं। चंदा देने वाली की गोपनीयता और राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बनी रहती है और यह सब चुनाव आयोग की जांच के दायरे से भी बाहर है। केवाईसी होने के बाद भी चंदा देने वाले के बारे में सिर्फ बैंक या सरकार को जानकारी हो सकती है, चुनाव आयोग या किसी आम नागरिक को नहीं। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 सी में बदलाव करते हुए कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा हासिल चंदों को चुनाव आयोग की जांच के दायरे से बाहर रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने इसे **प्रतिगामी कदम** बताया है। चुनाव आयोग ने कहा कि इससे यह भी नहीं पता चल पाएगा कि कोई राजनीतिक दल सरकारी कंपनियों से विदेशी स्त्रोत से चंदा ले रही है या नहीं, जिस पर कि धारा 29 बी के तहत रोक लगाई गई है।

देश की तीन राष्ट्रीय और 22 क्षेत्रीय दलों ने अपना 50 फीसदी चंदा चुनावी बांड के जरिए वसूला है। इन पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए ब्यौरे के आधार पर एडीआर रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 25 दलों ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 1163.17 करोड़ रुपए का चंदा वसूला जिसमें से 593.6 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से आया। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक ब्यौरा देने वाले राष्ट्रीय दलों में बसपा, तृणमूल कांग्रेस और बीजद शामिल हैं। भाजपा, कांग्रेस समेत 35 पार्टियों ने अब तक अपनी आय का ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं सौंपा है। इनमें पांच राष्ट्रीय और 30 क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्यौरा देने वाली 25 पार्टियों ने 893.6 करोड़ रुपए यानी 76.82 फीसदी स्वैच्छिक योगदान, दान और चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एकत्र किया है। जबकि अन्य दान में 305.53 करोड़ रुपए यानी 25 दलों की कुल आय के 26 फीसदी से अधिक राशि प्राप्त की। तीन राष्ट्रीय दलों में केवल तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिले दान का खुलासा किया है। पार्टी को 97.28 करोड़ की राशि मिली है। एडीआर ने कहा, चुनावी चंदे में चुनावी बॉन्ड

वर्तमान समय में सबसे अधिक लोकप्रिय हो रहा है। गोपनीयता के कारण इसे काफी पसंद किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक आय 249.31 करोड़ रुपए ओडिशा के बीजू जनता दली की है। इसके बाद 192.65 करोड़ रुपए के साथ तृणमूल कांग्रेस दूसरे और 188.7 करोड़ रुपए के साथ टीआरएस तीसरे नंबर पर है।

आलोचकों का कहना है कि ये बॉन्ड भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले साबित हुए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एडीआर की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण का भी यही तर्क था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कॉरपोरेट और उद्योग जगत को फायदा हो रहा है और ऐसे बॉन्ड से मिले चंदे का 95 फीसदी हिस्सा भाजपा को मिलता है। चुनाव आयोग ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से साल 2017-18 में सबसे ज्यादा 210 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को मिला है। बाकी सारे दल मिलाकर भी इस बॉन्ड से सिर्फ 11 करोड़ रुपए का चंदा हासिल कर पाए थे। चुनाव आयोग ने इस मामले में चल रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी। भाजपा को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 20,000 रुपए से अधिक के दान में 743 करोड़ रुपए मिले। यह राशि कांग्रेस समेत छह राष्ट्रीय दलों को प्राप्त हुई चंदे की राशि से तीन गुना अधिक है। 31 अक्टूबर को चुनाव आयोग के सामने दायर हलफनामे में भाजपा ने इस बात का खुलासा किया था। कांग्रेस को चुनावी दान में 147 करोड़ रुपए मिले हैं। यह राशि भाजपा को मिले चंदे का सिर्फ पांचवा हिस्सा ही है। भाजपा को साल 2018-19 में सबसे ज्यादा दान प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट द्वारा दिया गया। इसने भाजपा को 357 करोड़ की राशि चंदे में दी।

पिछले साल से अब तक देश के 16 राज्यों में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 12 चरणों में कुल 6,128 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं। इसमें से सबसे ज्यादा 1879 करोड़ रुपए के बॉन्ड मुंबई में बेचे गए हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा 4,917 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश हुए यानी भुनाए गए हैं। रिटायर्ड कमोडोर लोकेश बत्रा द्वारा दाखिल आरटीआई आवेदन के जवाब में यह जानकारी मिली है।

● **इन्द्र कुमार**

कॉर्पोरेट फंडिंग किसी खास फायदे के मकसद

ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट फंडिंग किसी खास फायदे के मकसद से की जाती है। जब कोई कंपनी किसी दल को चंदे के तौर पर धन मुहैया कराती है, तो इसके पीछे चुनाव बाद राजनीतिक और आर्थिक फायदा हासिल करने की नीयत होती है। लेकिन गौर करें कि जब चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा देने वालों का नाम किसी दल को पता नहीं चलेगा, तो यह कैसे मुमकिन है कि किसी व्यक्ति या कंपनी को सत्ताधारी दल कोई फायदा पहुंचा सकेगा? जबकि इसके उलट कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हाल ही में, चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया गया, उसमें से लगभग 95 फीसदी चंदा एक विशेष राजनीतिक दल के खाते में आया। लिहाजा, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि भले ही जनता इस बात से अंजान हो कि किस कंपनी ने किस दल को चंदा दिया है। लेकिन राजनीतिक दल अंदरूनी तौर पर इनके नामों से वाकिफ होते हैं।

दिल्ली का दांव

दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 8 फरवरी को यहां वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। पिछले दो विधानसभा चुनाव यहां आम आदमी पार्टी के पक्ष में एकतरफा या उसके और बीजेपी के बीच आमने-सामने के रहे हैं। इस बार कांग्रेस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर सकती है। सीएम अरविंद केजरीवाल के उभार के साथ दिल्ली की सियासत में अपेक्षाकृत युवा नेताओं का दबदबा बढ़ गया है। यहां की राजनीति पर प्रभाव रखने वाले पुराने नेताओं में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, मोटे तौर पर कहें तो लगभग सारे ही जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी में तकरीबन सारे युवा हैं।

कांग्रेस में अजय माकन के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद सुभाष चोपड़ा ने कमान संभाली है। बीजेपी से कांग्रेस में पहुंचे कीर्ति आजाद की भूमिका भी अहम हो सकती है। बीजेपी में डॉ. हर्षवर्धन और विजय गोयल सीनियर हैं, लेकिन कमान युवा पूर्वांचली नेता मनोज तिवारी के हाथ में है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की सक्रियता को भी गौर से देखा जा रहा है, जो दिल्ली की राजनीति में नए हैं। राज्यों के चुनाव में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती पर भारतीय राजनीति का केंद्र होने के कारण इन मुद्दों का असर यहां जरूर होगा। इस चुनाव में सीएए को लेकर जारी बहस और जामिया मिलिया व जेएनयू में हुई हिंसा की छाया पड़ने की संभावना है।

आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार के कामों के आधार पर वोट मांगने जा रही है, जिसे लेकर वह काफी आश्वस्त है। बीजेपी की दुविधा यह है कि पिछले कुछ असेंबली चुनावों में मोदी मैजिक नहीं चल पाया है। ऐसे में केजरीवाल सरकार के कार्यों में खोट दिखाकर वह बेहतर गवर्नेंस का दावा भी कर रही है। मुश्किल यह है कि उसके पास सुशासन का कोई ताजा मॉडल नहीं है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के हाथों खोई अपनी जमीन वापस पानी है। 2015 में आम आदमी पार्टी को रेकॉर्ड 54.34 फीसदी वोट मिले थे, जिनमें ज्यादातर कांग्रेस के थे। अगर बीजेपी को देखें तो उसके वोट कमोबेश ज्यों के त्यों रहे हैं।

2013 के चुनाव में उसने 31 सीटें जीती थीं और वोट मिले थे 33.07 फीसदी, जबकि 2015 में उसकी सीटें घटकर सिर्फ 3 रह गईं लेकिन वोट परसेंट 32.19 रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस ने अपना वोट शेयर सुधारा, वह आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। 2014 में कांग्रेस को केवल 15 पर्सेंट वोट मिले थे जबकि 2019 में उसका वोट शेयर 22.5 फीसदी पर आ गया। यह ट्रेंड जारी रहा तो आम आदमी पार्टी के लिए समस्या हो सकती है, हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का ट्रेंड एक सा नहीं होता। 2019 में 'आप' 18 प्रतिशत पर जबकि बीजेपी 57 पर्सेंट पर पहुंच गई। देखें, दिल्ली का वोटर किस मिजाज से वोट देता है।

मतदाताओं में अपनी पैठ और मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस नए तेवर और नए कलेवर के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। लाडली योजना, अनधिकृत कॉलोनी, पेंशन में बढ़ोतरी सहित दिल्ली में पूर्व की शीला दीक्षित सरकार के दौरान की योजनाओं का विस्तार कर नए कलेवर में जनता के बीच रखेगी। चुनावी घोषणा पत्र में पूर्व कांग्रेस सरकार की योजनाओं में बदलाव कर शामिल किया जाएगा। पार्टी नेताओं का दावा है कि यदि वह सत्ता में आते हैं तो दिल्लीवासियों को अधिक से अधिक राहत देने के लिए इन योजनाओं को लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार केंद्र के एनआरसी, सीएए और एनपीआर के मुद्दे को भी पार्टी विधानसभा चुनाव में भुनाएगी।

चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने से पहले कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को लेकर विपक्षियों पर निशाना साध रही है। अब तक हल्ला बोल रैलियों में कांग्रेस लगातार अनधिकृत कॉलोनियों का मुद्दा उठाती रही है। कांग्रेस सरकार ने 2012 में 600 से अधिक कॉलोनियों को नियमित करने की पहल की थी। अब नए तेवर के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। पार्टी न केवल कॉलोनियों के नियमितीकरण के दावे कर रही है, बल्कि पेंशन योजना को भी नए सिरे से लागू करने के लिए इसे बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिमाह करने का दावा किया है। शिक्षा में तयशुदा बजट से कम खर्च पर चिंता जताते हुए इसे बढ़ाने के अलावा लड़कियों के लिए दोबारा लाडली स्कीम को नए सिरे से लागू करने के लिए भी पार्टी ने खाका तकरीबन तैयार कर लिया है। दिल्ली सरकार पर जवाबी हमला बोलते हुए कांग्रेस ने पहले ही 600 यूनिट तक बिजली फ्री करने की घोषणा कर दी है।

● **अक्स ब्यूरो**

फिर राष्ट्रवाद और मोदी का सहारा

दिल्ली में दमदार चेहरे के अभाव में भाजपा को फिर से पीएम मोदी और राष्ट्रवाद के मुद्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। पार्टी की मुश्किल यह है कि जिन नेताओं को राज्यों में सीएम बना कर फ्री हैंड दिया, वह अपना दमदार व्यक्तित्व तैयार करने में नाकाम रहे। हरियाणा में मनोहर लाल, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और झारखंड में रघुवरदास अपने दम पर कोई कमाल नहीं दिखा पाए। दिल्ली में भी पार्टी के पास कोई सर्वमान्य कद्दावर नेता नहीं है। दिल्ली में भाजपा की जीत या हार आप और कांग्रेस के प्रदर्शन से तय होगी। पार्टी की दोनों प्रतिद्वंदियों के वोट बैंक (दलित-मुस्लिम-झुग्गी झोपड़ी) करीब करीब एक ही है। ऐसे में अगर आप और कांग्रेस के वोट बंटे तो इसका सीधा लाभ भाजपा को होगा। इसके इतर अगर इन वोटों का किसी एक दल के पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ, तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ेंगी। पिछले चुनाव में यह वोट बैंक सीधे आप की झोली में गया था। लोकसभा चुनाव में दलित-मुस्लिम और झुग्गी के मतदाताओं के वोट में बिखराव से भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। भाजपा की मुश्किल यह है कि वह लोकसभा में विपक्ष पर मिली जबर्दस्त बढ़त को बरकरार नहीं रख पा रही। लोकसभा चुनाव के मुकाबले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी के वोट प्रतिशत में काफी गिरावट दर्ज की गई। लोकसभा चुनाव के मुकाबले हरियाणा और झारखंड में पार्टी के वोट प्रतिशत में क्रमशः 22 फीसदी और 17 फीसदी की कमी आई। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हरियाणा की तरह दिल्ली में भी क्लीन स्वीप किया था। पार्टी को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 22.5 फीसदी, आप 18.1 फीसदी के मुकाबले 56 फीसदी वोट मिले थे।

क्या पटरी पर लौटेगी अर्थव्यवस्था?

एशिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भारत की मौजूदा विकास दर 4.5 फीसदी है जो छह साल में सबसे निचले स्तर पर है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था का जैसा हाल है उससे सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। वहीं अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखते हुए सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर पांच फीसदी तक बढ़ने का अनुमान जताया है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसकी विकास दर 6.8 फीसदी थी। इससे पहले आरबीआई ने भी देश की विकास दर के अपने अनुमान को घटाकर पांच फीसदी कर दिया था। विश्व बैंक ने इस पर मुहर लगा दिया है कि भारत की जीडीपी की विकास दर 5 फीसदी ही रहेगी।

उधर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 7 जनवरी को चालू वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया। बीते कई महीनों से अर्थव्यवस्था में जारी सुस्ती के चलते यह विकास दर पांच फीसदी तक पहुंचने को लेकर भी विशेषज्ञ बहुत सहमत नहीं हैं। अर्थव्यवस्था के विकास की दर लगातार नीचे गिर रही है। खाने-पीने की चीजें महंगी हो रही हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं और इसकी खपत कम हो रही है। बीते साल में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। लेकिन सरकार इसे नियंत्रित नहीं कर पा रही है। सरकार का कहना है कि चीजों की खपत कम हो रही है, लेकिन खपत कम होने की वजह क्या है और अगर यही हाल रहा तो क्या सरकार विकास दर के पांच फीसदी के अनुमानित आंकड़े को छू पाएगी?

भारत के लिए फिलहाल सुस्त अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और बड़ा वित्तीय घाटा चिंता के विषय हैं। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2020 में बजट पेश करेंगी तो उन्हें नई नीतियां बनाने या पुरानी नीतियों को वापस लाने में इन चीजों का ख्याल भी रखना होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह साल काफी चुनौती भरा रहा और इसका गहरा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखा। इस तिमाही में विकास दर 4.5 फीसदी तक गिर गई। ये गिरावट लगातार छठी तिमाही में और बाजार की उम्मीदों के उलट है। भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर छह साल में सबसे निचले स्तर पर है। निजी खपत और निर्यात के साथ निवेश पर भी बुरा असर पड़ा है। घरेलू खपत भी चिंता का विषय रही जिसका भारत की जीडीपी में हिस्सा 60 फीसदी है।

साल 2019 में सेंट्रल बैंक और आरबीआई ने पांच बार **ब्याज दरें कम की**, लेकिन इस असर का दिखना अब भी बाकी है। हालांकि सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं लेकिन जानकारों का मानना है कि ये पर्याप्त नहीं हैं। सुस्त अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में सरकार कई प्रयोगों के बावजूद स्थिति में कोई खास सुधार नहीं कर पाई है। महंगाई उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा है। जाहिर है जब क्रय शक्ति घटती है तो खपत भी घटती है और इसका **नकारात्मक** असर जीडीपी पर पड़ता है। महंगाई को तार्किक स्तर पर बनाए रखना और बीते छह साल के मुकाबले निम्न स्तर पर पहुंच चुकी 4.5 फीसदी जीडीपी को 7 या 8 फीसद के इर्द-गिर्द लाना साल 2020 में सरकार के लिए पहली चुनौती रहेगी।

गौरतलब है कि 5 टिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए 8 प्रतिशत जीडीपी की आवश्यकता है। सरकार ने अर्थव्यवस्था का जो भारी-भरकम स्वरूप बनाने का मन बनाया है मौजूदा जीडीपी को देखते हुए कह सकते हैं कि यह आसान राह नहीं है। अगर भारत को बदलाव की चुनौती का मुकाबला करना है तो केवल सामान्य विकास से काम नहीं चलेगा। इसके लिए बुनियादी बदलाव की जरूरत पड़ेगी जिसकी पहली आवश्यकता जीडीपी में बढ़ोतरी ही है। साल 2024 तक 5 डॉलर की अर्थव्यवस्था करने का इरादा कहीं कागजों तक न रह जाए इसके लिए कृषि, विनिर्माण, पूंजी, निवेश आदि को लेकर लंबी छलांग लगानी होगी। बीते समय में देशभर में **छोटी कंपनियां** कुछ अधिक ही प्रभावित हुई हैं और बड़ी कंपनियों में भी नौकरी के अवसर घटे हैं। इतना ही नहीं सरकारी नौकरियां भी समय के साथ सिमट रही हैं। बीते वर्ष बेरोजगारी दर 6.1 फीसद पर चली गई थी जो 45 साल में सबसे ज्यादा थी। नए वर्ष में इस आरोप से मुक्त होने के लिए सरकार को एड़ी-चोटी का जोर लगाना होगा। गौरतलब है कि साल 2027 तक भारत सर्वाधिक श्रम-बल वाला देश हो जाएगा और इसकी खपत के लिए बड़े नियोजन की दरकार होगी।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

राजकोषीय घाटा भी लक्ष्मण रेखा लांघ रहा

अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से कर संग्रह घटा है और चालू वित्त वर्ष में इसको सकल घरेलू उत्पाद के 3.4 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य है। राजकोषीय घाटा भी लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है। हालांकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य भी किसी चुनौती से कम नहीं। गौरतलब है कि बढ़ता राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करता है जिसके चलते ब्याज दरों के साथ महंगाई भी बढ़ती है। यही कारण है कि पिछली 5 समीक्षाओं में रिजर्व बैंक ने 5 बार रेपो रेट में कमी करते हुए बीते फरवरी से अब तक 1.35 फीसदी की कटौती कर चुका है। जिसके चलते बैंकों पर ब्याज दर कम करने का दबाव बना। इतना ही नहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कटौती की और भी संभावना है जो कहीं न कहीं इसका निचला स्तर होगा। आरबीआई की यह चिंता रही है कि आर्थिक सुशासन को कैसे पटरी पर दौड़ाया जाए। इसी के चलते वह लगातार रेपो दर में कटौती करता रहा।

माओवादी तय करतें हैं सरपंच

हाल ही में सम्पन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव के बाद राज्य में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है लेकिन यहां के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में 150 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका चुनाव माओवादी करते हैं। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी भी मात्र निर्विरोध चयन की औपचारिकता पूरी करते हैं। सरकार और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी इन पंचायतों पर ना तो कोई राजनीतिक दल और ना ही कोई आम ग्रामीण, सरपंच का चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाया है। यहां सरपंच कौन होगा इसका फैसला चुनाव से नहीं बल्कि स्थानीय माओवादी करते हैं। राज्य सरकार के आला अधिकारी भी मानते हैं इन ग्राम पंचायतों में वे माओवादियों द्वारा चुने हुए नामों पर सरकारी मुहर लगाकर मान्यता देने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिलों में स्थित इन ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार और प्रशासन आज तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई है। नक्सलियों के खौफ की वजह से इन गांवों में आधारभूत संरचनाओं का अभाव रहा है तथा मूलभूत नागरिक सुविधाएं भी पहुंच ही नहीं पाई हैं।

दरअसल अधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं इन 150 से भी अधिक ग्राम पंचायतों में उन्हें नक्सलियों द्वारा चुने गए नाम पर मुहर लगाकर औपचारिकता ही पूरी करनी होती है। नक्सिलयों के द्वारा सरपंच पद के लिए नामित व्यक्ति का विरोध कोई ग्रामीण भी नहीं करता है और सबंधित चुनाव अधिकारी भी औपचारिक रूप से निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर देते हैं। नाम जाहिर न करने की शर्त पर कुछ अधिकारियों ने दिप्रिंट को यह भी बताया कि माओवादियों द्वारा सरपंच चुने जाने वाली वाली ग्राम पंचायतों की संख्या 150 से काफी ज्यादा हो सकती है। इन अधिकारियों के अनुसार नक्सल प्रभावित चार जिलों में करीब 25-30 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में माओवादियों की अघोषित सरकार चलती है।

दंतेवाड़ा कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने यह भी माना कि प्रशासन की पहुंच अभी तक इन ग्राम पंचायतों तक नहीं हो पाई है। वर्मा आगे कहते हैं 'ऐसा नहीं है कि इन ग्राम पंचायतों में चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। लेकिन यहां एक ही नाम आपसी सहमति से चुना जाएगा और उसे निर्विरोध चयनित मान लिया जाएगा।' बीजापुर जिलाधिकारी के डी कुंजाम बताते हैं, 'सरपंच उम्मीदवार इन क्षेत्रों में 'उनसे' स्वाभाविक रूप से मदद मांगते जिसका कारण सर्वविदित है। फिर भी प्रशासन का पूरा प्रयास है कि ग्रामीणों को सुरक्षा के साथ-साथ अधिक से अधिक संख्या में चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के प्रति प्रोत्साहित किया जाए।' सुकमा जिलाधिकारी चंदन कुमार बताते हैं, 'उनके जिले की सभी 149 ग्राम पंचायतें वामपंथी हिंसा से ग्रसित हैं।'

28 जनवरी से शुरू हो रहे पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे। इस चुनाव में गांव वाले बढ़-चढ़कर भाग लें इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है। परंतु स्थानीय ग्रामीणों और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकारी प्रयास कामयाब नहीं हो सकते। आंकड़ों की बात करें तो दंतेवाड़ा जिले में करीब 20 से 25 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां माओवादी अपना सरपंच नियुक्त करेंगे, बीजापुर जिले में ऐसी पंचायतों की संख्या 25 से 30 के करीब है जबकि सुकमा में करीब 40, नारायणपुर में 20 से अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या है। चंदन कुमार इन ग्राम पंचायतों को लेकर कहते हैं, 'यदि आप पूछेंगे कि कितनी ग्राम पंचायत वामपंथी हिंसा से ग्रसित है तो मैं कहूंगा ऐसी एक भी पंचायत नहीं है जहां वामपंथी हिंसा का असर नहीं है, सुकमा जिले में करीब 30 से 40 ग्राम पंचायत हैं जहां आज तक प्रशासन अपनी पहुंच नहीं बना सकी है।'

नारायणपुर जिले में अकेले ओरछा ब्लॉक की 37 ग्राम पंचायतों में आधी से ज्यादा पंचायतें ऐसी हैं जहां सरपंच का फैसला माओवादी करेंगे। फिर भी जिलाधिकारी पदुम सिंह अल्मा बताते हैं कि जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को चुनाव में भाग लेने के लिए मनाने में काफी हद तक सफलता पाई है। परन्तु दिप्रिंट को जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह प्रयास कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि इन आति संवेदनशील ग्राम पंचायतों में ग्रामीण निरंतर माओवादी हिंसा के भय में जीते हैं और वे किसी भी हालत में उनके खिलाफ नहीं जा सकते।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

अभी तक जारी नहीं किया कोई फरमान

वैसे इन अति संवेदनशील या कहें नक्सलियों के आधिपत्य वाली ग्राम पंचायतों की जमीनी हकीकत सर्व विदित है, फिर भी इन चार जिलो में प्रशासनिक अधिकारी राहत की सांस इस बात से ले रहे हैं कि नक्सलियों ने 2020 के पंचायत चुनाव के खिलाफ अभी तक कोई फरमान जारी नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि आगे भी नक्सली चुनाव के बहिष्कार का कोई फरमान जारी न करें लेकिन उन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आना भी एक प्रकार से अच्छा है। नारायणपुर कलेक्टर कहते हैं 'हम इन पंचायतों में कई ग्रामीण मित्रों से लगातार संपर्क में है जिनसे नक्सलियों की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। इसके अतिरिक्त हमारे अधिकारी स्थानीय सरकारी कर्मचारियों जैसे हैंडपंप मकैनिक नर्स कृषि विकास था अधिकारी या फिर पंचायत सचिवों द्वारा भी जानकारी निरंतर प्राप्त करके रहते हैं अभी तक की जानकारी के अनुसार नक्सली पूरी तरह न्यूट्रल है।'

मौत का अस्पताल

राजस्थान का कोटा शहर कभी औद्योगिक नगरी के नाम से मशहूर था। उद्योगों के बंद होने के बाद यह शहर देश में कोचिंग संस्थानों का सबसे बड़ा हब बन गया। मगर पढ़ाई के तनाव में यहां बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों के लगातार आत्महत्या करने की घटनाओं ने इस शहर के चेहरे पर एक बदनुमा दाग लगा दिया था। हाईकोर्ट की सख्ती व सरकारी प्रयासों से कोटा में छात्रों के आत्महत्या करने की घटनाओं में काफी कमी आने से यहां लोगों ने राहत की सांस ली थी। मगर कोटा शहर के जेके लोन सरकारी अस्पताल में गत 36 दिनों में 111 बच्चों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इससे कोटा शहर एक बार फिर से देश भर में चर्चा का केन्द्र बना हुआ है। दिल दहला देने वाली इस घटना से राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार भी लोगों के निशाने पर आ गई है।

पिछले दिसम्बर महीने में कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजात शिशुओं के मरने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह अभी तक जारी है। नवजात शिशुओं की मौत रोक पाने में अस्पताल प्रशासन व राजस्थान सरकार नाकारा साबित हो रही है। ऊपर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कह कर कि 'प्रदेश के हर अस्पताल में हर दिन तीन-चार बच्चों की मौत होती रहती है। यह कोई नई बात नहीं है। पिछले 6 सालों के मुकाबले इस साल तो सबसे कम मौतें हुई हैं', लोगों को और अधिक नाराज कर दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा दिए गए ऐसे असंवेदनशील बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है।

इसी बीच राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांती व न्यायाधीश पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की खण्डपीठ ने कोटा सहित राज्य के सभी जिलों के अस्पताओं में नवजात बच्चों की मौत के कारणों की रिपोर्ट तलब करते हुए सरकारी अस्पतालों में सभी रिक्त व स्वीकृत पदों की जानकारी मांगी है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 1 दिसम्बर 2019 से लेकर 6 जनवरी 2020 तक मात्र 36 दिनों में 111 बच्चों की मौत हो चुकी है। कोटा के इसी अस्पताल में वर्ष 2019 में 963 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। कोटा के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिला जोधपुर के डॉक्टर सम्पूर्णानंद राजकीय मेडिकल कॉलेज में दिसम्बर माह में 146 बच्चों की मौत हो जाने की बात सामने आ रही है। जबकि गत दिसम्बर माह में ही बीकानेर के सरकारी पीबीएम अस्पताल में 162 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। इनमें 102 नवजात शिशु थे। इसी तरह दिसम्बर माह में बाड़मेर के सरकारी अस्पताल में 29 बच्चों की मृत्यु हुई है। वहीं गत वर्ष बाड़मेर जिले के सरकारी अस्पतालों में 202 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी।

नवजात बच्चों की मौत पर राजस्थान सरकार को घिरता देख कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे को दिल्ली तलब कर पूरी स्थिति की जानकारी ली। सोनिया गांधी ने राजस्थान में स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए उन्हें तत्काल जयपुर भेजा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे स्थिति का जायजा लेने अभी तक कोटा नहीं जा पाए हैं। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी घटना के एक माह बाद कोटा अस्पताल का जायजा लेने गए जहां उन्हें लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा।

प्रदेश में स्थिति बिगड़ती देख अंततः कांग्रेस आलाकमान को उपमुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को डेमेज कंट्रोल करने के लिए कोटा भेजना पड़ा। कोटा के हालात का जायजा लेने के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर अकेले नवजात शिशुओं की मौत की जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं। हमारी सरकार को बने हुए भी 13 माह हो गए हैं। प्रदेश में नवजात शिशुओं की मौत होने को हम हमारी सरकार की प्रशासनिक असफलता ही मानेंगे। हम इसे दुरुस्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कहीं कोई खामी तो रही होगी जिसके चलते इतने बच्चों को जान गंवानी पड़ी है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सचिन पायलट का बयान एक तरह से मुख्यमंत्री गहलोत व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की असफलता को ही उजागर करता है। कोटा में दिए गए सचिन पायलट के बयान के बाद विपक्षी दल सरकार पर और अधिक आक्रामक हो रहा है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

बचाव में अपने-अपने तर्क

राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने जेके लॉन अस्पताल में हुई बच्चों की मौत के मामले में अपने विभाग को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि बच्चों की मौत चिकित्सकों या मेडिकल स्टॉफ की लापरवाही या संक्रमण के कारण नहीं हुई है। वहीं सरकार की ओर से गठित कमेटी ने अपनी जांच में माना है कि बच्चों की मौत गंभीर रोगों के कारण हुई है। कोटा में बच्चों की मौत का मामला तूल पकड़ने के बाद सरकार हरकत में आई और अस्पताल के अधीक्षक को हटा दिया है। साथ ही हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कोटा में नवजात बच्चों की मौत पर सफाई देते हुए अस्पताल के अधीक्षक डॉ. एचएल मीणा का कहना था कि जांच के बाद हमने पाया है कि सभी मौतें सामान्य हैं। इसमें कोई लापरवाही नहीं हुई है। अस्पताल अधीक्षक के अनुसार उनके पास ज्यादातर मरीज कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बांरा जिलों से आते हैं। जिस वक्त वो अस्पताल लाए जाते हैं उनकी तबियत पहले से ही बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई होती है। बच्चों के मरने पर कोटा के जेके लोन अस्पताल के पीडियाट्रिक्स प्रमुख डॉ. एएल बैरवा ने राष्ट्रीय एनआईसीयू रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा है कि रिकॉर्ड के अनुसार 20 प्रतिशत शिशु मृत्यु स्वीकार्य हैं। वहीं कोटा में मृत्यु दर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यहां केवल 10 से 15 प्रतिशत बच्चों की मौत हुई। डॉ. एएल बैरवा के अनुसार ये चिंता का विषय इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस वक्त बच्चों को यहां लाया गया वो गंभीर स्थिति में थे।

चुनौतियां विकराल

उद्धव ठाकरे के सामने 2020 में चुनौतियां कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। ऊपर से तो सब ठीक ठाक है, लेकिन मंत्रियों में विभागों को लेकर झगड़ा होने लगा है। सीनियर मंत्री गर्मागर्म बहस के बाद मीटिंग छोड़ कर चले जा रहे हैं-और तो और शिवसेना कोटे से मंत्री बने एक नेता अब्दुल सत्तार ने तो इस्तीफा ही दे डाला है। उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार ने मंत्रियों के लिए बंगलों का बंटवारा तो खुशी खुशी कर लिया, लेकिन विभागों पर फंसा पेंच सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो मंत्री मनपंसद बंगले पाकर खुश हैं, वही मंत्रालयों के लिए जिद पर अड़े हुए हैं। गठबंधन की सरकार चलाना तो वैसे भी सत्ता की राजनीति के सबसे कठिन कामों में से एक है, लेकिन उद्धव ठाकरे के मामले में तो लगता है जैसे सरकार चलाने के लिए बना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सलाहकार कमेटी का भी असर नहीं हो रहा है।

उद्धव ठाकरे जब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे थे तो हर निगाह एक ही चेहरे को तलाश रही थी-लेकिन संजय राउत नजर नहीं आए। सरकार बनने से पहले और उसके बाद भी काफी देर तक संजय राउत, उद्धव ठाकरे की आंख और कान के साथ-साथ जुबान भी बने रहें, अब वो बात नहीं रही, ऐसा लगने लगा है। मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त गैरमौजूदगी अगर संजय राउत की नाराजगी की पहली झलक रही तो दूसरी झलक एक फेसबुक पोस्ट में देखी गई। वैसे वो पोस्ट थोड़ी देर झलक दिखाने के बाद गायब भी हो गई। संजय राउत ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था-हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आप को तीन भेंट दी हो-साथ, **समय और समर्पण...** किसी के लिए भी समझना आसान था। खबर आई थी कि संजय राउत अपने भाई सुनील राउत को मंत्री न बनाए जाने से काफी नाराज हैं-अब एक नई नाराजगी भी ब्रेकिंग न्यूज बनकर सामने आ चुकी है।

सबसे बड़ा मतभेद तो शिवसेना नेता सुभाष देसाई के घर पर गठबंधन के नेताओं की बैठक में देखी गई। बातों-बातों में ही विवाद इस कदर बढ़ गया कि एनसीपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता बीच में ही बैठक छोड़ कर चले गए। सब ठीक-ठाक ही लग रहा था कि तभी अशोक चव्हाण ने ग्रामीण विकास, सहकारिता और कृषि विभाग में से कोई एक कांग्रेस के हिस्से में दिए जाने की मांग रख दी। अजित पवार ने पिछली बैठक का हवाला देते हुए कहा कि तब पृथ्वीराज चव्हाण ने तो कुछ भी नहीं कहा और अब वो नई मांग पेश कर रहे हैं। अजित पवार यहां तक बोल गए कि कांग्रेस में किससे बात करें - कोई नेता ही नहीं है। ये सुनते ही अशोक चव्हाण भड़क गए, बोले - वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर उनकी बात को कैसे नकारा जा सकता है। पृथ्वीराज चव्हाण भी कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अजित पवार लहजा तो आक्रामक हो ही गया था, तैश में उठे और मीटिंग छोड़ कर चल दिए। फिर पीछे-पीछे एनसीपी के नेता भी चल दिए। अशोक चव्हाण ने भी ऐसा ही किया-लेकिन मामला जब तूल पकड़ने लगा तो अजित पवार ने सफाई में कहा कि अशोक चव्हाण से उनका कोई मतभेद न हुआ है न ही है।

अशोक चव्हाण ने मीटिंग में जो मांग रखी थी उसके पीछे कांग्रेस की दलील है कि उसके ज्यादातर विधायक ग्रामीण इलाकों से ही चुनकर आए हैं, इसलिए ग्रामीण विकास, सहकारिता और कृषि विभाग मिलने पर वे अपने क्षेत्र में काम कर सकेंगे। अभी की स्थिति ये है कि ग्रामीण विकास और सहकारिता विभाग पर एनसीपी के पास है और कृषि शिवसेना के पास। साथ ही, कांग्रेस चाहती है कि जहां पर कांग्रेस का जनाधार मजबूत है उन जिलों के प्रभारी उसके ही कोटे से बने मंत्री ही बनें। गठबंधन साथियों के बीच असहमति का ये एक और बड़ा मुद्दा है। 2019 में स्टेशन से निकल चुकी उद्धव ठाकरे सरकार की गाड़ी लगता है 2020 में आउटर सिग्नल पर जाकर रुक गई है। आगे तो तभी बढ़ेगी जब सिग्नल लाल से हरे रंग का हो जाए - और जब झंडी दिखाने वाले गार्ड की भूमिका निभा रहे किरदार एक से ज्यादा हों तो हाल क्या होगा - सब सामने ही है।

● **बिन्दु माथुर**

किसानों का हमदर्द बनने की होड़

देखा जाए तो किसानों के नाम पर ही महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर मुलाकातें होती रहीं। तब तो गवर्नर से भी मिलने देवेंद्र फडणवीस और आदित्य ठाकरे किसानों के नाम पर ही मिलने गए थे- और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनसपीपी नेता शरद पवार ने भी किसानों की समस्याओं के नाम पर ही मुलाकात की थी। बाद में पता चला मोदी और पवार की मुलाकात के दौरान भी कृषि मंत्रालय का जिक्र आया था। सुना गया कि पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए केंद्र में कृषि मंत्रालय की मांग की थी। दरअसल, शरद पवार भी पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं और महाराष्ट्र में किसानों की राजनीति के लिए विभाग की बड़ी अहमियत है। मगर, अफसोस की बात ये ही कि किसानों के नाम पर महज राजनीति होती आ रही है- किसानों की आत्महत्या के मामले नहीं रुक रहे हैं। यहां तक कि जब किसानों के नाम पर महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर थीं, किसानों की आत्महत्या नहीं थमी।

सियासी दुश्मन कौन?

प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश का तूफानी दौरा कर रही हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस लगातार उनके निशाने पर है। अब तक मायावती के बयानों से बचती रही प्रियंका गांधी ने पलटवार भी किया है। मायावती यूपी में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर लगातार हमलावर रही हैं, लेकिन काफी परहेज के बाद अब प्रियंका ने भी पलटकर चैलेंज कर दिया है। उन्नाव गैंग रेप के खिलाफ मायावती और अखिलेश यादव के साथ-साथ एक ही दिन सड़क पर उतरीं प्रियंका गांधी खुद को दिखाने की भी कोशिश कर रही हैं। फिलहाल तो वो लोगों को यही मैसेज देना चाहती हैं कि कांग्रेस दुख की घड़ी में उनके साथ है और उनकी बात सबके सामने लाने की पूरी कोशिश भी कर रही है। मायावती के बाद अखिलेश यादव ने भी अगर प्रियंका गांधी को टारगेट करने की कोशिश की तो मान कर चलना चाहिए, जवाब भी वैसा ही मिलेगा जैसा बीएसपी नेता को मिला है। सवाल ये है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दुश्मन किसे मानती हैं-योगी आदित्यनाथ को, मायावती को या फिर अखिलेश यादव को?

यूपी पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रियंका गांधी खुद को पीड़ितों के साथ खड़े होने का मैसेज दे रही हैं। यूपी में हुई हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी ने राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी है। बकौल प्रियंका गांधी, राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में बताया है कि पुलिस ने लोगों को किस तरह से पीटा है? कैसे बच्चों को जेल में डाला है? बेगुनाहों के साथ बर्बरता से पुलिस कैसे पेश आई है। जब पत्रकारों के बीच होती हैं तब भी प्रियंका गांधी लोगों की शिकायतों की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं। कहती हैं - पुलिस बेगुनाहों को परेशान कर रही है। उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तक नहीं दे रही है और जेल भेज दिए जाने की धमकी भी मिल रही है।

प्रियंका गांधी कांग्रेस को ऐसे वक्त रेस में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं जब वो सूबे में जैसे-तैसे सांसे गिन रही है। विधानसभा में सिर्फ सात विधायक बचे हैं और एक लोकसभा सांसद। राहुल गांधी की हार के बाद कांग्रेस अमेठी भी गंवा चुकी है। प्रियंका गांधी भी मुस्लिम समुदाय के साथ फिलहाल वैसे ही सपोर्ट में खड़ी दिखाने की कोशिश कर रही हैं जैसे राहुल गांधी एक दौर में दलितों के साथ। मायावती की प्रियंका गांधी से चिढ़ की वजह भी यही है। कांग्रेस के खिलाफ मायावती के ताजा बयान देखें तो वो दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के ही नाम लेती हैं - और कहती हैं कि अगर कांग्रेस ने लोगों पर ध्यान दिया होता तो बीएसपी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रियंका गांधी की सक्रियता भी यही बता रही है कि वो कांग्रेस का खोया हुआ वोट बैंक वापस दिलाना चाहती हैं।

2019 के आम चुनाव में पाया गया कि कांग्रेस को यूपी में मुस्लिम समुदाय से सिर्फ 14 फीसदी वोट मिले थे, जबकि 76 फीसदी सपा-बसपा गठबंधन के खाते में गया था। कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा फिक्र वाली बात तो ये रही कि बीजेपी ने 62 में से 36 सीटें उन इलाकों में जीती जहां 20 फीसदी मुस्लिम आबादी रहती है। आगे बढ़ने से पहले और वक्त रहते प्रियंका गांधी को ये तय कर लेना होगा कि कांग्रेस का वोट बैंक वापस किससे लेना है-भारतीय जनता पार्टी से, समाजावादी पार्टी से या फिर बहुजन समाज पार्टी से? तभी प्रियंका गांधी ये भी तय कर पाएंगी कि कांग्रेस का असली सियासी दुश्मन कौन है - योगी आदित्यनाथ, मायावती या फिर अखिलेश यादव?

प्रियंका गांधी यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ लोगों के हर गुस्से को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। चाहे वो सोनभद्र का नरसंहार हो या उन्नाव में **बलात्कार** की तमाम घटनाएं - या फिर नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। कानून और व्यवस्था के नाम पर बीजेपी सरकार को घेरने के साथ साथ प्रियंका गांधी भगवा रंग पर कांग्रेस का बदला नजरिया भी पेश करती हैं-आतंक से अहिंसा की ओर। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को चिट्ठी भी लिखी है। जहां कहीं भी कांग्रेस महासचिव को लगता है कि सरकार के खिलाफ लोगों की सहानुभूति बटोरी जा सकती है, वो फौरन पहुंच जाती हैं। लोगों से मिलती-जुलती हैं और फिर मीडिया के सामने आकर यूपी पुलिस की ज्यादती की कहानियां भी बताती हैं।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

कांग्रेस को होगा कितना फायदा

जो राजनीति प्रियंका गांधी फिलहाल कर रही हैं, राहुल गांधी भी ऐसे ही तूफानी दौरे किया करते थे। दलितों के घरों में राहुल गांधी के लंच और डिनर खूब सुर्खियां बटोरते रहे। फिर मायावती का बयान आता था- जब राहुल गांधी दलितों के घर से लौटकर दिल्ली जाते हैं तो एक विशेष प्रकार के साबुन से नहाते हैं। राहुल गांधी के तूफानी दौरों का असर यही हुआ कि धीरे-धीरे मायावती भी सत्ता से बाहर हो गईं और एक दिन अखिलेश यादव भी। सिर्फ यही नहीं, जब दोनों गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे तो भी नुकसान समाजवादी पार्टी और बीएसपी को ही हुआ - और फायदा तो कांग्रेस को भी नहीं मिला। फायदा मिला तो बीजेपी को जो बरसों के वनवास के बाद यूपी की सत्ता पर काबिज हो गई है। क्या प्रियंका गांधी को मालूम है कि उनकी हालिया राजनीतिक गतिविधियों का कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? आम चुनाव हुए कुछ ही दिन हुए हैं और यूपी में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने हैं-दो साल का वक्त काफी लंबा होता है, लेकिन लोकस्मृतियां उतनी लंबी नहीं होतीं। पब्लिक कम ही बातें याद रख पाती है, बाकी बातें बड़ी जल्दी भूल जाती है।

अबुझ नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के सर्वाधिक निराश करने वाले किरदारों में से एक बनकर उभरे हैं। कभी नए जमाने के प्रगतिशील और काम से मतलब रखने वाले नेता के रूप में प्रसिद्ध रहे नीतीश आज खुद का बेजान संस्करण नजर आते हैं- दिशाहीन, मित्रविहीन, अधीर तथा राजनीतिक विचारधारा और सामंजस्य से रहित। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार उन नेताओं में से एक हैं जिन पर कि 2020 में सबकी गहरी नजर रहेगी। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और उस पर नीतीश के जनता दल (यूनाइटेड) के रवैये ने भारत के तेज बदलावों वाले राजनीतिक परिदृश्य में उनकी अप्रासंगिकता और कमजोर होती पकड़ को एक बार फिर से उजागर किया है।

बिहार में भाजपा गठबंधन के साथ सत्तारूढ़ नीतीश की पार्टी जदयू ने संसद में एक अनुदार सीएए कानून का समर्थन किया। हालांकि इसको लेकर विवाद भी हुए क्योंकि कई पार्टी नेताओं ने इस कदम का खुला विरोध किया, और कुछ ने परोक्ष रूप से ऐसा किया। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री का भाजपा से संबंध कभी नरम तो कभी गरम वाला रहा हो, पर वे अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहे हैं और मुसलमानों को अपना वोट बैंक भी मानते रहे हैं। लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक को जदयू के समर्थन के बाद उनके राजनीतिक और वैचारिक रुझान को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है और ये पूछा जाने लगा है कि क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी के समक्ष घुटने टेक दिए हैं और इस तरह राजनीति के हाशिए पर धकेले जाने की बात मान ली है। अभी लोग उनकी बदली हुई प्राथमिकताओं को लेकर भ्रमित ही थे कि नीतीश ने एक बार फिर पलटी मारते हुए-शायद चिढ़े बैठे पार्टी नेताओं और मुस्लिम मतदाताओं को शांत करने के लिए- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अपने राज्य में लागू नहीं होने देने का ऐलान कर दिया।

दोस्तों और दुश्मनों की फेहरिस्त बदलते रहने से लेकर अपनी मूल विचारधारा से डगमगाते रहने तक-नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के शीर्ष पलटमार साबित हुए हैं। इस परिदृश्य पर गौर करें। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश ने 2002 के गोधरा दंगों में कथित भूमिका को लेकर मोदी के बिहार आने पर अघोषित रोक लगा रखी थी। और जब 2013 में मोदी को उसके अगले साल के चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो उन्होंने भाजपा से संबंध तोड़ लिया था। वैसे ये नहीं भूलें कि वे भाजपा के साथ 1996 में तब आए थे जब पार्टी की हिंदुत्व की नीति तथा सांप्रदायिक रुख और राजनीति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी।

नीतीश राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के लालू प्रसाद से अलग होने के कुछ ही वर्षों के बाद 2017 में फिर से एनडीए के पाले में लौट आए। लालू उनके पुराने समाजवादी सहयोगी रहे हैं जो अपनी तमाम खामियों के बावजूद हमेशा धर्मनिरपेक्षता पर अडिग रहे हैं। वास्तव में, नीतीश अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में कुछ समय के लिए केंद्रीय मंत्री भी रहे थे।

बिहार में विधानसभा चुनावों से पूर्व 2015 में जब नरेंद्र मोदी स्पष्ट 'खतरा' बन चुके थे, नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए दोस्त से दुश्मन बने लालू यादव से दोबारा हाथ मिला लिया। इस एकजुटता को 2013 में शुरू हुए उस दौर के संदर्भ में देखा गया जब नीतीश मोदी के खिलाफ आक्रामकता दिखा रहे थे।

बिहार के 2015 के चुनाव में महागठबंधन को बड़ी जीत मिली और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए, हालांकि उनका राजनीतिक कद पहले जैसा नहीं रह गया था। पर ये हमजोली भी अल्पकालिक ही रही, जोकि नीतीश की पहचान है। वर्ष 2017 के आधा बीतते-बीतते नीतीश मोदी से अपनी नफरत को भूल प्रेमकमल खिलाते हुए भाजपा के पाले में लौट आए। नीतीश कुमार जिस निरंतरता के साथ खास कर धुर विरोधियों के बीच पाला बदलते हैं, उसको देखते हुए हरियाणा की 'आया राम, गया राम' की व्यंग्योक्ति तक सहज लगती है। हालांकि नियमित पलटमारी का परिणाम ये हुआ है कि आज नीतीश पर किसी का भी भरोसा नहीं है, खास कर 'मित्र' नरेंद्र मोदी का तो बिल्कुल ही नहीं।

● **विनोद बक्सरी**

बार-बार बदलता रुख

ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार सिर्फ दोस्त और दुश्मन ही बदलते रहते हैं। विचारधाराओं को लेकर भी उनकी यही स्थिति है। वह धर्मनिरपेक्ष रहना चाहते हैं, फिर भी मुखर हिंदुत्व वाली एक पार्टी के साथ मित्रता करते हैं। उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए और इसके लिए 2006 में उन्होंने 1989 के भागलपुर सांप्रदायिक दंगा मामले को दोबारा खोलने का कदम तक उठाया था, पर इसके बावजूद उन्होंने संसद में संदिग्ध उद्देश्यों वाले नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) का समर्थन किया। असल में सीएबी का विरोध नहीं करने के नीतीश के रुख ने ही उनकी अनिश्चित और ढुलमुल राजनीति और विचारधारा को एक बार फिर उजागर करने का काम किया है। विधेयक का समर्थन करने के नीतीश के फैसले का जदयू के भीतर विरोध हुआ तथा प्रशांत किशोर और पवन वर्मा जैसे खुद उनके चुनिंदा नेताओं ने खुलकर उनकी आलोचना की।

विश्वयुद्ध की आहट तो नहीं?

वैश्विक स्तर पर नई मोर्चाबंदी की संभावना

बहरहाल, अमेरिका द्वारा सुलेमानी को मारे जाने के बाद आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर नई मोर्चाबंदी खुलकर सामने आ सकती है। अगर दुनिया एक और खाड़ी युद्ध की ओर आगे बढ़ती है तो यह भी तय है कि भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में तेल की सप्लाई बाधित होगी, जिससे पहले से ही भारी दबाव झेल रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है। इसे अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो तेल की आपूर्ति प्रभावित होने या कच्चे तेल के दामों में भारी वृद्धि होने से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमारी करीब सत्तर फीसदी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति पश्चिमी एशिया के खाड़ी देशों से ही होती है। पहले से ही मंदी की शिकार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह बेहद मुश्किल दौर होगा। अगर आने वाले दिनों में खाड़ी युद्ध के हालात उत्पन्न होते हैं तो वहां काम कर रहे भारतीयों को स्वदेश लौटना पड़ेगा और इससे वहां से भारत आने वाली अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा का नुकसान भी होगा। भारत को पश्चिम एशिया में कार्यरत 80-90 लाख भारतीयों के जरिए प्रतिवर्ष करीब 40 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

3 जनवरी की सुबह इराक में बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो कुछ हुआ, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने नए साल की शुरुआत के महज तीसरे ही दिन जिस प्रकार एक ही झटके में ड्रोन हवाई हमला करके ईरान के 62 वर्षीय शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला, उससे उन्होंने पूरी दुनिया को एकाएक एक और विश्वयुद्ध के मुहाने पर धकेल दिया है। हालांकि यह आने वाला समय ही बताएगा कि ईरान के रिवोल्यूनशरी गॉर्ड्स कॉर्प्स के शीर्ष कमांडर सुलेमानी को इस प्रकार मार दिए जाने के बाद पहले से ही बेहद खराब चल रहे ईरान और अमेरिका के और कटुतापूर्ण हुए संबंधों का क्या परिणाम सामने आएगा लेकिन जिस प्रकार ईरान द्वारा लाल झंडे लहराकर अमेरिका के इस हमले का बदला लेने की चेतावनियां दी जा रही हैं, उससे इतना तो तय है कि इसका खामियाजा सिर्फ इन दो देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा।

ईरानी चेतावनियों और उसके जवाब में अमेरिकी धमकियों को देखते हुए आज हर किसी के दिलोदिमाग में अब एक ही प्रश्न कौंध रहा है कि कहीं यह तीसरे 'विश्वयुद्ध' की आहट तो नहीं है? दरअसल एक तरफ जहां ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताते हुए तेल का समुद्री रास्ता बंद करने की चेतावनी दी है और कहा है कि वह वाशिंगटन से अपने शीर्ष कमांडर की हत्या का सही समय पर बदला लेगा तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने तेवर कड़े करते हुए बार-बार कह रहे हैं कि अगर ईरान ने उसके हितों पर कहीं भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो अमेरिकी सेनाएं ईरान के चुनिंदा 52 ठिकानों को निशाना बनाने से नहीं चूकेंगी। दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खोमैनी ने अमेरिका को जबरदस्त बदले और अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इस पूरे प्रकरण से समूची दुनिया एक और खाड़ी युद्ध की ओर आगे बढ़ती दिख रही है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हर तरफ सिर्फ तबाही का ही मंजर सामने आएगा क्योंकि आज के दौर में साधारण तरीकों से लड़े जाने वाले युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती बल्कि अगर युद्ध हुआ तो उसमें अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित हथियारों और परमाणु हथियारों का खुलकर इस्तेमाल होगा, जिनका प्रभाव दुनिया के अनेक हिस्सों में देखा जाएगा।

ईरान के खिलाफ अमेरिका के इस कदम के विरोध में रूस, चीन जैसी महाशक्तियां खुलकर आ गई हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी ट्रंप के इस कदम से खुश नहीं हैं। दूसरी ओर, ब्रिटेन ने तो अमेरिका का साथ देते हुए अपना एक युद्ध पोत खाड़ी की ओर रवाना भी कर दिया गया है। ऐसे में अमेरिका के समर्थकों और विरोधियों की खेमेबंदी कहीं ज्यादा खुलकर सामने लगी है। पर अब अमेरिका के लिए ईरान ही नहीं, इराक भी गले की फांस बन गया है। विदेशी फौज की मौजूदगी खत्म करने को लेकर इराकी संसद ने हाल में जो प्रस्ताव पास किया है, उससे भी अमेरिका की नींद उड़ गई है। बदले में अमेरिका ने इराक पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। इराक की बौखलाहट इसलिए ज्यादा है कि हमले में उसके भी शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए हैं और यह हमला उसकी जमीन पर हुआ है। इराक में अमेरिका का सबसे बड़ा सैनिक अड्डा है, जहां से अमेरिका ईरान और सीरिया के खिलाफ जंग की रणनीति बनाए हुए है। ऐसे में जोखिम भरे कदम उठाना अमेरिका के लिए भी कम महंगा नहीं पड़ने वाला।

सैन्य ताकत के मामले में ईरान भले ही अमेरिका के समक्ष कहीं टिकता नहीं दिखाई देता हो लेकिन इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान आज एक ऐसा देश बन चुका है, जिसके पास मिडल-ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइल पावर है। उसके पास ऐसी मिसाइलों, क्रूज और लड़ाकू विमानों का बड़ा जखीरा मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वह अपने सबसे बड़े दुश्मन सऊदी अरब सहित खाड़ी के कई अन्य देशों को भी बड़ी आसानी से अपना निशाना बनाने का सामर्थ्य रखता है। हालांकि यह अलग बात है कि अमेरिका के पास ऐसी-ऐसी तकनीकों वाले हथियारों का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है, जिससे वह अपनी ही जमीन से ईरान को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। तस्वीर का दूसरा पहलू देखें तो रूस अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है और चीन तथा उत्तरी कोरिया जैसे ताकतवर देश भी पहले से ही अमेरिका के खिलाफ हैं और वे भी इस लड़ाई में ईरान का साथ दे सकते हैं। ऐसे में अगर विश्व युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो ईरान को इन देशों का सहयोग मिलने से हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं।

● **अक्स ब्यूरो**

भक्ति का प्रवाह

रामचरित मानस हमारे जीवन में भक्ति का प्रवाह करता है। इससे हम परमात्मा की शरण का आश्रय प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। रामचरितमानस वह ग्रंथ है जिसमें कि मनुष्य के जीवन का कल्याण समाहित है। रामचरितमानस के पठन-पाठन से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और मानव के जीवन में जितने भी दोष हैं वह रामचरितमानस के पाठ करने व उसे जीवन में अपनाने से स्वत: ही दूर हो जाते हैं। विकराल कलिकाल में मानव के जीवन में अनेक समस्याओं का प्रादुर्भाव हो गया है, परमात्मा की कृपा यदि प्राप्त करना है तो इस कलयुग में रामचरितमानस का आश्रय लेना पड़ेगा।

गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस की रचना जगत कल्याण के लिए की थी और रामचरित मानस सम्मेलन के आयोजन से हमारे जीवन में परमात्मा की कृपा का प्रादुर्भाव स्वत: ही हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह परमात्मा की शरण का आश्रम ग्रहण करें और रामचरितमानस से स्वयं के संबंध को स्थापित करें। रामचरित मानस एक समग्र जीवन दर्शन है, जिसमें संसार की जितनी भी कठिनाइयां हैं उनका निदान हमें मिल जाता है।

रामचरितमानस भगवान राम का कलेवर है। यह गोस्वामी तुलसीदास के मानस में विराजमान भगवान राम का श्री विग्रह है। बालकांड राम का चरण, अयोध्याकांड राम का कटि, अरण्य कांड राम का उदर, किष्किंधा कांड राम का हृदय, सुंदर कांड राम का गर्दन, लंका कांड राम का मुखारविंद एवं उत्तर कांड राम का मस्तिष्क है। बाल कांड में सात, किष्किंधा कांड में दो एवं बाकी पांच कांडों में तीन श्लोक हैं।

बालकांड के सातों श्लोकों में सातों कांडों की कथा छिपी हुई है। तुलसीदास ने विद्वत्ता के लिए नहीं अपने सुख के लिए रामचरित मानस की रचना की है। तुलसीदास ने गणेश, शक्ति, विष्णु, शंकर, सूर्य ये पांच देवों की वंदना की है। गुरु की वंदना के बाद सत्संग की वंदना तुलसीदास करते हैं। वाल्मीकि, नारद, अगस्त्य मुनि आदि सत्संग से ही सुधरे और प्रसिद्ध हुए।

शठ भी सत्संग से सुधरता हैं। मणि की तरह सत्संग है। सांप के सिर में मणि रहती है फिर भी उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह सत्संग करनेवालों को कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। रामचरितमानस मणियों से भरा है, जो एक रामचरित मानस का पाठ करता है, वह जीवन भर उसी का हो जाता है।

किसी भी काम में सफलता के लिए जरूरी है आत्मविश्वास। इसके बिना किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिल सकती और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रीरामचरित मानस का पांचवां अध्याय सुंदरकांड सफलता और शांति सबसे बड़ा उदाहरण है। वानरों के सामने एक असंभव सी दिखने वाली चुनौती थी। सौ योजन लंबा समुद्र लांघकर लंका पहुंचने की। जब वानरों के दल में समुद्र लांघने के बात आई तो सबसे पहले जामवंत ने असमर्थता जाहिर की। फिर अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं, लेकिन समुद्र पार करके फिर लौट पाऊंगा इसमें संदेह है। अंगद ने खुद की क्षमता और प्रतिभा पर ही संदेह जताया। ये आत्म विश्वास की कमी का संकेत है।

जामवंत ने हनुमान को इसके लिए प्रेरित किया। हनुमान को अपनी शक्तियों की याद आ गईं और उन्होंने अपने शरीर को पहाड़ जैसा बड़ा बना लिया। आत्म विश्वास से भरकर वे बोले कि अभी एक ही छलांग में समुद्र लांघकर, लंका उजाड़ देता हूं और रावण सहित सारे राक्षसों को मारकर सीता को ले आता हूं। अपनी शक्ति पर इतना विश्वास था हनुमान को। जामवंत ने कहा नहीं, आप सिर्फ सीता माता का पता लगाकर लौट आइए। हमारा यही काम है। फिर प्रभु राम खुद रावण का संहार करेंगे। हनुमान समुद्र लांघने के लिए निकल गए। सुरसा और सिंहिका नाम की राक्षसियों ने रास्ता रोका भी, लेकिन उनका आत्म विश्वास कम नहीं हुआ।

हम जब भी किसी काम पर निकलते हैं तो अक्सर मन विचारों से भरा होता है। आशंकाएं, कुशंकाएं और भय भी पीछे-पीछे चलते हैं। हम अधिकतर मौकों पर अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त नहीं होते। जैसे ही परिस्थिति बदलती है हमारा विचार बदल जाता है। ये काम में असफलता की निशानी है। अगर हम इन स्थितियों से गुजरते हैं तो साफ है कि हमारे मन में आत्मविश्वास की कमी है। सफलता के लिए सबसे जरूरी है आत्म विश्वास। जब तक हम खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे, हमारे प्रयास कभी सौ फीसदी नहीं होंगे।

● ओम

व्यथा सुनाने आयी हूँ

ओढ़ निराशा का आंचल जो,
क्रंदन को मजबूर हुई।
विवश उसी भारत माता की,
व्यथा सुनाने आयी हूं।
छंद लिखें कितने कवियों ने,
अधर, नयन, मुख, गालों पर।
रुदन नहीं क्यों लिख पाए वो,
रिसे पांव के छालों पर।
मौन हुए भारत के जन भी,
निर्धन की निर्धनता पर।
दुबके रहे घरों के भीतर,
झांके नहीं विवशता पर।
मैं अबोल मां के जायों की,
पीड़ा गाने आई हूं।
विवश उसी भारत माता की,
व्यथा सुनाने आई हूं।
अफरा-तफरी मची हुई है,
और अभी हां और मिले।
शानों शौकत, गाड़ी, बंगला,
धन दौलत पुरजोर मिले।
दिन ढलते ही जा मदिरालय,
रूप रसों का पान करें।
घुंघरू, ठुमकों में रम कर वो,
यौवन का गुणगान करें।
असली सूरत उनकी जन-जन,
को दिखलाने आई हूं।।
विवश उसी भारत माता की,
व्यथा सुनाने आई हूं।
रिश्वतखोरी, सीनाजोरी,
ये सब बातें आम हुई।
मजहब चला बैर के रस्ते,
अच्छाई नाकाम हुई।
दुनियां भले चांद पर पहुंची,
शिक्षा ठंडे बस्ते में।
महंगाई ने रोटी छीनी,
रक्त बहा है सस्ते में।
कितना और अभी सोओगे,
जगो जगाने आई हूं।
विवश उसी भारत माता की,
व्यथा सुनाने आई हूं।

— रीना गोयल

जीवन-चाहत

जीवन सिंह घर के बाहर किसी बुरी आशंका में खड़ा भयभीत था। प्रेरणा का आज नतीज़ा आना था, कुछ बुरा न होवे, अभी तक घर नहीं आई। वाहर हालात भी ठीक नहीं रव सुख करें। उसी समय एक मोटरसाइकिल से खुशी से कूदती प्रेरणा पापा से लिपट गई। प्रेरणा- 'पापा, मैं क्लास में प्रथम आई और अब आपकी बेटी बाहरवीं पास हो गई। मेरी बस निकल गई थी। मुझे ये मेरा सहपाठी नमित गांव छोड़ने आया। ये हर मुश्किल में मेरी पूरी मदद करता है।' नमित को दोनों चाय पिलने के लिए अंदर ले गए। जीवन सिंह को बातों में बेटी की खुशी और बातचीत ढंग से दोनों में गहरी दोस्ती की आशंका हुई। जीवन सिंह नमित को, 'पिता जी क्या करते हैं, परिवार में कौन-कौन हैं?' पूछने लगे।

नमित, 'माता-पिता दोनों दमे से बीमार रहते हैं। बहन का तो विवाह कर दिया, हमारी जमीन दो किल्ले है। बस उसी में गुजारा चलता है।'

नमित के जाने के बाद पिता जीवन सिंह बोले, 'बेटी प्रेरणा, मैने तेरे लिए एक लड़का देख लिया साथ वाले गांव में है और बीस किल्ले जमीन का मालिक है। बेटा, नौकरी भी न हो जमीन तो मुश्किल वक्त में सहारा होती है। अब तेरे सहपाठी की दो किल्ले जमीन में क्या गुजारा होता होगा, मुश्किलों में रहते होगे।'

प्रेरणा, 'पापा, ये आप क्या कह रहे हो? मैं उसको पसंद करती हूं। मुझे लगता है कि उसके साथ रहकर मैं खुश रहूंगी बाकी आपकी मर्जी जो चाहो करो।'

जीवन सिंह बेटी का रिश्ता दूसरे गांव पक्का कर जब वापिस आ रहा होता है तो उसको एक जानकार बेली मिल जाता है जो बताता है कि 'ये लड़का तो बहुत शराबी और झगडालू है। यहां बेटी ना देना, किस्मत को रोयेगी।' आखिर पिता की आंखे खुल जाती हैं। वो बेटी को बोलता है, 'अभी नमित के घर जाकर तेरा रिश्ता पक्का करके आता हूं।' और वो बेटी मन की जीवन चाहत ढूंढता है।

— रेखा मोहन

सॉरी

लता का छः वर्षीय बेटा अपनी छोटी बहन से एक रोटी ज्यादा खाने की जिद करने लगा इसपर लता आग बबूला हो गई । लता के हरकतों को देखकर उसकी सहेली बोली- 'लड़का तो लड़का है यार इस तरह नहीं डांटना चाहिए। एक रोटी ज्यादा हो गई तो क्या हुआ बेटी को इसकी आदत डालनी चाहिए, सहेली की बातों को सुनकर लता मुस्कुरा पड़ी-' यही तो हमसे गलती हो जाती है सोना, लड़के को छूट देकर उसकी मनमर्जी करने देते हैं और लड़की के पैरों में जंजीर डाल देते हैं। बात सिर्फ एक रोटी की नहीं है एक लड़की की बेबसी, चुप रहने, लोगों की ताने सुनने की है... अगर लड़की भी अपने हक की जिंदगी जीने लगेगी तब गाड़ी सही पटरी पर चलेगी। लड़के को भी अपनी जिम्मेदारी और सीमाओं का एहसास होना बहुत जरूरी है। जमाना बदल रहा है। अब हमें (मांओं को) भी अपनी सोच बदलनी होगी। कब तक बेटी को कमजोर बनाते रहेंगे, कब तक उनके पंख काटते रहेंगे।

अपनी सहेली की ऐसी बातें सुनकर सोना को अपनी भूल का एहसास हुआ वह अपने बेटी की गलती ना होते हुए भी दो तमाचा जड़कर आई थी। वह सीधे घर की ओर दौड़ी आखिर बेटी को 'सॉरी' जो बोलना था।

— भानुप्रताप कुंजाम 'अंशु'

जेएनयू में विवाद करने वालों को 4-4 झापड़ लगाने चाहिएः कंगना

जेएनयू विवाद को अभिनेत्री कंगना रनोट ने कॉलेज गैंगवार बताया है। उन्होंने सलाह दी है कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की बजाय इससे जुड़े लोगों को हिरासत में लेना चाहिए और 4-4 झापड़ रशीद करने चाहिए। कंगना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पंगा के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इसी सिलसिले में वे एक इंटरव्यू में बात कर रही थीं।

कंगना ने जेएनयू विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जेएनयू में स्टूडेंटस पर हुए हमले की छानबीन चल रही है। मैंने इस मुद्दे में यही देखा कि वहां पर दो तरह के लोग हैं। एक एबीवीपी वाले और दूसरे जेएनयू वाले। ये दो तरह के यूनियन हैं। कॉलेजों में गैंगवार होना आम बात है। जब मैं चंडीगढ़ में पढ़ रही थी और जिस गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, उसके पास ही एक ब्वॉयज हॉस्टल भी था। वहां यह स्थिति थी कि खुल्लम-खुल्ला मर्डर तक हो जाते थे। एक बार जिस लड़के का मर्डर होने वाला था, वह हमारे होस्टल गेट के अंदर कूद गया। उसे हमारे मैनेजर ने बचाया था।

गैंगवार में दोनों ओर के लोग घायल होते हैं

कंगना आगे कहती हैं, मेरा मानना है कि इस तरह की गैंगवार में दोनों ओर के लोग घायल होते हैं। इसे चलाने वाले बहुत ही आक्रामक होते हैं। क्या यह राष्ट्रीय मुद्दा बनने के लायक है? बिल्कुल नहीं। इस तरह के लोगों पुलिस को हिरासत में लेकर चार-चार झापड़ लगाने चाहिए, ताकि उनकी सारी हेकड़ी निकल जाए। हर गली, मोहल्ले, कॉलेज में इस तरह के गुंडे मिल जाएंगे। इसलिए इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं।

फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग जलते हैं भूषण कुमार सेः अनिल कपूर

मुंबई में टी सीरीज, भूषण कुमार के प्रॉडक्शन में तैयार अनिल कपूर, दिशा पाटनी, आदित्य रॉय कपूर और कुणाल खेमू स्टारर फिल्म मलंग का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस खास मौके पर अनिल कपूर ने मलंग से जुड़ने की अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए बोले कि प्रड्यूसर भूषण कुमार की फिल्मों के हिट होने से काफी लोग जलते भी हैं, जबकि भूषण इस समय बॉलीवुड में रीढ़ की हड्डी बन कर काम कर रहे हैं। अनिल बताते हैं, फिल्म मलंग की मेरी जर्नी की शुरुआत लव रंजन के फोन कॉल के साथ शुरू हुई, लव ने मुझे फोन कर कहा कि वह मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाना चाहते हैं, जिसे मोहित सूरी डायरेक्ट करेंगे। मोहित के साथ पहले भी मिल चुका हूं, लेकिन साथ काम करने का अवसर नहीं मिला। स्क्रिप्ट सुनकर मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था, मोहित सूरी टाइप की स्क्रिप्ट थी।

इस वक्त देश 2 हिस्सों में बंटा हुआ हैः अजय देवगन

कई फिल्म पंडितों का मानना है कि नागरिकता संशोधन कानून की वजह से बीते काफी दिनों और हफ्तों से देश का जो माहौल है, व्ह फिल्म बिजनस के लिए ठीक नहीं है। इस माहौल की वजह से हाल ही में रिलीज़ हुई सलमान खान की फिल्म दबंग 3 को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब अगले हफ्ते यानी 10 जनवरी को 2 बड़ी फिल्में रिलीज़ के लिए तैयार हैं। अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान स्टारर फिल्म तानाजी और दीपिका पादुकोण की छपाक एक साथ रिलीज़ हो रही हैं। 2 बड़ी फिल्में, ऊपर से देश का बंटा हुआ माहौल। बीती रात जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा की निंदा पूरा देश कर रहा है, इस हिंसा के बाद दिल्ली और उत्तर भारत का माहौल ठीक नहीं है। ऐसे में ठीक 4 दिन बाद तानाजी और छपाक रिलीज़ के लिए तैयार हैं। आधा देश अलग बातें कर रहा है, आधा देश अलग तरह की बातें कर रहा है।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 15 जनवरी 2020 को साल 2019 के लिए आईसीसी पुरस्कारों की घोषणा की। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान (सीमित ओवरों के फॉर्मेट) रोहित शर्मा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है। वहीं कोहली को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड देने का ऐलान किया। पिछले साल इंग्लैंड में हुए आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान विराट कोहली ने मैदान पर बैठे लोगों खासकर भारतीय दर्शकों से स्टीव स्मिथ की हूटिंग करने की बजाय उनकी हौसलाअफजाई करने की मांग की थी। बता दें कि स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर ने बैन खत्म होने के बाद वर्ल्ड कप से वनडे क्रिकेट में वापसी की थी। शुरू-शुरू में वे जब भी मैदान पर उतरते फैंस उनकी हूटिंग करने लगते। भारत के खिलाफ मैच में भी स्मिथ के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था, तब विराट बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट को यह सब नागवार गुजरा और उन्होंने बल्लेबाजी रोककर दर्शकों से स्मिथ हौसलाअफजाई करने को कहा।

वहीं, पिछले साल रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन की बात करें तो यह काफी शानदार रहा था। उन्होंने किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 5 शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे थे। ओवरऑल उन्होंने पिछले साल कुल 7 वनडे शतक लगाए थे। हालांकि, आईसीसी ने साल के सबसे बड़े पुरस्कार इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को चुना है। साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाती है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। भारत के उभरते हुए तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने टी-20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ऑस्ट्रेलिया के मारनस लबस्सचगने को इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। वहीं स्कॉटलैंड के काइल कोएत्जर एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी ने पुरस्कार जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं हैं।

उधर, बीसीसीआई के सालाना अवॉर्ड्स समारोह का आयोजन 12 जनवरी को मुंबई में हुआ। इसमें एक क्रिकेट संघ सहित कुल 25 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस क्रम में भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ियों में के श्रीकांत और महिला खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा का तो सम्मान हुआ ही, साथ ही ओपनर मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा और फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को भी सम्मानित किया गया। बुमराह को पॉली उमरीगर अवॉर्ड के अलावा दिलीप सरदेसाई अवॉर्ड भी दिया गया।

रोहित शर्मा सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर

बुमराह को पॉली उमरीगर अवॉर्ड

बुमराह को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर (मेल) और पूनम यादव को इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर (फीमेल) चुना गया। दुनिया के नंबर एक वनडे गेंदबाज ने जनवरी 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। वे उसी समय से जबरदस्त फॉर्म में थे और 12 मैचों में 19.24 की औसत से 62 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने इस छोटे से टेस्ट करियर में हैट्रिक भी ली है। वहीं 15 साल की शेफाली वर्मा बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यूटेंट और बेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेटर जूनियर का पुरस्कार हासिल करने में सफल रही। वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने और सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए स्मृति मंधाना और झूलन गोस्वामी को भी पुरस्कृत किया गया।

लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड्स की श्रेणी में श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र सहित पुरस्कार राशि स्वरूप 25-25 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। पॉली उमरीगर अवॉर्ड के लिए बुमराह और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर (वुमेन) पूनम यादव को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र सहित 15-15 लाख रुपए की राशि बीसीसीआई ने सम्मानित करते हुए प्रदान की। पूर्व क्रिकेटर कृष्णमचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा।

पुरुष वर्ग में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड: कृष्णमाचारी श्रीकांत, बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड: दिलीप दोषी, पाली उमरीगर अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर: जसप्रीत बुमराह, बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू: मयंक अग्रवाल, दिलीप सरदेसाई अवार्ड (टेस्ट में सबसे ज्यादा रन) : चेतेश्वर पुजारा , दिलीप सरदेसाई अवार्ड (टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट) : जसप्रीत बुमराह।

महिला वर्ग में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार: अंजुम चोपड़ा, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर: पूनम यादव, बेस्ट विमेन क्रिकेटर (जूनियर डोमेस्टिक): शेफाली वर्मा, बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू: शेफाली वर्मा, बेस्ट विमेन क्रिकेटर (सीनियर डोमेस्टिक) : दीप्ती शर्मा, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज : स्मृति मंधाना(वनडे में सबसे ज्यादा रन), सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज: झूलन गोस्वामी (वनडे में सबसे ज्यादा विकेट)।

अन्य पुरस्कारों में बेस्ट अंपायर (डोमेस्टिक) वीरेंदर शर्मा, घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: विदर्भ क्रिकेट संघ, रणजी ट्रॉफी में बेस्ट ऑलराउंडर: शिवम दुबे (मुंबई), सीमित ओवरों की क्रिकेट में बेस्ट ऑलराउंडर : नीतीश राणा (दिल्ली), माधव राव सिंधिया अवार्ड: (रणजी में सबसे ज्यादा रन): मिलिंद कुमार, माधव राव सिंधिया अवार्ड: (रणजी में सबसे ज्यादा विकेट): आशुतोष अमन, एमए चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर 23 में सबसे ज्यादा रन-सीके नायडू ट्रॉफी) मनन हिंगराज, एमए चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर 23 में सबसे ज्यादा विकेट-सीके नायडू ट्रॉफी) सिडक सिंह, एमए चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर 19 में सबसे ज्यादा रन-कूच विहार ट्रॉफी) वत्सल गोविंग, एमए चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर 19 में सबसे ज्यादा विकेट-कूच विहार ट्रॉफी) अपूर्व आनंद।

● आशीष नेम

मैं और कीड़ा

कहते हैं मनुष्य के दिमाग में एक कीड़ा होता है, जो समय-बेसमय पर उसे काटता रहता है। उस दिन कीड़े ने मुझे काटा और पूछा-क्यों रे मानव खोपड़ी, ये मिलावट क्या होती है? तू इस पर विश्वास करता है?

मैंने कहा-भैया मेरे, मिलावट पर विश्वास न करना भगवान पर अविश्वास करने के समान है। बिना मिलावट के यह संसार निःसार है। चल ही नहीं सकता।

पढ़ा-लिखा आदमी होकर कैसी मूर्खों जैसी बातें करता है? अब कीड़े ने जरा जोर से दांत गड़ाए। मैंने कहा-भैया, आजकल तो मिलावट का ही युग हैं। वह चाय पत्ती, चाय पत्ती नहीं, जिसमें घोड़े की लीद न हो। वह अनाज क्या जिसमें कंकड़ न हो। वह घी क्या, जिसमें डालडा न हो। अरे भाया, शुद्ध दूध तो आजकल गाय-भैंसे भी नहीं देतीं। संगीत, संगीत नहीं रहा। लक्ष्मी-प्यारे हो गया। नदीम-श्रवण हो गया। कुत्ता भी अब कुत्ता न रहा। अल्सेसियन हो गया, डॉबरमेन हो गया और बुलडाग हो गया। मिलावट देवी तो यहां तक पहुंच गई कि हमारी सरकार भी बड़ी मुश्किल से शुद्ध हो पाई। वरन कभी अठारह दलों का तो कभी तेईस दलों का कॉकटेल हो गई थी। एक ही घूंट में रम का मजा भी देती है और देशी का भी।

कीड़ा मेरी बात मानने को कतई तैयार न था। कीड़ा जो था। उसे तो मेरी खोपड़ी खाने की आदत पड़ चुकी थी। तुनककर बोला-मैं नहीं मानता इस मिलावट-विलावट को। तेरी खोपड़ी में देख, क्या शुद्ध साहित्यिक गूदा भरा हुआ हैं।

मैंने कहा-दादा, ये शुद्ध खोपड़ीवाला दिमाग भी मिलावटी हैं। सारी मानव काया ही मिलावट की देन है। कीड़े ने जोर से काटा। वह मानने को तैयार ही नहीं था कि किसी मिलावटी माल पर पल रहा है।

मैंने कहा-बंधु, तुझे साहित्यिक खोपड़ी खाने का तो शौक है, पर साहित्य का जरा भी ज्ञान नहीं! अरे कबीर बाबा तो ये पांच तार का तंबूरा बजाते-बजाते अल्लाह को प्यारे हो गए और तुलसीबाबा ने भी डंके की चोट पर ऐलान किया था- क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पंचतत्व मिलि बना शरीरा।। अब बता इस देश में किसमें दम है जो इन दो दादाओं की बात को काट सके?

कीड़ा इतनी आसानी से हार मानने वाला न था। कीड़ा जो ठहरा। बोला-रे पगले! तू ठहरा नए जमाने का पढ़ा-लिखा आदमी। तैने जरा भी दिमाग नहीं। इन बूढ़ों की बातों को गांठ बांधकर बैठ गया। तेरे से अच्छा तो मैं हूँ। कम-से-कम इन दकियानूसी बातों पर तो विश्वास नहीं करता। सच ही तो है जितना इस देश को अनपढ़-गंवारों से खतरा नहीं है, उससे ज्यादा खतरा इसे तुम जैसे पढ़े-लिखों से है। सच में अब कीड़ा मेरे अहम को चुनौती देने लगा था। मैंने कहा-मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूं। कीड़े को लगा अब मैं फंसा उसके जाल में। वह बोला-ठीक है, दम है तो करो सिद्ध।

मैं शुरू हो गया। हाथ को आरसी क्या, और पढ़े-लिखे का फारसी क्या? मैंने अंगुली से शरीर को थोड़ा-सा खुरचा तो मिट्टी निकली। कीड़ा बोला-हूंऽ-हूंऽ। मैंने कहा-देख भैये, ये रहा पहला भूत। और तूने समय-समय पर इस शरीर से हवा और पानी निकलते देखा है जो आसपास के वातावरण को प्रदूषित करता है। वह बोला-ठीक है, मान लिया। अब बता, तेरी बॉडी में आकाश कहां है?

मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। कीड़े को लगा लोहा गरम है। उसने तुरंत प्रहार किया-खा गए गच्चा। मैं बोला-नहीं बच्चा। देख तूने कभी-कभी मेरे पेट से कुछ गुड़गुड़ाने की आवाज़ सुनी है, बादलों के गरजने टाईप। अब भैया, बादल तो धरती या पानी पर होते नहीं, आकाश में ही छाए रहते हैं। बस मान ले कि मेरे भीतर कहीं आकाश भी हैं।

कीड़े ने आखरी दांव मारा-अच्छा माना। अब आदमी में आग कहां से निकालेगा? एक पल को लगा कि मैं भी कीड़े के जाल में फंसा किंतु तुरंत मेरी चेतना जागी-है-है, आग भी है, इस शरीर में। बल्कि आग ही आग है। अरे जब पेट खाली होता है तो भूख की आग लगती है। किसी नवयौवना को देखो तो काम-वासना की ज्वाला दहकती है या नहीं? दादा, जब मैं किसी को अपने से आगे से बढ़ता हुआ देखता हूं, किसी का फायदा होते देखता हूं, किसी को अपने से ज्यादा प्रतिभावान पाता हूं और किसी को अपने से अधिक ज्ञानवान और धनवान देखता हूं तो, एक अजीब-सी जलन होती है, तन-बदन में आग-सी लग जाती है। और जानते हो उस समय लगता है इस आग के सामने संसार की सारी आग व्यर्थ हैं-क्या दावानल, क्या बड़वानल और क्या जठरानल? सब इनके आगे ठंडी महसूस होती हैं। मेरा सारी शरीर धधक उठता है। यही है पांचवां महाभूत-आग।

अब कीड़े के पास कोई तीर न बचा था। वह शांत हो गया। मेरे तर्कों के कारण वह भी सुलग रहा था-ईर्ष्या की आग में। जिसकी आंच मैं महसूस कर रहा था।

● **शरद सुनेरी**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®

ADITYA BIRLA
UltraTech

UltraTech
CEMENT
The Engineer's Choice

BECAUSE YOUR REPUTATION IS INVALUABLE
BUILD IT WITH INDIA'S NO.1 CEMENT

Consistent Quality | Pan-India Presence

Statue of Unity - Gujarat

Airport T2 - Mumbai

Metro Project - Hyderabad

Eastern Peripheral Expressway - Delhi NCR

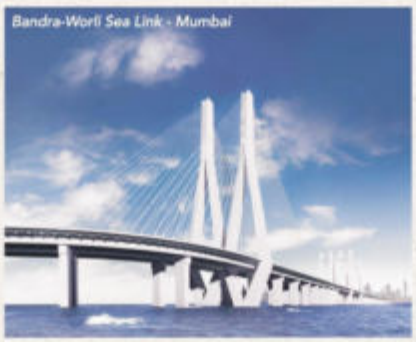
Bandra-Worli Sea Link - Mumbai

High-rise Tower

Call 1800 425 2525 for details on our wide range of products.

www.ultratechcement.com facebook.com/ultratechcementlimited twitter.com/ultratechcement